

Saturday, June 25, 1977
Asadha 4, 1899 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Series)

Vol. III

[June 23 to July 4, 1977/Asadha 2 to 13, 1899 (Saka)]



Second Session, 1977/1899 (Saka)

(Vol. III contains Nos. 11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

CONTENTS

No. 13.—Saturday, June 25, 1977/Asadha 4, 1899 (Saka)

COLUMNS

Papers Laid on the Table	I
Yoga Undertakings (Taking over of Management) Bill—	
Motion to consider—	
Shri Raj Narain	1—II
Clauses 2 to 16 and 1	II
Motion to pass—	
Shri Raj Narain	II
Demands for Grants, 1977-78—	
Ministry of Commerce and Ministry of Civil Supplies and Cooperation	II—146
Shri T. A. Pai	14—29
Prof. R. K. Amin	29—36
Chaudhury Brahm Perkash	36—45
Shrimati Ahilya P. Rangnekar	45—53
Shri K. Lakkappa	53—58
Shri Parmanand Govindjiwala	58—66
Shri K. Suryanarayana	66—74
Shri Anant Dave	74—75
Shri Annasaheb P. Shinde	75—84
Shri Yuvraj	84—87
Shri Kanwar Lal Gupta	88—97
Shri Vasant Sathe	97—104
Shri A. Murugesan	104—107
Shri Sukhdeo Prasad Verma	107—14
Shri Mritunjay Prasad Verma	114—21
Shri Vayalar Ravi	121—26

COLUMNS

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Saturday June 25, 1977/Asadha 4, 1899
(Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, 1962

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962 :—

(1) Notification No. 95-Customs published in Gazette of India dated the 25th June, 1977, together with an explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. LT-541/77].

(2) Notification No. 96-Customs and 97-Customs published in Gazette of India dated the 25th June, 1977 together with an explanatory Memorandum. [Placed in Library No. LT-541/77].

YOGA UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL—Contd.

MR. SPEAKER : Mr. Raj Narain may continue his speech. The time allotted was 1 hour and it has already taken 2 hours and 40 minutes. You may kindly finish your speech now.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री राज नारायण) : श्रीमन शाप जितना समय मुझे दें, उसी के अन्वर मैं समाप्त

कर दूँगा। (बहुचाल) बप्ला तो बड़ा है, मगर अब उस को क्या छेड़ें। जो प्रश्न सम्मानित सदस्यों ने इस सदन में उठाये हैं, उन्हीं तक मैं भप्ने को सीमित रखूँगा, उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अधिक समय लग जायेगा।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) : Mr. Speaker, Sir, we can close the debate now.

SHRI M. V. KRISHNAPPA (Chikballapur) : Let them take Brahma-chari also along with Ashram.

श्री राज नारायण : श्रीमत कल सदन के एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा कि धीरेन्द्र बहुचारी को बदनाम करने के लिये रजिस्टर में जाली लिख दिया गया। इसलिये मैंने सोचा कि यह बात किसी से छिपी न रहे। मैं रजिस्टर यहां बाकायदा लाया हूँ। रजिस्टर पर कमिक्षन के दस्तखत हैं, मैंजिस्ट्रैट के दस्तखत हैं और धीरेन्द्र बहुचारी के पलेकार दस्तखत हैं। कानून के अनुसार वह रजिस्टर बनाया गया है —

श्री दीनेन भट्टाचार्य : (सीरमपुर) : वह बहुचारी है या नहीं यह बता दें।

श्री राज नारायण : * * *

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I have been hearing him yesterday. This is too much for us. We refuse to hear one word more from him.

SHRI J. RAMESHWARA RAO (Mahaboobnagar) : This innuendo cannot be permitted.

MR. SPEAKER : I have not understood it.

* * * Expunged as ordered by the Chair.

SHRI VASANT SATHE : Even a child can understand it.

SHRI J. RAMESHWARA RAO : I cannot explain it here in this House. I can explain it to you in your room. This innuendo cannot be permitted to go unchallenged. It has got to be expunged.

SHRI VASANT SATHE : Unless he apologises, we will not hear one word. We will walk out.

MR. SPEAKER : You explain it to me in my room. For expunging also, I will have to study it.

SHRI SONU SINGH PATIL (Erandol) : It may be expunged.

SHRI J. RAMESHWARA RAO : You ask the Minister for Parliamentary Affairs. He will explain it to you and he will agree with me.

MR. SPEAKER : Even a Janata Party Member says it must be expunged.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : Sir, you can do as you were pleased to do yesterday. If there is a remark to which serious objection has been taken by the other side, it is always your privilege to look into the record and if in your wisdom you find it is objectionable, you have the right to expunge it.

MR. SPEAKER: An hon. Member from your party also says it must be expunged.

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : Even if the members on the other side feel annoyed they should also observe some restraint and not say, "We shall not allow him to proceed."

SHRI J. RAMESHWARA RAO : I did not say it; I only made a humble submission.

MR. SPEAKER : Shri Sathe said it. Last time I did it and in the same way I shall do it. I have not understood its implication. I will study it. I will expunge it if it is objectionable. Both sides say it must be expunged. I am glad to see that the other side agrees. I will appeal to Shri Raj Narian to complete his speech. I will look into this. Shri Rameshwara Rao also can meet me in my chamber.

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam): If both sides agree, you can expunge it here and now.

MR. SPEAKER : Then it has to be repeated again and explained to me here. I do not want that to be repeated.

श्री राज नारायण : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ आप से। आत ए प्वाइंट आफ इनफर्मेशन। अगर कोई सम्मानित सदस्य मुझे से प्रश्न करता है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वास्तव में ब्रह्मचारी है या नहीं तो क्या मैं उसका यह उत्तर नहीं दे सकता कि मैं उसके बारे में नहीं जानता क्योंकि मैंने उससे योग नहीं सीखा। जिसने उससे योग सीखा है उससे इस प्रश्न को पूछो।

SHRI J. RAMESHWARA RAO : You may kindly expunge it now. What is the use of going on like this? He is again repeating it in different language

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore) : I would not like this to go on the record.

श्री राज नारायण : मान्यवर, मैं आप से जानना चाहता हूँ कि क्या मैं यह कह सकता हूँ कि नहीं? क्या यह असंसदीय है? इस सदन से कोई चीज़ एक्सपर्ज नहीं की जा सकती जो असंसदीय न हो। मैं इस तरह की चीजों को वर्द्धित करने को तैयार नहीं हूँ मैं व इस तरह की चीजों को चलने देने के लिये तैयार नहीं हूँ। एक मर्तवा हो गया, कल, परसों मैंने देख लिया।

श्रीमन्; मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर सदन का कोई माननीय सदस्य मुझ से पूछता है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी क्या वास्तव में ब्रह्मचारी है तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि नहीं मैंने उससे शिक्षा नहीं ली है, जिसको उसने योग की साधना बतायी हो उससे जा कर पूछो?

श्रीमती अर्हिलंगा पी० रामनेकर : (बम्बई उत्तर मध्य). योग सीखने का ब्रह्मचारी से क्या संबंध आता है?

श्री राज नारायण : योग का वह पंडित है आखिर यह प्रश्न हम से क्यों पूछा जाता है?

SHRI J. RAMESHWARA RAO : Mr. Speaker, Sir, You cannot allow him to go on like this.

MR. SPEAKER : I will look into the question of expunging. How can I do it now? All the power the Speaker has is to expunge it. After all, we want to continue the business of the House. We do not want to insult anybody. So, before it goes to the press, I will see whether I can expunge it or not.

श्री डॉ एन० तिवारी : (गोपालगंज) : अध्यक्ष जी, हिन्दी के हों या अंग्रेजी के, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका डिफरेंट इंटरप्रीटेशन हो सकता है, इन्सीन्यूएशन हो सकता है। हम लोगों को चाहिये कि ऐसे शब्द का उच्चारण न करें जिस का गलत मतलब लगाया जा सकता हो। इसलिये मैं राज नारायण जी से कहूँगा कि यह शोभनीय नहीं होगा। ऐसे शब्द न बोलें जिसका अर्थ दूसरा लगाया जा सकता हो।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon): When such speeches are made or such bad references are made, I will request you as Speaker to immediately expunge them so that the press may not get on with it. There are Mr. Ravi and others who will not keep quiet so that the Minister will be irritated while speaking.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : The rules are very clearly laid down that if any Member or Minister is making or indulging or creating a bad taste by using such words in the debate, they should not only be expunged, but the Member or the Minister should also be warned. The Speaker can do everything in his right.

MR. SPEAKER : What Mr. Tiwary said is right and what the other Hon. Member is saying is also all right. Any interpretation can be given on this and I will certainly expunge it as I said. Now, I would appeal to Raj Narainji to go on with this Bill. Let him not insult anybody. You have a right to discuss the charges on Brahmacari or anybody. But let us not insult anybody. It is not good. I would appeal to Raj Narainji to kindly complete it.

श्री राज नारायण : श्रीमन्, मैं बहुत ही अदब के साथ और विनम्रता के साथ

आप से विनम्र निवेदन करूँगा कि संसदीय प्रथा की कुछ डीसेंसी और डेकोरम, सुनीति और सुशोभा है। जा की रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। अपनी अपनी भावना के अनुसार ही भगवान की मूरत सब को दिखाई देती है। अगर किसी की भावना दूषित है तो अच्छे शब्द के अर्थ भी वह दूषित समझ सकता है। यदि किसी की भावना अच्छी है तो वह खराब शब्द को भी अच्छा समझ सकता है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी परिपेक्ष्य में सारी स्थिति का अध्ययन किया जाना चाहिये। मैं पार्लायामेंटसी प्रोसीजर के विरुद्ध कभी जाने वाला नहीं हूँ मैं किसी को भी वह अधिकार देने के लिये तैयार नहीं हूँ कि जो असंसदीय न हो वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। पहले यह डिक्लेयर करना होगा कि यह असंसदीय है। असंसदीय हो, हटा दिया जाये, संसदीय हो तो न हटाया जाए। दूँ की झेंप इस सदन में हल्ला कर के कोई मिटाना चाहे तो वह नहीं मिटेगी।

कल माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि मालूम होता है कि रजिस्टर में नाम इधर उधर लिख दिया गया है। इसलिये मैं रजिस्टर को यहां पर लाया हूँ, जिस सम्मानित सदस्य को देखना हो वह यहां आकर देख सकता है। अगर आप आज्ञा दे अध्यक्ष महोदयः तो वह मैं आप की टेबल पर रख दूँ आप देख ले यह पूरा रजिस्टर है।

दूसरी बात यहां पर पोलिटिक्स की कही गई थी, मैं कहना चाहता हूँ कि यहां पोलिटिक्स कोई नहीं है।

मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल हमारे विधेयक के समर्थन में विपक्ष से भी

[श्री राज नारायण]

जितने सदस्य बोले, करीब करीब सभी ने समर्थन किया और इस बात के लिये मैंने उन को दाद भी दी है। सी० पी० आई० ने जो कुछ कहा, बहुत सुन्दर कहा और मैं उन को एक बात की और दाद देना चाहता हूँ।

जब मैं बोल रहा हूँ तो सी० पी० आई० बातें कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय यह भी पार्लियामैटरी डिकोरम नहीं है।

MR. SPEAKER : The Minister is inviting the attention of Mrs. Parvathi Krishnan also.

श्री राज नारायण : मैं इस बात के लिए इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो जनता पार्टी को चेतावनी दी, वह बहुत ही सही दी है। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास किया है, तो जनता पार्टी तकि भी भ्रष्टाचार को बर्दाशत न करे। मैंने कल अध्वासन दे दिया था कि जनता पार्टी किसी भी हालत में, किसी स्तर पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाशत करने के लिये तैयार नहीं है: कोई भी केस उन के पास हो, किसी भी विभाग से संबंधित हो, वह ला सकते हैं चैयर के ध्रूला सकते हैं और उस को बराबर देखने के लिये हम तैयार हैं, क्योंकि हम ने सिद्धान्त बनाया है कि कथनी, करनी और लेखनी—जो कहो वह करो, जो करो वही लिखो। यह नहीं कि कहो कुछ, और ऐसे कुछ और लिखो कुछ, इस सिद्धान्त को मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं।

इसीलिये मैं अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को बदनाम करने की मेरी तनिक भी मंशा नहीं थी और न है।

अगर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने अन्दर साध्य संशोधन कर लें तो वह किसी काम के लिये उपयोगी भी हो सकते हैं, उनका उपयोग जो करना चाहें कर सकते हैं।

जो अतिथि का रजिस्टर है, वह मेरं पास है, उसमें देखा जा सकता है कि कौन अतिथि आये, कैसे आये और किसके साथ आये, कैसे रहे और कितने दिन रहे। यह सारी बातें देख कर अपने आप जो घटना है वह लोगों को प्रत्यक्ष पता लग जायेगी कि वहां पर योग हो रहा था या भोग हो रहा था।

इस रजिस्टर को सराय एक्ट, 1867 के सेक्शन 4 के अनुसार बनाया गया था। इस के प्रत्येक पृष्ठ पर मैजिस्ट्रेट की सील है और इसके प्रथम पृष्ठ पर डेपूटी कमिश्नर का सर्टिफिकेट भी है। जो गोलियां उनकी मेज की दराज से निकली हैं, उस कमरे पर धीरेन्द्र जी का ताला था, किसी दूसरे का ताला नहीं था। इसलिये किसी को यह मुशालता नहीं होना चाहिये कि किसी दूसरे ने ताला बन्द किया था। वह कमरा मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोला गया, एकाएक किसी ने जाकर खोल दिया हो, ऐसी बात नहीं थी। जितने भी प्रीकाशन्ज और केअरली जा सकती थी, उतनी ली गई ताकि कोई यह न समझे कि बदले की भावना से, या उनको तंग करने की भावना से ऐसा किया जा रहा है

एक माननीय सदस्य : उन के पास लाइसेंस भी था या नहीं ?

श्री राज नारायण : लाइसेंस नहीं था। जो भी बहस यहां हो रही है, उस सारी कार्यवाही का एक नोट तैयार करके हम गृह-मंत्री को देंगे और वे उसके मुताबिक उचित जांच की कार्यवाही कर सकते हैं, केस चल सकता है तो तत्काल केस चलायें और उनको जेल में ले जायें।

मैं कह रहा था कि कमरा मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोला गया, जिस समय उस कमरे

की वस्तुओं की इन्वेन्ट्री बनाई जा रही थी, वह गोली उनकी मेज की दराज में मिली।

एक ज़िक्र यहां यशपाल कपूर के बारे में आया कि केन्द्रीय योगानुसंधान संस्था की गवर्निंग-बाडी पर उनको मेम्बर पार्लियामेंट ने नियुक्त किया था। इस सदन के एक सम्मानित सदस्य ने कहा था कि वे पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त किये गये थे। मैंने इसकी जांच की और पाया—हालांकि यह आवश्यक है कि पार्लियामेन्टरी अफेअर्स मंत्री की राय से नामिनेशन भेजा जाय, परन्तु इनके केस में ऐसा नहीं किया गया, इस प्रकार उनकी मेम्बरी भी अवैध थी। पालियामेन्ट ने किसी को नहीं भेजा था और पार्लियामेन्ट अफेअर्स की मिनिस्ट्री ने भी उनका नाम नहीं भेजा था, वह सीधे जाकर गवर्निंग-बाडी में बैठ गये और बैठ कर वहां क्या-क्या गूँल खिले—अब मैं उसको कहूँगा तो फिर सदन में हल्ला हो जायगा, इसलिये मैं कुछ कहना पसन्द नहीं करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग सोचें कि किसी वस्तुस्थिति को हल्ले के डर से छिपा दूंगा, मैं वस्तुस्थिति को विरोध या हल्ले के डर से छिपाने वाला नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत विरोध देख चुका हूँ। सन् 1934 से विरोधी राजनीति करते-करते 1977 आ गया। कांग्रेस के हाथ में मुल्क की आजादी देकर मैं बाहर रहा।

अध्यादेश 1977 के अनुसार केन्द्रीय योगानुसंधान संस्था तथा विश्वायतन योगाश्रम का परिचालन-भार केन्द्र सरकार ने 25-5-1977 को ले लिया। इस अध्यादेश की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को दोनों संस्थाओं की सम्पत्ति को प्रशासन को हस्तान्तरित करना होगा। इन दोनों संस्थाओं को सम्पत्ति का व्यौरा (इन्वेन्ट्री) बनाया जा रहा है। इसमें बहुत समय लगाना पड़ रहा है क्योंकि प्रत्येक फाइल की अच्छी तरह से छान-बीन करके तब यह काम किया जा रहा है। इन दोनों संस्थाओं के परिचालन कम को सुगम बनाया जा रहा है। योग शिक्षकों

को आदेश दिया गया है कि वे रोगियों के साथ तथा साधकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अब तक जो व्यवहार चलता था उसको बिलकुल रोक दिया गया है और अब तक जो प्रथाओं चलती थीं उन प्रथाओं को भी भंग कर दिया गया है। यह कह दिया गया है कि उन प्रथाओं को अब किसी भी तरह से बरदाश्त नहीं किया जायगा। चिकित्सालय में रोगियों की संख्या 25-5-1977 को 23 थी, वह 25-6-77 को बढ़ कर 27 हो गई है। जिस दिन से इसका टेक-ओवर हुआ है, उस दिन से जनता की आस्था बढ़ गई है और जनता की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अपने रोग के निराकरण के लिये अब लोग आश्रम में आने लगे हैं।

गवेषणा कार्य को वैज्ञानिक ढंग से परिचालन करने के लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

इन संस्थाओं में पूर्ववर्ती परिचालकों ने कई समस्यायें बना रखी हैं। उन समस्याओं के समाधान में अत्यधिक समय लग जायगा। परन्तु आशा है कि शीघ्र ही स्थिति पर काबू पाकर तरकी की जायगी।

यह सारी स्थिति हमने सदन के सामने रख दी है क्योंकि हमारा वरावर यह सिद्धान्त रहा है कि जनता से सम्बन्धित जो प्रश्न हो, उसको खुल कर और खोलकर जनता के सामने रखें। इसलिए हम ने जितनी भी आपत्तियां उठाई गई थीं, उन सब का करीब करीब जबाब दे दिया है और ऐसी कोई बात नहीं है जिसका जबाब न दे दिया हो। इसलिए अब इस पर और ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है।

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill to provide for the taking over of the management of the undertakings of the two Yoga Societies for a limited period in the public interest and in order to secure the proper manage-

[Mr. Speaker]

ment thereof and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : Now, we take up clause by clause consideration. There is no amendment to clause 2. I put it to the House. The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. SPEAKER : Now, we take up clause 3. There are two amendments, one is by Shri Rajgopal Naidu and other is by Shri Kapur. Mr. Rajgopal Naidu, are you moving the amendment ?

SHRI P. RAJGOPAL NAIDU : (Chittoor) : No. I am not pressing.

MR. SPEAKER : Shri L. L. Kapur is not here. So, I put clauses 3 to 16 together. The question is :

"That clauses 3 to 16 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 3 to 16 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री राज नारायण : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पास किया जाएं"।

MR. SPEAKER : The question is : "That the Bill be passed."

The motion was adopted.

श्री राज नारायण : मैं आपके द्वारा विरोध पक्ष को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हमारे तर्कों से वे इतने सन्तुष्ट हो गये कि किसी बात पर बोलने की उल्लंघन हिम्मत नहीं की।

11.29 hours

*DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78

MINISTRY OF COMMERCE AND MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

MR. SPEAKER : Now, we take up the Demands for Grants under the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore) : We cooperated with the Government in having the Order of the Demands changed. But I am sorry to say that the Report of the Ministry of Commerce is made available just now and the report of the Ministry of Civil Supplies and Cooperation has not been made available till now. These are very important documents for us to go through before we speak. I request you that this should be looked into. The second point is that you were gracious enough yesterday to give us time to move cut motions.

Now, the normal procedure is that, you ask us to indicate the serial numbers of the cut motions that we would like to move. We are not at all able to do that because the printed lists of cut motions given by us have not been circulated. So, you kindly give us permission to move them formally on Monday.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : Sir I appreciate the observations made by the hon. Member. We are highly appreciative of the cooperation that the opposition extended to us in accepting the proposal that we made for the change in the order of business. At that time, our intention was to see that the reports reach the hon. Members as early as possible. In spite of the best efforts that we made, there has been some delay. We are deeply sorry for this delay. We hope to see that such delays do not occur in future. We hope that the House will bear with us and excuse us and take up the discussion on these Demands.

MR. SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 15 and 16 relating to the Ministry of Commerce and Demand Nos. 13 and 14 relating to the Ministry of Civil Supplies and Co-operation for which 8 hours have been allotted.

Motions moved :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1978, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 15 and 16 relating to the Ministry of Commerce."

*Moved with the recommendation of the Vice-President acting as President.

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges

that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1978, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 13 and 14 relating to the Ministry of Civil Supplies and Cooperation."

[Demands for grants : 1977-78 in respect of Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation to the vote of the Lok Sabha.]

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 30-3-1977		Amount of Demand for Grant Submitted to the vote of the House	
		1 Revenue	2 Capital	3 Revenue	4 Capital
		₹ Rs.	₹ Rs.	₹ Rs.	₹ Rs.
MINISTRY OF COMMERCE					
15. Ministry of Commerce		48,50,000	..	97,01,000	..
16. Foreign Trade and Export Production		131,54,90,000	106,22,44,000	277,65,39,000	177,19,87,000
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION					
13. Ministry of Civil Supplies and Cooperation		12,27,000	..	24,53,000	..
14. Civil Supplies and Cooperation		7,57,74,000	7,21,16,000	15,27,48,000	14,19,32,000

SHRI A.C GEORGE (Mukundapuram): Sir, This new Ministry is the combination of the earlier Ministry of Commerce and the Ministry of Civil Supplies. Since this is a vital Ministry, more time should be allotted to it.

MR. SPEAKER : Let us see. 8 hours have been allotted. If Necessary, we may extend the time by an hour or so.

How much time do you want to move your cut motions? Will you do it by 12 O' Clock?

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : We are not in a position to tell you the serial numbers of cut motions that we want to move because these have not been circulated yet. We can only formally move them on Monday.

MR. SPEAKER : If you do it on Monday, when are they going to be printed and circulated?

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : We have given the cut-motions this morning. These are yet to be circulated.

MR. SPEAKER : We will circulate them.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : We can only formally move them on Monday.

MR. SPEAKER : Yes; that is accepted.

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : Sir, in view of the fact that the time allotted for this Ministry is only 8 hours, I have decided that instead of initiating the debate, I would like to hear the hon. members give them more time and only at the end of the debate, I shall reply.

MR. SPEAKER : Shri T.A. Pai.

SHRI T. A. PAI (Udipi) : Mr. Speaker, Sir, on behalf of the Opposition, I would support the Demands subject to certain considerations being taken up seriously by the Commerce Minister.

[Shri T. A. Pai]

We must congratulate ourselves in having reached the highest peak of exports last year. Sometimes, the people find fault with the Government or praise the Government for its performance. We forget that this is the country's performance of which either we are ashamed or we are proud.

I must say that the country did very well during the last two or three years. I do hope that it is necessary for us to keep it up. There is a school of thought which feels that the country has been influenced by the World Bank in trying to have export growth performance. But I am afraid it is not so. In fact, as back as in 1969, if you look into the World Bank report, the debts of the developing countries to the developed countries amounted to 16 billion American dollars and this amount was doubling once in five years. But after the oil crisis, it has gone up enormously.

And this country itself is now put to the problem of repaying nearly Rs. 750 crore by way of debt services and the debt repayments, whether it is to the western countries or the socialist countries. The money that we have borrowed has to be repaid. I don't think there is any altruistic consideration in international transactions. We have to pay them with interest, which means that we have to earn this foreign exchange first. Therefore, it is of primary importance that the export performance is kept up.

Apart from that, we found last year and the year before, that considerable capacity in this country had been unutilized. In the First, Second, Third and the Fourth Five Year Plans, the country had taken a leisure in investing the money but not getting the best out of it, and in fact, on an average, the utilization of the capacity in the industry was not more than 40-50 per cent. And having borrowed very heavily from other countries for making these investments and having invested the savings of the people through public financial institutions for creating this industry and not getting the best out of them, would have been anti-national and anti-socialist and going against all those purposes that we had in mind. But the difficulty is that industrial production in this country unfortunately gets restricted because of the lack of purchasing power of the people themselves which has got to be set right. And therefore when you produce more, you have the difficulty of recession in this country because you are not able to sell. Therefore, we have to encourage all industries to develop this idea of exporting using their surplus capacity for exporting.

Now, take the case of engineering industry. In 1972, the performance of export of the engineering industry was only Rs. 180 crore. We said by 1978-79 or at least 1980 that this country should be able to export engineering goods worth Rs. 2000 crore, and I am glad that the engineering industry had fixed the target—they had exceeded the target of Rs. 350 crore last year at Rs. 615 crore this year. They claim that they have exported 10 per cent of the capacity of the engineering industry and they are in a position to step up to 20 per cent.

Now the implication of this is not only to earn money, but the pattern of our foreign trade has undergone very sophisticated changes. Instead of exporting traditional commodities like jute or textiles, our engineering products have ¹ own a considerable share in the export performance. Not only sophisticated products are being exported, India, for the first time, has been able to export turnkey projects to the developing countries. Perhaps this country suffers considerably from inferiority complex and that is why our criticism against ourselves comes up very often. We are not confident that we are capable of succeeding and perhaps our successes in other countries must convince us while the BHEL or the EPI are able to compete internationally against other companies of the well developed countries and are able to secure order in Malaysia or Libya or in Kuwait. It shows our people are appreciated, our technology is appreciated, the progress this country has made is appreciated and if we are not proud of this, I do not know who will be so. I like very much when the criticism against this kind of things comes up that the people should restrain themselves. Certainly there could be a difference of opinion as to which direction we should have gone. I don't think we could wait for another 30 years to find out whether our conclusions are right or wrong.

Today, the whole international field is so confused, I don't think any country can plan for itself. To think of planning in isolation for a country is a ridiculous exercise. The world has become very small. The oil crisis has upset everything. The Eurodollar Market is with its swing up and down has made difficult even the most sophisticated economy to control internally what is happening. Now the Arab dollar are in the market. Neither the economic theory nor the old method of controlling money supply is any longer valid. It is the ability of your country to react fast to the situations that develop. It is here that I would make a request to the Commerce Minister. The Capacity of this country would depend entirely on developing the ability

to react to the fast-changing situations abroad and not go by the old theories or the old experiences which are no longer valid. When we enter this field of export of turn-key projects, we find that it is not merely the industries that have to gear themselves up, but even the financial institutions and our methods of working also will have to be geared to meet the international competition. While in other countries their Governments are solidly giving support for the industries to take up these projects, we have somehow felt that all this assistance is not necessary. I have seen the Prime Ministers of countries intervening in order that their country might get the order. It may be that it is not the Prime Minister's job. But when the prestige of a country is involved, I think, the entire Government, the entire country, will have to be involved in this, and it should not be treated just as a business operation.

Again we will have to develop certain strategies of development. The joint projects which we had started in Malaysia and some of the countries in the Far East have brought considerable goodwill for this country. It is not merely the political relationship that we have to develop; the inter-dependence of the developing countries with India has also to be developed. The last Conference of the UNIDO, Ministers of Industries in India also clearly pointed out that while the dialogue with the developed countries might be continued, there should be greater efforts for trade between the developing countries themselves—more cooperation and collaboration. I have seen some of these joint projects abroad, they suffer because of lack of imagination on our part to react quickly to the difficulties that they suffer when they go out of the country; it is the official procedures and other difficulties that are created which make them unable to cope with the situations abroad. And if you are really interested in developing such projects—I, for one, would strongly recommend this course because in the Far East there is so much of goodwill for India; the countries are trying to develop themselves under the ASEAN scheme and they are trying to build up tariff walls against others—we should establish soon our projects in various countries with the special abilities that we might have in taking up any international development, and that would be for the lasting benefit of India. Similarly, efforts will have to be built up in Africa—these countries are developing very fast—and in the Middle East. They depended once on foreign technology and the big names of the West and are now realising that they have been taken for a ride and that it is necessary that they must get the technology from India because ultimately most of these projects are being managed by Indian technicians for want of manpower in those countries

Let not the Commerce Minister take an attitude that the export performance is enough. I think, it must have a deeper significance than merely exporting goods; we must export our talents, we must export our abilities, we must be able to bring the whole world together and be participants in the developing countries. The developed countries have realised that India is developed in one sense. When we say that, in 30 years, nothing has happened, we are only denying our history; it is denying that the country is today one of the developed countries in the world with immense problems of developing. I am not minimising the problems of developing. Every development has its own problem; it will create situations which were not imagined. If we think that the planners, including the new Planning Commission, are Lirikhaspati in this world and that we can expect magic from them to transform the great problems of this country, we are making a serious mistake. We should be prepared to admit where we have gone wrong; we should have the humility to adjust ourselves to the peculiar Indian conditions. After all, for the problems that we have, we do not have: any model of development except that of China. Whether we are prepared to go with that kind of rigidity, it is upto us to decide. Without that rigidity if we have means of developing, then we should certainly try, I am not minimising the difficulties. But to say that all that has happened in the past has no relevance is entirely incorrect. Today we have the abilities to take up responsibilities which, 30 years ago, we did not have. You have the industries which can manufacture enough to meet the needs of the village industries. You have the trained manpower who ought to take up this responsibility of developing the most backward areas in this country. The only thing that is required is the will to do and proper planning. You may change the priorities, there is no question of keeping the same priorities.

Today, the performance of export is supported by the heavy industries. The Country's respectability has gone up in the eyes of the world on account of our ability to produce power plant at BHEL or undertake the construction of 2500 houses in Kuwait and if this ability was not there, nobody would have trusted us. I would like that this ability is continuously built up and improved upon so that we become participants in the world trade.

We take great pride in our export performance, but we should realise that we

[Shri T. A. Pai]

are exporting hardly anything between half and one percent of the total world trade. The total exports of an Island like Hongkong are almost equal to us and, therefore, to say that this is all and there is nothing more to be done and on the other hand, we should go back, is not correct. I would like the hon. Minister to consider this. Today, what is happening in this country? We export what we cannot sell in the domestic market which means that when we can sell here, nobody will export. We cannot build up international trade in this manner. International trade depends upon continuous contacts that we establish. The contacts will depend upon our reliability, upon the quality of the products and their competitive prices. Nobody comes to us out of love for us. It means that unless we develop this kind of finesse in the international trade, we would not be in the field for a long time. If the Commerce Minister looks into the various lists of commodities which featured in our export programme, he will find that there is hardly any exercise to find out why is it that one particular commodity which was exported last year does not find itself in this year. It shows that we function by fits and starts. One short operation cannot build up international trade.

What do we export? Ultimately, in a product there is labour involved, there is raw material involved and there is technology or brain involved. Brain and brawn and the raw materials. If out of these three, two elements do not come from India, it is not worthwhile exporting anything. There is no point in getting all the three elements from outside and say that we are exporting. Therefore, we will have to identify in future the fields from the point of view of world market. The idea that we can sell anything which we cannot sell in this country abroad is perhaps one of the most ridiculous ideas. We will have to find what the world requires, not only now but prospectively. We will have to do an exercise to find out the need of the rest of the world and find out in terms of raw materials, in terms of skills and abilities, what we are in a position to export.

In respect of certain industries, we did try to have an exercise. We felt that fisheries have considerable scope; as against 180 crores, it may be possible to step up the export to 500 crores. These new lines of production will create more employment. Secondly, garments are there. We tried to liberalise the conditions which applied to this industry. It is not enough only to liberalise the conditions; there must be persistent effort to achieve the goal. The third is engineering industries and

the fourth is electronics. The basis of growth of electronics industry has been to achieve self reliance in the country. It was never export oriented, but this is one industry which is an intellectual industry, where the capital involved and the raw material involved are the smallest and if ever you want to absorb vast technical manpower as quickly as you can, the competence of this country in electronics will have to be built up quickly. I do not think we can go on talking about it, because the world is going much faster than we have been able to do.

In the past few years, our relations with Soviet Russia and East European countries have been very pleasant. When the rest of the world was not helping us, these countries entered into bilateral agreements with us. We meet and decide every year that the trade will be doubled or trebled, but unfortunately after all these developments, India today has to sell only things which they can sell to us. So, in the past the East European countries were prepared to give us machinery but now we tell them that we have the machinery. So this idea that trade can be carried on only on the basis of exporting without importing is also not correct because no country can afford only to buy from you unless you are prepared to buy in return something from them. Therefore, the time has come when the Minister should make an effort to see whether the bilateral trade can be converted into multilateral trade and there is a closer collaboration with the East European Block which has been a trade partner with us for a long time and we cannot afford to neglect them. I think there is a considerable scope for collaboration with them in these matters. Therefore, this is another aspect of the commerce which will have to be looked into.

Thirdly, I would like the Minister to look into one item which is asking us to approve an expenditure of Rs. 263 crores on foreign trade development and all that. Now, I do not know why this money is being wasted. Apart from that, we have this State Trading Corporation, MMTC, TDA and a multiplicity of organizations under the same Ministry operating abroad and sometimes working at cross purposes with each other. I had to bring it to the notice of his predecessor once, that MMTC, and STC are in competition with each other. That happens in the Government of India where every Ministry is an empire by itself and which is very anxious to protect its own prestige and all organisations under a Ministry become very important since in the name of autonomy they do not consider the interests of the country being more important than

their importance. I think the country has suffered a great deal on account of this. Apart from that in our Embassies we have the Consul-Generals who do not know much about trade and the time has come when you train a new cadre of persons. If necessary, draw them from any sector—Government sector or public sector or private sector and train them in order to see that our products are popularised. Otherwise I have seen the attitude that somebody exports something from this country and it is below standard and the embassy receives a complaint and the embassy complains to the Commerce Ministry and the Commerce Ministry says, 'It is no one of our business to interfere in this.' When, in the world we are developing a reputation that we are not true to what we say and what we send by way of samples and products are not the same how can business be developed? It may be that 10% or even 1% of the people behave like this. But when we have inspections provided for things that go out of the country, why should there be any complaints at the other end that what you have supplied is below standard. This is an insult to the country. Even if you do not want to send, do not send but do not send wrong things and get a bad name for the country. I have received this complaint in Peru. I have received this complaint in Australia. I have received this complaint everywhere and, therefore, this seems to be a general pattern and I would very much like that the working of our Consul-Generals, the working of STC, MMTC, TDA for which so much money is asked for, is looked into. Apart from that, what are the branches of our banks doing? What is the LIC doing? Take Japan. The branches of the Japanese Banks are their ambassadors at the economic level. It is not necessary that you should have one new corporation for selling each item. I would also like you to look into it.

When I went to Sofia, I found that the tea packet, said, 'Made in Ceylon'. Go to Belgium. There is no name. Why in all British restaurants in the menu card it is mentioned, 'Tea made in Ceylon' but not of India. Why? Because we have believed in selling wholesale to the London market not realising that the highest profits in the international trade are realised in the retail business and not in the wholesale business. So, we are trying to do something which is easier. If we want to popularise this product development should come in. But unfortunately, it is not so. I would very much like that the Minister thinks of utilising the services of the non-resident Indians

abroad who have all the facilities of trading there. They now merchandise mostly Chinese goods, I would very much like that Indian Banking system gives them loan for this purpose and every effort is made to utilise the services of Indians abroad to popularise those products so that the highest per unit value could be obtained.

Another aspect of international trade is participation of Commerce Ministry in exhibitions. If you fail in international exhibitions, you will feel sorry and the exports cannot go up. In Zagreb when I visited Chinese pavilion it was a beautiful and one of the best pavilions. It showed that progress that China had made and China did not require canvassing of any kind for the progress that they had made because the products that were shown were the best. Instead our people were having a big kettle and were offering tea packets to everybody free. Either you should be serious or do not participate at all. I would prefer that you take it seriously, because the idea of spending is to establish permanent trade relationship. I would like that in future through proper participation in these exhibitions, Minister will enhance the reputation of India.

Now I come to the functioning of industries. Last year, we had an industrial growth of 10 per cent. Unfortunately, the textile industry failed us very badly. My complaint was textile was not doing well because there did not seem to be any basic policy of textiles in this country. Soon we should decide a national clothing policy rather than textile policy so that the people of this country are clothed, and the per capita availability to which also depends upon our textile exports have no meaning for the people. The question is can we make our cloth cheap? Can we make cloth available to the people. Statistics are not going to clothe the people of this country.

He has on hand 103 or 105 sick textile units which form 20% of the production capacity of textiles in this country. I think, at one stage, two years ago, it was losing @ Rs. 6 crores per month. What is the use of making profits in all public sectors, to be lost in one NTC. So, it becomes not only a sick industry but it becomes a sick set for the public sector also. An exercise was conducted some time ago of modernising the NTC Mills. An estimate of Rs. 600 crores was provided.

[Shri T. A. Pai]

Where do we have Rs. 600 crores to modernise? With Rs. 30 or 35 crores which is provided, I do not know what can be modernise? I would like him to consider whether modernisation is only to keep the industry as it is replacement of old machinery by a new machinery or restructure of the industry is also called for?

Private Sector has not come forward into textile industry for the last so many years. NTC should not lose money. I would request him to consider conversion of four very big spinning units for four regions of the existing units and convert all other mills only for weaving. Because the practices that were complained about in the private sector continue in the public sector also. In the matter of purchase of cotton, in the matter of marketing and so one unless you try to see that the purchase points of these units are limited and you have greater control. I am afraid, the losses will not be controlled.

12 hrs.

This brings me to another point with regard to our international trade. If we want to sell anything to Paki tan, if we want to sell anything to Sudan, for instance, the most important point is that we will have to have long and enduring relationship with these countries. Otherwise you will not be able to sell. When they sell to the developing countries or developed countries their main product like cotton we will have more competition in respect of our textile industry. Perhaps a similar arrangement is necessary with Bangladesh for jute. Therefore it is very necessary to have this sort of enduring relationship with our neighbours; you can buy their produce from them even if it means a little sacrifice. Thereby the economy of the countries will get more and more integrated and we will be able to play a better role in the development of the region as a whole.

श्री उमा सैन (देवरिया) : भार्या
महोदय, बात सारं नहीं है। माननीय
सदृश क्या कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण
चाहते हैं।

SHRI T. A. PAI : Whether you want to nationalise or not is your own business. I only want that your industries should be run properly. It is not a question of public sector which is important now, but what is important is the proper functioning of the public sector. The sort of talk against public sector

which we hear is going to demoralise them. We have sunk considerable finance which we got from abroad, which even our children and grand-children are committed to pay. After all, in this country we have seen that the debts of the grandfather are discharged by the grand-children. But I don't want to leave such debts to be discharged by them and I do feel it would be better if it is possible by our own efforts to repay most of them.

Coming to civil supplies, the problem here is this. A poor country like ours cannot afford to have inflation. Some people are protected by D.A. rise. Vast number of public suffer on account of rise in prices. All sections, all parties, must have a vested interest in stabilising prices. It is not monetary theory alone which matter. Of course, theories, are important, no doubt. Last year, the prices went up in respect of groundnut oil which affected other oils too. Prices of gur also went up by 100%. It went up in respect of cotton. The country will have to develop its ability to manage the economy in regard to these commodities which are of beneficial service to the people. Last year we suffered a great deal because the Gujarat Government wanted to protect its own people. Inspite of Governor's rule, availability of groundnut oil became difficult. If any State knows that the country depends upon it and wants to do like that, I am afraid we will have to continue with deficit for atleast five or ten years more. Because even the budget has provided hardly Rs. 1.60 crore for oil-seed development. We have sunflower oil and soyabean oil which have been hardly developed. The greatest gift of God to Indian is the sun. Every part of the country is capable of growing anything. There are difficulties faced by farmers. Nobody wants to commit suicide. Nobody wants to grow something if he is to be told later, we don't want to buy from you. Again in the restructure of the textile industry, I am pointing out that the complaint against this country was that when the per acre yield of cotton was low and when science and technology is applied to growing of cotton and when we have been able to produce a higher yield of finer cotton, the whole industry will have to be restructured to use this. It is not correct to say that superfine cloth is a luxury of the rich and that the poor people of this country should wear only the coarse cloth. I say that the philosophy should be that the people of this country must be able to use what the country produces. If you are able to produce more super-fine cloth, I do not see anything wrong in a man's getting a finer dhoti and poor man's getting it at a cheaper price. You should not prohibit

that. So, I say that some clarifications in our own thinking are absolutely necessary. Don't go about saying what you want to do. But, say what is being done. It is from this point of view I say that your difficulties are immense. Please do not say that it is because your report for civil supplies was not implemented and so the prices have gone up. Don't make that mistake again. We can write a very fine report on paper. The question is : how to implement it. You are not the person to implement it. You only lay down the policy. Civil supplies are in the hands of the State Governments. Even the emergency did not affect them. I can tell you that for the first three months I used to get information from every State as to what exactly is the difficulty that was experienced in respect of particular commodities because, shortages can develop in any part of the country. Even if the wagon movements are manipulated, you will find shortages everywhere. There may be a surplus of the same product somewhere and considerable shortages elsewhere, at the same time, since the implementation is with the States unless you have a well-developed information system which extends to the whole country to inform you about what is in short supply, I do not know what you can do about it. Therefore, it is necessary that for the information system you should not depend only on official organisation. Non-official organisations, but also you should see the *Samachar*, for instance is involved in this so that their correspondents in different parts of the country may inform you what exactly the situation that is developing is and after the receipt of that news, if you try to act immediately, the tendency of hoarding and blackmarketing also will go down.

You now say that you are opening 1,000 shops. I can tell you—my hon. friend Mr. George knows it—that we are prepared to admit our shortcomings. For example, the prices of vegetables were going up in Delhi. He went and inaugurated a co-operative vegetable shop. After one week, I had to tell him that the shop had no vegetables. So, if you are going to open shops without the products being supplied what is the use of that? Don't worry about opening of shops in Madras or Bombay or Calcutta. Look at Madhya Pradesh, Bastar area. Also look at the various other inaccessible areas of this country. They want communications. It is only there that the people have to pay a higher price for the requirements of their living. So, if you want to open 1,000 shops, please identify the most important and in-

accessible areas where the shops can be opened because you do not have unlimited resources.

SHRI MOHAN DHARIA : Sorry for interrupting you. I would not like to interfere. But, there is some short of misapprehension. I was addressing Vaikunth Mehta's Institute and said that for the development of the cooperatives, youngsters will be given all the possible encouragement. And these 1,000 shops can be opened by the youngsters. That has little to do with our massive distribution system. I agree that unless and until we make these commodities available to these shops, it is no use opening these shops. I can very well understand this.

SHRI T. A. PAI : That is all what I wanted to tell you. What I was pointing out was that the opening of shops, alone is not enough if the things are not being made available to them. That is a very difficult exercise also. It is not that merely by opening the shop, you will solve all the problems. But if you want to make it competitive with the private trade, your shops must not be empty because if the Government shops are empty private trade will have greater advantage in manipulating the market.

The most important problem to be tackled is with regard to public distribution system. Take the case of wheat. You see the cost of it in this country. We have to see that the growers must get a fair price and, at the same time, we have also to see that the consumers also must get it at a reasonable price. This twin objective can be achieved only if the gap between the producer's price and the consumer's price is reduced. But what about our official organisations? Today, you say 20 to 24 million tonnes will be procured and you do not know where to store it. You say 2 million tonnes of wheat—which got affected by the rains—is also a great problem. Further, you do not have differential price for good and spoilt wheat. When there is shortage of food grains in the open market then everybody goes to fair price shops. If better quantity is available, people avoid them. The public distribution system should not sell sub-standard foodgrains. The sub-standard foodgrains must be destroyed rather than being given to the poor people because poor people in this country cannot be given anything which is not good enough for eating. There is no question of any kind of adulteration by anybody. It must be the same policy that must be applied to all.

SHRI DINEN BHATTACHARYA : (Serampore) It is a legacy of the past.

SHRI T. A. PAI : It is a legacy of the Indian character. I am telling you not to follow the past precedents. We are prepared to admit our mistakes. If you like, I will criticise myself. Last time, for instance, as Minister of Civil Supplies we came across an instance when some stone was found in the Modern Bakery bread. We could not prosecute the Modern Bakeries because it was a government concern. I do not want that standard to be applied. Do not go by the past precedents.

Mr. Speaker, Sir, it was shocking for me to learn that in the last four years we have given a subsidy of Rs. 1,800 crores for wheat distribution and that is equal to the total stock of wheat on hand today. Last year we distributed Rs. 560 crores as subsidy for wheat. This year we are providing for Rs. 460 crores. I am sure it will go up because the procurement price has gone up.

Mr. Speaker, Sir, a lacuna has come to my notice. To my shock I find while the wheat eaters are provided with a subsidy of Rs. 24.15 per quintal, the rice eaters in this country are provided with Rs. 1.35 per quintal. What sin have the rice eaters committed? Are they rich enough? Why do you make distinctions between the rice and the wheat eaters. The same subsidy should be given. One of the reasons as to why the rice production in our country has not gone up is.....

SHRI SAMAR GUHA (Contd.) : I raised this very matter on the Floor of the House and the then Minister stoutly denied it.

SHRI T. A. PAI : Whether it has been denied or not yet it is a fact. Please, do repeat it. I know the government always goes by precedents. Please, try to establish new precedents. So, Sir, if you want the rice production to go up, then you must not penalise the rice growers.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Unfortunately, you did not speak earlier.

SHRI T. A. PAI : If I were an ordinary member like you, I would have spoken. I was a minister. Let us not say whether I had spoken in the past or not. Say, whether what I say is correct or not the point is that you will have to think for making proper policies now. Sir, the Minister for Civil Supplies has only the right to make policies. He has not got the food department with him. He has not got the vanaspathi industry with him. He has not got the sugar industry with him. In the vast empire, it is preserved in another Ministry which is reluctant to part with them. They make their own policy. He has to go and discuss with

them, coordinate with them and plead with them and by the time he does it, the prices go up and he is not able to bring them down. I would very much like, whatever happens, a reorganisation of the Ministry is called for. Either he should agree to this or he should not take the responsibility. I can assure him that in spite of his report being implemented he will not succeed. Fortunately he has got the textile industry with him with all the problems that we have. Now in the case of textile industry, he has a lot of unnecessary expenditure in his department. The Textile Commissioner's office came into existence after the Second World War. It has gone on expanding without knowing why it is necessary. Now today it is finding work for itself. If spindles have got to be changed it requires a written permission of the Textile Commissioner. If an old item has got to be discarded, it has to be done in the physical presence of the Officers of the Textile Commissioner. Can you not find some better work for them? I am sure, if every industry has a commissioner like this, you do not have to look into the reasons why any industry has become sick. So, for heaven's sake let us look into all the expenditure. Again the Finance Minister has said that there should be a 10% cut in the expenditure. You will have to find reasons, causes for the expenditure. If the cause for any expenditure is not justified, cut it out completely. There was a classic instance of two guards in the Buckingham Palace appointed 150 years ago to look after the seats in the Government and for 150 years people retired and they were appointed. One day somebody asked why they were appointed. They found that originally when the three benches were painted they wanted to see that nobody sits on the benches and therefore, guards were appointed. But the appointments were continued in spite of the benches having dried up long long ago. I can assure you that there are many departments in our Government which deserve to be looked into. In fact we had to abolish the tariff commission. Well, Sir, you say you are the successors to Indira's Government and I can assure you that you will fail because the administrative set up is not going to be changed, their attitudes are not going to be different and you are going to justify everything you did was right. Wait for some time. You will all now say that you are perfectly satisfied with the Government. It is not a question of this Government or that Government. You will have to continuously see, whichever Government it is, wherever things could be improved, they ought to be improved in national interest. It is not in your interest or my personal interest. You may say it is a 'criticism of your own'.

I do not hesitate to make it. Therefore I would very much like the Civil Supplies to give the consumer due importance, which we have failed to give. I wanted women's committees to be appointed everywhere. But somehow men do not like women's committees to be appointed even to look after these things though they are the housewives. They are the persons who suffer from these difficulties. Take the case of vegetables. Prices of vegetables have been going up in cities. One item which goes up every time is the price of vegetables. Is it difficult to grow vegetables? There are many villages in our country where vegetables are grown and there is nobody to buy them. Even if it costs Rs. 8/- per kilo in Delhi, people will buy it. They will complain but there is no effect.

Your suggestion to start one more corporation will not solve the problem. This country has got this habit. Whenever there is a problem, there will be a committee or a commission. Now we have developed another technique. Whenever there is a problem, we have a corporation. I tell you, corporation does not grow vegetables. The difficulty is to transport the vegetables to the urban areas from the villages. If you can create this facility of transportation, you will make life much more attractive in the urban areas and the business of growing vegetables much more profitable to the villagers. Today it is in the hands of the middlemen. The wholesale trade is entirely controlled by black money and we made some efforts control it. But it requires considerable effort to do it. Sir, I wish that during Mr. Dharia's time, all these problems will be seriously looked into, that he will not be satisfied with exports of 5000 crores. Of course, do not go by blanket assertions. "We won't export onions. We won't export vegetables. If the price of rice is Rs. 30/- per kilo in Abu Dhabi and if you say, you do not want to export rice, it will be smuggled. I would rather prefer you to have special production of rice to meet the requirements of your neighbouring countries if you are at an advantage. Let us look into it. With these words, I wish him the best of luck, because if he succeeds, it is the success of the country. It is not a question of any party succeeding. If the party fails, the country fails. We are interested in the success of the country and therefore, we wish him the best of luck.

PROF. R. K. AMIN (Surendranagar): Sir, I rise to congratulate the hon. Minister as well as to sympathise with him because he has inherited a good deal of confusion in his ministry. The previous government has created such a

confused state of affairs in the ministry that it would be a Herculean task to clean the stables. A little while ago Mr. Pai added to the confusion by saying, our country is the most developed one, with the greatest possible number of problems of development. If it is a most developed country, how can it have the greatest number of problems of development? He also said that ours is the poorest country! He has added to the confusion and therefore, I would say to the hon. minister, "take courage and take a bold step to come out of the confusion in which you are entangled by the past government."

12.23 hrs.

[SHRI SONU SINGH PATIL in the Chair]

Let me take the case of edible oil. We are very much concerned about the rise in prices in this commodity. If you analyse the factors behind it, even from the opposition I find two views are being presented. Mr. Chavan said sometime ago that prices rose because the may supply increased by Rs. 840 crores in the months of April and May 1977. Mr. Pai just now said that the price rise is due to failure of supply management and low production in certain commodities. Mr. Chavan challenged us a few days ago that this is going to be a budget which would please the stock market and that the moment the budget was presented, the prices in the stock market went down. With such false forecasting, the opposition is not going to help us. The minister must not take any hint from them because they have created sufficient confusion in the ministry. If he really wants to come out of the entanglement, he must take a bold and imaginative stand.

In October 1976 it was very clear that there was very little edible oil in the pipeline and our stock was the lowest in the last several years. Any sane government would have imported oil at that time or entered into a contract for the import of oil at that time. They did not do it. They allowed export of oil from the country. Had they also simultaneously purchased cheaper soyabean oil, probably our problem would have been eased, but they did not do so. In January-February 1977, when the problem became very acute, instead of dealing with the problem in a straight forward manner—the acuteness was such that they should have imported oil immediately and should not be after 12 months—for reasons best known to them, they gave licences to the importers to the tune of Rs. 500 crores without any conditions whatsoever! I do not know why they did so. When they saw that there was no stock available with us, when they saw that there was an acute shortage all around,

[Prof. R. K. Amin.]

they should have given licences to those who would like to import immediately and also sell it immediately and there should not be a big profit on such sale. Instead of doing that, during the month of February and March, those who have got the licences for import of oil, purchased the oil and sold it out there in the foreign countries because the international prices went up. Some of them brought it over here and they got a huge profit on that turnover. I have evidence that the landed cost of imported oil was Rs. 110/- per tin and they had sold it out after the import within 15 days at Rs. 137 per tin, that is, a profit of about 20 to 22 per cent on the turnover. In the usual course it would have been a hell of a job to get such a huge profit on the turnover. I have also got the evidence that a licence of huge amount was given to one party. I say, Rs. 47 crores worth of licence was given to one party and up to 18th of May that company did not import the oil. He imported oil worth only Rs. 5 crores, though his licence was for Rs. 47 crores. During the three months he could not import oil worth more than Rs. 5 crores and that also he sold it at very high profits. He had also contracted for import of oil worth Rs. 25 crores abroad. In a letter I suppose the National Convenor of the Hindustani Movement, Mr. Madhu Mehta, has also supplied the information to the hon. Minister that he has the intention to take advantage of the rising prices in the international market. This company also says that it has got more than 10 per cent profit consistently. So, these are the importers who have got the licence from the previous Government. The previous government did not put any condition on them and that is why it is a Herculean task that the hon. Minister will have to discharge.

SHRI VINODBHAI B. SHETH (Jamnagar): The Hon. Member should place these important documents on the Table of the House.

PROF. R. K. AMIN: I am prepared to place the documents which indicate that M/s. Godrej Ltd. were given a licence worth Rs. 47.60 crores. He has only got the import of oil worth Rs. 5 crores. He has the intention to take the advantage of the rising international prices. His profits are more than 10 per cent and his landed cost is Rs. 110/- per tin and he has sold it out at Rs. 137/- per tin. With your permission, Sir, I am laying all these documents on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-523/77].

MR. CHAIRMAN: Mr. Amin, you wanted to produce some documents. So, they are to be given to the Secretary

and we will examine them and we will decide afterwards whether they can be laid or not.

SHRI VINODBHAI B. SHETH: I would request the Chairman to actually allow him to place the documents on the Table of the House.

PROF. R. K. AMIN: The documents indicate that the landed cost of import of oil was Rs. 110/- per tin and the importer has sold it at Rs. 137/- per tin. They also indicate the importer's clear intention of getting 10 per cent profit consistently. He had also declared to the bank that he would like to take advantage of rising prices in the international market. Now, how could you take advantage of the rising prices in the international market? It means that you purchase and sell it out in the market when the prices have risen and make huge profits and keep your foreign exchange abroad and do not bring the oil here in this country and thereby make it possible to increase our foreign exchange reserve. I have got evidence to show that such people were given licences by the previous Government. My request to the Minister is to take a very bold and imaginative step because your job is a very very difficult one.

My friend, Mr. Pai, has referred to our export policy. Now I would like to say that the previous Government never understood the changing time which is taking place in the international market. They were brought up in a policy which was suitable when our rupee was over-valued and stable prices elsewhere and rising prices in our country were prevailing. Under these conditions, probably their policy was correct. At that time you had an inflationary situation in our country, and the importing countries did not have the inflationary situation. At that time you had evolved a policy of encouraging export and restricting imports. Now, after 1973, the situation has changed considerably which fact has not been taken into account by the previous Government. I mention this because the hon. Minister could take all these factors into account, while overhauling the import-export policy. After 1973, the dollar reserves had not been accumulating with the U.S.A. and European countries; they had started accumulating in the oil exporting countries. Even the Middle East countries are having a lot of dollar reserves. The whole pattern of international trade has changed which should be taken into account while encouraging the exports or restricting the imports. The second factor is that there was a system of fixed exchange rate all over the world. There is now a freely fluctuating exchange rate all over the world. That is why the smuggling has come down.

Smuggling has not come down because of Government policy or because of Emergency. It has come down because there is a very little difference between the blackmarket rate and the official exchange rate. That is why it is not profitable to them to smuggle. Formerly one ounce of gold was equal to 35 dollars. At that time the gold price was very high in this country and therefore the gold was smuggled into the country. Now the gold price is no more fixed. It is determined by the demand and supply position. That is why it is very high abroad and the difference being smaller, it is not being smuggled now.

Sir, there is great need of going in for overhauling the export promotion policy, because export will take place automatically now because our rupee is not over-valued as it was before. When rupee was over-valued, there was a need for encouragement, but not now. You have so far given a lot of encouragements by way of low rate of interest, subsidies and import entitlement. When the things are changed, when the situation is changed it is a pity that we are still continuing the same old system. The hon. Minister must overhaul his export promotion policy to suit the present circumstances. The whole machinery which was suitable for fixed exchange rate should be scrapped and a new machinery suitable to the present circumstances of freely fluctuating exchange rate should be installed.

My third point is about the sick mills, especially in the textile sector. Probably that is the only industry which has been in the grip of controls to the maximum extent. Labour is controlled; installation of spindles is controlled; installation of looms is also controlled; even production pattern is controlled i.e., what is the length of a dhoti and what is the length of a saree; etc, is controlled. If at all any industry is controlled all around the classic example is the textile industry. The sooner, Sir, these unnecessary controls are removed, the better it would be. I request the hon. Minister to look into this matter earnestly and also quickly and remove unnecessary controls in the textile industry.

I am glad that he is evolving a multi-fibre policy. Here again I should like to point out the changes which have taken place. Formerly cotton was cheaper and manmade fibres were dearer and that is why we also imposed high excise duty on those who were using man-made fibre. Now cotton is dearer. From 1960 we were trying to increase the production of cotton in our country but it has remained stagnant around 60-70 lakhs of bales of cotton; it has not increased. There is no noticeable rising trend in production of cotton in our

country and because of that cotton is becoming dearer and our policy should be to economise the use of cotton. On the other hand manmade fibres are cheaper and durable and many poor people have started using it and found it to be cheaper in the long run. I, therefore, welcome our multi-fibre policy. But when it is to be evolved it must be borne in mind that cotton is under the control of the Ministry of Civil Supplies and fibres are under the control of the Ministry of Petroleum and Chemicals. If those two ministries have no effective coordination, it will create problems in the growth of the industry. There should be a well thought out integrated policy in the civil supplies and commerce ministry. The Minister, I hope, is aware of the need for reorganisation of the ministry for this purpose and I also urge upon him that the evolution of the multi fibre policy should be done as early as possible.

In this connection, I want to submit that the export of textiles of manmade fibre is hardly of the order of Rs. 30 crores in India whereas South Korea exports goods worth about Rs. 2,000 crores and even a small country like Taiwan, has exported textiles of manmade fibres worth about Rs. 1,200 crores. Looking to our situation, since we have so many skilled workers in textiles, it is possible to develop our exports as much as, if not more than, what they have done in South Korea and Taiwan. For that you must see that the organised sector in textiles develop their export in man made fibre textiles and for that encouragement has to be given in order to import fibres, give them all concessions in imports of raw material and in return they should give employment to people and export the entire products so that you can give employment to people here and at the same time you lose nothing because the raw material is imported and the finished product is exported. If you develop in that way, your large-scale industry can be encouraged and at the same time labour also will get employment. We are not losing anything at all because we import raw material and we export finished products. The hon. Minister can look into this matter. About cotton also, the previous government decided for the import of cotton worth about Rs. 400 crores. If imports are permitted it will have an adverse effect on the growers. If you adopt an uncertain policy in regard to import, cotton growers get discouraged even though sometimes they get a higher price.

If you wanted to adopt a consistent policy, you could have imported man-made fibres, because it will not hit any supplier over here; whereas if you import cotton, it will hit the existing

[Prof. R. K. Amin]

producers of cotton. When you have an avenue available whereby you are not hitting any people here but at the same time your purpose is served, why not adopt that course? Instead, you are adopting a policy which will hit your own producers. I plead with the hon. Minister that he should adopt a policy by which more and more man-made fibres are to be imported; and the cotton growers are supported very well in the domestic market.

I now refer to the question of sick mills. Earlier, it had been admitted that taking over of sick mills by the government has not paid any dividend to us. The NTC is incurring huge losses; and government is so tired of taking over the sick mills. Therefore they have declared that they will not take over any more sick mills. The second alternative suggested was that good mills may be encouraged to take over these sick mills. That alternative also is not a happy one, according to me, because it only means supporting the sick mills with government money. When the good mills which have accumulated profit or profitability take over the accumulated losses of the sick mills, it means that this profit will not be taxed; it will be at the cost of the tax revenue that the losses of the sick mills will be offset. That is not good. Secondly, it will not be possible to find out whether the sick mill has lost its sickness or not, because, along with the good one, i.e. under its shelter, the sick mill will remain alive. Oxygen will be given to it, but its sickness will not go. I suggest that the third alternative should be taken up. Whenever there is a sick mill the moment the management thinks of closing it down or when the management accumulates losses beyond a particular point, it should be auctioned out. Let the unit be the same. But a new management will come. The new management must come without any encumbrment whatsoever, and without any profits of the other good mill. If you allow good mills to take over, very soon you will find 5 or 6 people controlling all the mills. If you have a sick mill in Ahmedabad and if you think of other mills taking it over, you will be thinking of Mafatlals or Kasturbhai doing it. Kasturbhai is already having 7 or 9 mills. He will add 2 or 3 more. If Mafatlals are to do it, they will take sick mills and thereby will lead to greater concentration of economic power—which we want to avoid. That is why the third alternative should be taken up. (Interruption) Your suggestion is for the State government taking it over, instead of the Centre doing it. No, that is also not a good alternative, there is no difference between Central and State Governments taking over.

Before I sit down, I have two suggestions to make. The management of the MMTC is rigid and bureaucratic. It is a trading concern. It must behave in a business-like way. If there is an offer from abroad, it will take about 7 or 8 days in order to decide whether to accept the offer or not. In business, you have to give the reply the next day; otherwise, the offer goes away. You cannot deal with international offers by dealing with them like a government department. You have improved the machinery in the STC to some extent in this regard, but not in the MMTC. You will have to do something to tone up the machinery in MMTC. You will notice, Sir, that only trading companies have made huge profits. It is not a real profit; it is a monopoly profit.

If I have the control over STC, I can show you a profit of Rs. 50 or Rs. 100 crores a year because it is a monopoly concern. There I dictate my price. Therefore, it is not real profit. On the contrary, under the shelter of that profit, a lot of corruption can take place. Therefore, the hon. Minister will have to remain alert and watchful because he is managing many trading concerns which are monopoly concerns and which behave in a monopolistic manner. He must restrain them from behaving in a monopolistic manner and he must not be guided by the profitability of the trading concerns.

With these words, I again sympathise with the hon. Minister because he has inherited the most confused state of affairs in the most important Ministry, namely Civil Supplies and Commerce. The Members of the Opposition are adding more and more confusion, but I hope he will take courage and act in a bold manner so that our management of the supply of scarce commodities like oil, cotton, cement and other things, is such that the public is satisfied.

बीजारी बाज़ार प्रकाश (बाह्य दिल्ली) : बादर साहब, यह निमिस्टी बहुत बड़ी निमिस्टी है, एक आटे की तरह से। इसमें कामसं भीर उच्चार्ह है तो ही ही, इसके पीछे दुम भी तरह कोलाप्रेशन भी जगा हुआ है। कोलाप्रेशन विपाटमेट भी इसमें जाविल है। जावल इस निमिस्टी के बारे में बिलकुल बातचीत होनी वह अपारत रकामसं भीर उच्चार्ह पर ही हीनी। जूँते पता नहीं कि हमारे आवरिकल मेल्डसं कोलाप्रेशन के बारे में भी कुछ जाह्नवे या नहीं : ऐसो कोलाप्रेशन के बारे में ही बोलने के लिए यहाँ बादा हुआ है। हालूक बीजारी बालं भी मैं कह देना चाहता हूँ।

यहां दोनों बातों का विषय थाया। यहां सबाल उठा कि मुक्त में योगोपती हो या न हो। अबर हो तो किस की योगोपती हो, कैसी योगोपती हो। यह भी कहा थया कि किस की योगोपती हो, स्टेट की योगोपती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अबर स्टेट की योगोपती हो तो कहा थया कि पहले उसकी बाराबियां दूर कर दी जानी चाहिए। लेकिन येरा कहना है यह है कि स्टेट का ज्यादा से ज्यादा दबाल, हिस्ता यहां की इंटर्स्ट्री और ट्रेड पर होना चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूँ कि उसकी एफीजियेंसी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि इसकी एफीजियेंसी नहीं बढ़ती है इसलिए इसको प्राइवेट सेक्टर के हथाले कर दिया जाए। अबर इस किस्म का सबाल कभी थाया तो मैं उन लोगों में हूँगा जो इसकी मुख्यालफत करेंगे। मैंने आज तक इसकी मुख्यालफत की है और आगे भी करता रहूँगा। भेरी राय में जहां-जहां भी मृत्युसिव है, जहां-जहां भी पासिवल हो, स्टेट सेक्टर को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके लिए कामर्स विनिस्ट्री के सम्बद्ध पूरा बन्धीकरण किया जाए।

इतना कह कर मैं यह भी कहूँगा कि यह जो विनिस्ट्री है—मैं कोई बहुत हिसाब-किताब नहीं जानता हूँ, कामर्स और इंटर्स्ट्री से येरा सम्बन्ध नहीं है—लेकिन जो कुछ भी सुनता हूँ, बाजारों में, ड्राइवर्स कम्प में, हर कहां तो सुने जाते हैं कि हिस्ताल में जो ज्वेक यानी है और आज भी उस ज्वेक यानी का अबर कोई जब्तीरा जाना हुआ है तो उसके लिए ये कहां कहा जा सकता है कि आज जब्तीरा इस विनिस्ट्री के बाइरे जाना हुआ है। इसको ठीक करने के लिए आपको हारीके नियमों पड़ेंगे। विस तरह से यार्डों में पुस्तक का डिपार्टमेंट एक बहालाम डिपार्टमेंट होता है, उसी तरह से नक्काशी घार इंटिंग में यह सब से बहालाम विनिस्ट्री है। इस बच्चह से इस में कफाई

की बड़ी सबूत बहरत है। मैं हाजर में बराबर यहां हूँ चार पाँच साल के प्रसंग को छोड़ कर। मैं हाजर में 1957 से हूँ। मैं मुक्त से देखता आ रहा हूँ। लेकिन यही तक कोई सुधार नहीं हुआ है। यहां तक हाजर है कि करप्जान दिन-ब-दिन बढ़ती जली रही है। पिछली हृकूमत ने घीर एमरजेंसी में हृकूमत ने क्या किया उसको आप छोड़ दें। जो हृकूमत है इस बक्त उसको इस भीज को देखना चाहिए। पहिले जबाहर लाल नेहरू के बाद और भी लाल बहादुर लालस्वी के बाद बहुत लोग जानते होंगे कि मैं जो भी हृकूमत रही है उसके बिलाफ सहता रहा हूँ। 1966-67 के बाद जो हृकूमत घाँट और जिस तरह से काम चला, मैं जानता था कि उसके नतीजे बहुत बराबर होंगे। जो हुआ वह आपके सामने है। उससे मैं ग्रलग रहा हूँ। मैं पाई साहब से इतिहास करता हूँ करप्जान को, एडमिनिस्ट्रेशन में कनप्यूशन को और जो उस में गन्दगी है उस सब को आपको दूर करना होगा। जो उसकी परम्पराएं बनी हुई हैं, प्रेसीडेंस बने हुए, डांचा बना हुआ है उनको आपको बदलना होगा। हम इसकाम ढाल दें कि उन्होंने क्या किया, इससे काम नहीं चलेगा। आज दुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत है, ठोस परिवर्तन करने की जरूरत है। समय मेरे पाल नहीं कि मैं सुलाल दे सकूँ। इनकामाली यांत्रि जो सामने हैं, बदबू यांत्रि जो सामने हैं तो महीने में जल्द हो जाएंगे और साल ऐड़ साल के बाद बहुत जोर से मांग लोग करने लगेंगे और पूछेंगे कि आपने क्या किया है और अब यह यही दिलेंस देने लगे जो पहली सरकारे दिया करती थीं तो यीह चलेगी नहीं। इतना कह कर आब मैं औषधीयेटिव मूवमेंट पर आता हूँ।

मैं इसको बूलकिस्मती समझता हूँ कि आरिया साहब का कोर्टीयेटिव से बहुत दूरांग सम्बन्ध रहा है, वह इच में बहुत बौद्धिक विवरण्यां सेते रहे हैं और इसको

एक आदर्श और अच्छी चीज़ मान कर वह बलते आ रहे हैं। मैं इसके बारे में कहने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी सम्बन्ध इससे चालीस साल पुराना है। गांवों की कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ से जे कर नेशनल कोओप्रेटिव भारगनाइजेशन तक से मेरा सम्बन्ध रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो कोओप्रेटिव्ज़ की हालत है उस में वे सिफ़र एक आफिशल मर्गीनरी बन कर रह गई हैं। कोओप्रेटिव नाम की कोई चीज़ इस बक्त हिन्दुस्तान में नहीं है। कानून इस तरह से बनाया गया कि जिस व्यक्ति को चाहें जिस भौके पर चाहें हटाया जा सकता है, तमाम बोईं आफ डायरेक्टर्ज़ को एक दम डिसमिस किया जा सकता है और दूसरा बोईं आफ डायरेक्टर्ज़ एप्पाइंट किया जा सकता है। किसी अफसर को लगा दें, किसी को हटा दें यह सिलसिला हो गया है। 1967 में जब श्री मुश्हमम्ब्यम साहब एप्रिकलचर मिनिस्टर बने तो उन्होंने यह सिलसिला शुरू किया। हमने बहुत प्रोटेस्ट किया। लकिन इसके बाद ऐसे-ऐसे कदम उठाए गए जिन से कोओप्रेटिव मूबमेंट एक आफिशल मूबमेंट बन कर रह गई। इससे तो अगर वह आफिशल डिपार्टमेंट रही तो आया बेहतर होता क्योंकि कम से कम उसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी तो होती। एक कारपोरेशन बने तो भी बेहतर था कम से कम बहर्नमेंट की डायरेक्ट जिम्मेदारी तो होती। कामज़ों पर और तकरीरों में तो कहा जाता था कि यह बालेंटरी पीपल्ज भारगनाइजेशन है इसमें हमारा कोई बहल नहीं है लेकिन असल में क्या होता है कि न वह चीज़ आफिशल रहती है और न ही नाम आफिशल रहती है। अब होता क्या है। जो फस्ट्रैटिव पालिटिशियज़ हैं उनको बहां बिठा दिया जाता है, कहाँ कोई हार गया तो उसको बिठा दिया जाता है और जिस अफसर की कही कोई

जरूर नहीं होती है, जो कहीं एडजस्ट न हो सकता हो उसको बहा भेज दिया जाता है। रिटायर्ड लोगों के लिए तो वह हैवन है, बहित है और उनको बहा भेज दिया जाता है। क्यों यह हालत हुई? आज जानते हैं कि कोओप्रेटिव एक बालेंटरी आर्गेनाइजेशन है। दुनिया में इसका डिवे-लपमेंट केसे हुआ इसको भी आज जानते हैं। जब कैपिटलिज़ खास तौर से यूरोप में बढ़ रहा था तो वहां से किसानों ने एक मूबमेंट बाड़ी की इस बढ़ते हुए कैपिटलिज़ का मुकाबला करने के लिए। एक बैलेंटरी भारगनाइजेशन डेवलप हुआ। तमाम बैस्टन यूरोप का ऐशीकल्चरल डेवलपमेंट कोओपरेटिव मूबमेंट के जरिए हुआ था। कहीं सरकारें बेस्टन योरप के अन्दर सरकार नहीं बना सकती जब तक कि ऐशीकल्चर और कोओपरेटिव से बील करने वाला मिनिस्टर न रहती हों। कोई फैसला प्राइवेज का नहीं हो सकता जिन कोओपरेटिव्ज़ की राय के यूँ एस० ए० जो पूँजीपति देख है वहाँ की जो आयल और हरल इलेक्ट्रिकल कोओपरेटिव्ज़ हैं, फटिलाइज़स को-ऑप-रेटिव्ज़ हैं वह अपने में इतनी बड़ी जाईंट है कि वह आज मुकाबला कर सकती है प्राइवेट सेक्टर के बड़े से बड़े जाईंट का और उन्होंने वह कायम की बढ़ते हुए मोनोपली कैपिटलिज़ के बिलाक। वहाँ के किसानों ने वह आर्गेनाइज़ की। इसी तरह से कन्यूमर मूबमेंट डैवलप हुआ। सप्लाई का सबाल बढ़ती हुई डैवलपमेंट इको-बोर्डी में उठा तो वहाँ के मजदूरों ने छोटी छोटी कंज्यूमर कोओपरेटिव सोसायटीज़ जुड़ की जो आज जाईंट कन्यूमर कोओपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और वह प्राइवेट कोट करती है, टम्स डिक्टेट करती है इकोबोर्डी के कपर न कि प्राइवेट ट्रेडर्स या कैपिटलिस्त्व। कम्युनिस्ट बंदीज़ के अन्वर, विद्याय रीलाया को छोड़कर, जितनी भी ऐशीकल्चर और कन्यूमर इकोबोर्डी है वह तमाम की जागरूक

कोआपरेटिव टाइप आफ आवेनाइजेशन वर बेस्ट है। इस लिए कोआपरेटिव की इम्पोर्ट्स आप समझ सकते हैं। यही कारण था कि जब पहली पांच सालों में बनी तो कोआपरेटिव को एक बुनियादी स्वातंत्र्यानिग कमीशन की रिपोर्ट में दिया गया और वह कहा गया कि कोआपरेटिव सोसायटी का हमारी इकोनोमी को बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा हिस्ता होगा। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि एक तरफ पर्लिक सैक्टर हो, प्राइवेट सैक्टर डेवलप करे और उन के बीच में कोआपरेटिव सैक्टर डेवलप हो और वह ज्यादा से ज्यादा फैलता जाय। यह पीलिसी डिसीजन लेने के बाद कोआपरेटिव और पंचायत को साधन माना गया देश की इकोनामी को डेवलप करने का।

सिविल सप्लाई का जहाँ तक प्रश्न है उम सिलसिले में शहरों की जहरत की तरफ ही ध्यान जाता है, गांवों के लोगों की जहरत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सिविल सप्लाई के लाभ को लेकर आज हम बड़े-बड़े शहरों तक ही कनफ़ाइन हैं, उसी के लिए कोआपरेटिव बना रहे हैं। और जितनी कंज्यूमर कोआपरेटिव्ह हैं वह सब प्राक्षिणियता रखते हैं, डायरेक्टर के बल नाम के लिए हैं। वह अपना भत्ता बनाने में लगे रहते हैं। तो जब कोआपरेटिव को इसी इम्पोर्टेस दी गई तो पीलिसी डिसीजन लिया गया और उस की रोजनी में जहाँ पहले मिनिस्टर कोआपरेटिव के बैयरमेन होते थे, नीन-माफिसियर उस के बैयरमेन बने थे। बैकुल भाई नेहता कमेटी बैठी जो इंवियन कोआप-रेटिव मूबर्मेंट के भास्त्र कावर रहे हैं, इस बात को हमारे मन्त्री जी घण्ठी तरह जानते हैं। उन की रिपोर्ट है, मिनिस्टर ने कमेटी अपाइंट की थी, उस की रिपोर्ट है डीलेन्ट्रालाइजेशन की। उस के अनुसार कामुक बदला जाया और

प्रावित में यह कहा गया कि तमाम कंट्रोल, फौरमेशन मुपरविजन, रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन, आडिट सब कोआपरेटिव तरीके पर कर दिया जाव। कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोआपरेटिव का डिपार्टमेंट भलग-भलग किए दिया गया, दोनों के संकेटरी भलग-भलग रखे गए। एक मिनिस्टर थे, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर भी काम करते थे। आकिसरी के एप्पाइन्टमेंट के बारे में यह तथ गिया गया कि यहाँ पर कोआपरेटिव डिपार्टमेंट सिंकें एक डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि यह आईडिया है, विचार है, संगठन है। इसलिए वहाँ ऐसे प्राक्षिणियत को रखा जाये, जो उससे बाकिक हों। जो ट्रेन होते थे, रजिस्ट्रार होते थे, नीचे काम करते थे, उनको संकेटरिएट में लाते थे। हम कोशिश करते थे कि ऐसे आदमी संकेटरिएट में आयें, जो 3 साल रजिस्ट्रार रह चुके हों, और रजिस्ट्रार ऐसा आदमी आये, जो काफी दिन फील्ड में काम कर चुका हो। लेकिन आज वह सब खत्म हो चुका है।

23 रुप्य.

मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के जो संकेटरी हैं, वह अच्छे आदमी होंगे, लेकिन मुझे है कि वह 1978 में रिटायर होने वाले हैं। आप बतायें कि वह इन्हें दिनों में क्या कर सकते हैं।

कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की सब बीजें डी-प्राक्षिणियलाइजेशन की दूसरी रिपोर्ट में भीजूद हैं। किस तरह से भलग डिपार्टमेंट कियेट किया गया, किस तरह के ला और रूल्ज बैन्ज किये गये, प्राक्षिणियर्स के मुतालिक फैलते किये गए थे तमाम बातें रिपोर्ट में भीजूद हैं। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में किसने आकिसर

[चौथी बहु प्रकाश]

हों। ईडिट सर्वे कमेटी की 1952 की रिपोर्ट के बाद सारे हिन्दुस्तान के को-आपरेटर्स आफिकियल्स, नान-आफिकियल्स, मिनिस्टर्स सब निले थे और मुझे पूरा व्यापार नहीं, वायद पटना में भीटिंग हुई थी। उस में यह फैसला हुआ था कि गवर्नरमेंट कितना रुपया को-आपरेटिव में इवं ट करती है, इसका सम्बन्ध नहीं है कि गवर्नरमेंट के डायरेक्टर्स उसमें कितने होंगे। यह तय कर दिया गया था कि कोई भी पोजीशन हो, 3 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होंगे किसी भी को-आपरेटिव आर्गेनाइजेशन के अन्दर। यह फैसला कम्प्रोमाइज फैसला था जिसमें प्लानिंग कमीशन के बेस्टर, गवर्नरमेंट आप इंडिया के मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, हिन्दुस्तान के को-आपरेटर्स शामिल थे। लेकिन आज तमाम के नमाम बोर्ड आप डायरेक्टर्स आफिकियल हो जाते हैं और आफिकियल यह कहते हैं कि चूंकि हमारा इन्वीस्ट्रैटिव व्यापार है, इसलिए हम व्यवस्था करेंगे, हम डायरेक्टर रखेंगे। किसी नान-को-आपरेटिव आर्गेनाइजेशन के मामले में एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का कुछ रुपया लगा हुआ था, तो हमने कहा कि रुपया वापिस कर दो मगर रुपया रखकर वह उस पर कट्टोल करना चाहता था। वह पालिसी गवर्नरमेंट की पहले नहीं थी, जो कि अब चेंज हो गई है। इसको देखना चाहिए।

एक बार नहीं, बार बार इस पर बहस हुई है कि लार्ज सोसाइटीज बननी चाहिए या स्माल सोसाइटीज बननी चाहिए, विलेज सोसाइटीज होनी चाहिए। यह ठीक है कि ईडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक लार्ज साइज सोसाइटीज बननी चाहिए, लेकिन बार-बार इस सबाल को उठाया गया। पं० जवाहरलाल जी के सामने भी सबाल आया, नेशनल ईवेन्युमेंट

कार्डिनल में भी सबाल उठाया गया, लेकिन बार-बार इसको टॉप डाइल निया गया। सन् 1952 से 1965 तक रिपोर्ट ईडिट के आफिकियल और मिनिस्टर्स की तरफ से इस सबाल को उठाया गया, लेकिन इसको एफिकियेसी के नाम पर रद्द कर दिया गया कि हम को-आपरेटिव प्रिसिपल्स को बत्त्य नहीं करना चाहते हैं। आज वह फैसला बदल दिया गया, इस बदल ताकि सोसाइटी आडॉर आफ दी रहे हैं। मेरे पास दरबारास्त आई है कि दिल्ली में भी 150 सोसाइटीज हैं, जब कि 40 सोसाइटीज रही ही चाहिए, कहा गया कि 40 में एडब्ल्यूस्ट कर दो। यह को-आपरेटिव की पालिसी और प्रिसिपल्स नहीं हैं।

इसलिए बेयरबैन साहब, मैं आपके उत्तरे निवेदन करूँगा कि इस पर नये हंग से सोचने की ज़रूरत है और वहीं जाने की ज़रूरत है, जहां सन् 1952 में हम थे। आप सबसे आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकार्ड्स कमीशन की रिपोर्ट निकालिये। आप एक बिकिंग सुप बैठाइए जो जल्दी से जल्दी सारी रिपोर्ट्स को स्टडी करे और आप के साथ बैठ कर इन तमाम बातों पर विचार करे कि आपेक्षा क्या हो, किस तरह से इस का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस तरह से को-आपरेटिव सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस में डायरेक्टर्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए, इससे रेग्लेमेंट और ना में क्या परिवर्तन होना चाहिए। इन तमाम बातों पर वह विचार करे यद्यों कि आप जानते हैं जनता पार्टी का जो भैनिफेस्टो है जिस के साथ आज मैं हूँ उस में सब से ज्यादा एम्प्रेसिस इस बात पर विचार गया है कि अब हम विलेज को और बड़ी जोग को बेस बना कर अपनी एकोनामी को बिल्ड करेंगे। कोई भी देश जाहे वह कम्पनीस्ट कट्टी हो जाहे कंपिलेटेस्ट कट्टी हो, विलेज को-आपरेटिव को जावदा नहीं हुए अपनी एकोनामी को बिल्ड नहीं कर सकता है।

राजिया ने कोलिन की लेकिन ऐडीकल्पर फ़िल्ड में बैठ रहे। उन्होंने बहुत कोशिक की लेकिन सफल नहीं हो सके। इस बास्ते किर से आप को इस में बहुत भेदभाव करती पढ़ती। मुझे बहुत बहुत बड़ी हीरानी होती है कि इसी बड़ी चिनिटी यह है, कैसे इस के साथ आप चाय कर सकते लेकिन मेरा लालब भी इस के साथ चाय नहीं है कि अगर कहाँ किसी और मिनिस्टर लालब के पास गवर्नरी से बड़ी गई तो यह काम कहीं और न पीछे चला जाय। इसलिए मैं आप से कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी ठोस कायदाहारी इस के ऊपर करेंगे। मैं बहुत उपरान्त में नहीं गया हालांकि मेरे पास इस समय सब कुछ है। लेकिन मैं अब केवल यही कहूँगा कि आप बहुत ठोस कदम उठाइए कोआपरेटिव को पुनर्जीवन देने के लिए। यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती अर्हिता पी० रामनेकर (बम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गोर से बिरोधी दल के माननीय सदस्य भी पाई साहब का भाषण सुना। सब सुनने के बाद मुझे एक अप्रेज़ी कहावत की याद आ गई —

It was like the pot calling the cattle black.

यह जो आजकल परिस्थिति हो रही है सीरियल्स-स्प्लाई की ओर एक्सपोर्ट की यह तो सब पिछले सालों से जो पिछला कारोबार चल रहा था उस के कारण है। उन्होंने इसे कबूल किया है और कहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है और हमें मालूम है दो साल से स्टीम बन कर के रखी थी, अभी भी कोका मिला है तो बहुत जोर से स्टीम बाहर आने लगती है। उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात बताई कि आगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम (स देश में) ऐरिक हो जाएंगे, हमारा सर्वानाश हो जायगा। मैं इस चीज़ को नहीं मानती।

उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, मैं शीर किसी के बारे में अपोक नहीं करनी लेकिन एक उदाहरण उन्होंने दिया कि अपर चरण कांट्रीज में 30 रुपये किलो चावल बारीबो हैं तो हमारे देश से चावल जाना चाहिए। वही पुराना तरीका था कि अपने देश के लोगों को भूले रख कर चावल प्राप्ति भीजें बाहर भेजी जाती थीं जिस के लिए हमारी भारतीयों को बेलना उठाना पड़ा था, यह उन्हें भूल नहीं जाना चाहिए।

मैं दो ही तीन विसालें देना चाहती हूँ। उन्होंने एक बात रखी थी कि हमारी कम व्यक्ति कम हो रही है। लेकिन यह एक विशेष सकिल है। कम व्यक्ति कम हो रही है, हम बारीद नहीं सकते इसलिए परदेश में भेजना, यह बात तो बल्त है। अपनी कम व्यक्ति हम बड़ा सकते हैं। लेकिन आज जो हमारी एकोनामी परदेश से आने वाले पैसों के ऊपर निर्भर रहती है इसलिए ज्यादा बोक्सा हमारे लिये पड़ता है और हमें बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं वह सबसिडाइज़ रेट पर करनी पड़ती हैं। हमें उस में नुकसान होता है। हमें कारेन एड लेनी है लेकिन जिस में कोई गत नहीं हो। जैसे हम देखते हैं कि सोशलिस्ट कान्ट्रीज के साथ जो हमारा ट्रेड है उस में कांई स्ट्रिंग नहीं है। लेकिन जो बैस्टेन क द्वीप से हमारा ट्रेड है, हम उन से जो पैसा कर्बं दे हैं में लेते हैं, उस में बहुत सारी घरें ऐसी होती हैं जिन का दबाव हमारी इकानमी पर, हमारे आर्थिक दांबे पर पड़ता है। इसी लिये हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जिन की जहरत हमारे देश में हैं, जैसे बहुत सारा-मैट्रीयल, बहु भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमें अपने देश को बचाना है तो इस तरह का जो ढांचा है उस को हमें बदलना चाहिए। जब तक यह नहीं बदलेगा, जब तक हम फोरें-कर्जी पर निर्भर रहेंगे, तब तक यह विशेष

[श्रीमती अहिल्या पी० रामनेकर]

सर्किल चलता रहेगा और इस देश में सुधार होने वाला नहीं है।

दिरोध पक्ष के मानवीय सदस्य ने कहा कि यह सरकार एक्सपोर्ट बहुत कम कर रही है—ऐसी बात नहीं है। मैं एक ही मिसाल आप को देना चाहती हूँ—स्टेनलेस स्टील, एम्ब्रायडर्ड फैब्रिक्स, हैण्ड निटिंग मशीन्ज मार्फि का टारगेट 1976-77 में 500 लाख रुपए था, जिस को उन्होंने 347 लाख रुपए तक पूरा किया, लेकिन इस सरकार ने इस का टारगेट 1000 लाख रखा है, इस के मायने हैं कि इस सरकार ने दुगुना टारगेट रखा है। इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है, बल्कि हमारे फाइनेंस मिलिस्टर ने एक्सपोर्ट के बारे में 6 हजार करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। इस लिए मेरा कहना है कि कई चीजों का एक्सपोर्ट कम होना चाहिए, इस के कम करने से हमारे देश को कोई नुस्खान होने वाला नहीं है।

हमारे यहां आज बहुत सी फैक्ट्रीज बन्द हैं, जूट मिलें बन्द हैं, टैक्सटाइल मिलें बन्द हैं और जो टैक्सटाइल मिल आप के हाथ में हैं उन का कारोबार तो बहुत ही बुरे तरीके से चल रहा है। अभी एक बेस्टने इण्डिया मिल आप ने बम्बई में अपने हाथ में सी है। 6 मिलें अभी और बन्द होने वाली हैं। नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के हाथ में जो भी कारोबार जाता है, ठीक ठंग से नहीं चलता है। सब से पहले तो मैं यह बात ही हूँ कि इस कारपोरेशन के पश्चानल को बदलना चाहिए। मुझे मालूम नहीं किस आधार पर, किस मैरिट पर उस में लोगों को लिया गया है, कोई रिस्तेदारी के कारण आए हूँगे कोई दूसरे कारणों से आय होंगे—इस लिए, इस को पूरा बदलने की जरूरत है।

अभी कोहिनूर मिल आप ने 15 करोड़ रुपए देने के बाद अपने काढ़ में सी। पहला काम बहां पर क्या हुआ? जो हमारे बहां कॉम्प्रेस के फैजीबैट थे उन के 6 लाख रुपये के बैनर बहां पर तैयार किये गए, टैक्सटाइल का कपड़ा तैयार नहीं हुआ, बैनर तैयार हुए। चूंकि चुनाव में जनता पार्टी ने उस को डीकीट दिया था, इसलिए यद्य पह अंदी बन गए हैं। बहां मजदूरों ने एक महीना काम किया, प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन उस के बावजूद भी बहां के बैनरजेन्ट और नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन ने, जो उस में अधीक्षीदार है, मजदूरों को पगार नहीं दी। अब एक महीना काम करन के बाद भी मजदूरों को पगार नहीं मिलती है, तो यह कारपोरेशन क्या करती है मेरा ऐसा कहना है कि यह कारपोरेशन प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में, माल बेचने के बारे में अच्छे तरीके से काम नहीं करती है, उसमें करप्शन बहुत चलती है। अभी टाहम बहुत कम है, बरतन मेरे पास ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिन में मैं बहां चल रही करप्शन को बता सकती हूँ। मेरा यह कहना है कि आप पूरी टैक्सटाइल इण्डस्ट्री को नेशनलाइज कीजिए, बरतन 15 में सुधार होने वाला नहीं है। आप यह देखिए कि मिलें तिक क्यों होती हैं? ऐसी बात नहीं है कि उन की प्रोडक्शन बिक नहीं सकती है, उन के बैनरजेन्ट में इतनी गडबड होती है जिस की बजह से वे तिक हो जाती हैं। हम वे इस के बारे में जो कमेटी बनाई थी, उस की रिपोर्ट है कि उन के कारोबार में गडबड होने की बजह से वे बन्द हो जाती हैं। इसलिए मेरा अंदी महोदय से कहना है—टैक्सटाइल का जाता आप के हाथ में है, यदि आप इस में सुधार जाना चाहते हैं तो आप इस के नेशनलाइजेशन के बारे में तय करें और जब तक तय नहीं कर सकते हैं, तब तक आप को टैक्सटाइल कारपोरेशन की रक्खा के बारे में सोचना चाहिए, उस में परिवर्तन लाना चाहिए।

मेरे पास टाइम बोडा है, जिसलए भ्रम में सिविल सप्लाइज के ऊपर जाती हूँ। सिविल सप्लाई का जहाँ तक सबाल है, मैं यह देखती हूँ कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अभी भी बहुत से लोगों को कीमतें बढ़ाने का ख्याल आता रहता है और इतनी जेनवरी देने के बाद भी उग्हाने आशी कोई सबक नहीं सीधा है। मंत्री महोदय ने जो रिपोर्ट में फीगर्स दी है वे जेनवरी तक की फीगर्स हैं लेकिन जेनवरी के बाद भी प्राइसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, यह चीज़ ध्यान से रखनी चाहिए। जेनवरी से अप्रैल तक इतनी ज्यादा प्राइसेज बढ़ गई हैं जिन का कोई हिसाब नहीं है महाराष्ट्र के जो कीमतें हैं वे भेरे द्वारा में हैं। और मैं उन को आप के सामने रखना चाहती हूँ। चावल की कीमत 25 फीसदी बढ़ गई है, तूर दाल की कीमत 35 से 90 प्रतिशत बढ़ गई है। इतनी कीमत पहले कभी बढ़ती हुई नहीं देखी थी। प्राउण्डनट आयल की कीमत तो 112 फीसदी बढ़ गई है। यह अप्रैल तक की फीगर है। कोकोनाट आयल की 32 फी सदी, बासमती की 64 फीसदी और मसूर को 62 फीसदी कीमतें बढ़ गई हैं।

इस महीने की 7^{वीं} तारीख को आपने एक बीटिंग बुलाई थी, जिस में ट्रेडर्स और इण्डस्ट्रियलिस्ट्स आए थे और आपने उन से अपील की थी कि उनको खुद कीमत कम करनी चाहिए लेकिन भुजे^१ ऐसा लगता है कि अभी तक उन्होंने उस अपील पर रेस्पोन्ड नहीं किया है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि वे कीमतें कम नहीं करेंगे। उनको अपर सबक लिखाना है, तो अपील करने से कुछ नहीं होगी। मैं आप के सामने प्राउण्डनट आयल की नियाल रखना चाहती हूँ। पिछली गवर्नरेट ने इसके लिए पार साल^२ 520 करोड़ रुपए के लाइसेंस दिए थे, तेल बाहर से लाने के लिए लेकिन बाहर से वे केवल 60

करोड़ रुपए का तेल लाए और बाकी 440 करोड़ रुपए का तेल इन्टरेशनल बाकेट में बेच दिया। इससे जो उन्होंने पैसा कमाया है, उस के लिए सिफ़र बानिंग ही दे दी है और यह कह दिया है कि हम तुम्हारे लाइसेंस रद्द कर देंगे। यह बानिंग काफी नहीं है। अगर आप को कुछ करता ही है तो जो लाइसेंस दिये गये हैं और जो तेल बाहर बेच कर इन्होंने पैसा कमाया है, वह सरकारी ताबे में लेना चाहिये और दूसरा तेल खारीदने में इस्तेमाल करता चाहिये, नहीं तो वे यह कहंगे कि इस साल नहीं तो अगले साल हम लाइसेंस ले लेंगे। गोदरेज साहब जो महाराष्ट्र में आयल के सब से बड़े बोनोपोलिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला है कि तेल की कमी है और लाइसेंस नहीं मिलता है। मैं इन बात का स्वागत करती हूँ कि आप ने इस लोगों को लाइसेंस नहीं दिया है और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के धू^३ आप को तेल खारीदने का लाइसेंस देना चाहिये जिससे काला बाजारी न हो। गोदरेज साहब बहुत बड़े आदमी हैं और उन के पास पैसे की ताकत है जो सब कुछ खारीद सकती है लेकिन मुझे विश्वास है कि वह इस गवर्नरेट को नहीं खारीद सकेगी और आप एस० टी० सी० के धू^४ ही तेल बंगारेंगे।

तेल के बारे में एक बात और मुझे कही है। मैं देखती हूँ कि गवर्नरेट ने यह तथ किया है कि आउ ड सीड़स 9 करोड़ रुपये का वह एक्सपोर्ट करेगी और बाहर से बेजिटेबल आयल इम्पोर्ट करेगी। यह भेरी समझ में नहीं आता है। आप बेजिटेबल आयल का इम्पोर्ट कर रहे हैं। उस से आप को एक करोड़ रुपये की इम्पोर्ट टैक्टी मिलने वाली है। आप प्राउण्डनट एक्सपोर्ट करते हैं और बेजिटेबल आयल इम्पोर्ट करते हैं, यह नहीं होना चाहिये।

[श्रीमती अहिल्या पी. राणेकर]

इसरे शूगर के बारे में जो हमारी एक्सपोर्ट पासिस्ती है उस के बारे में में कहा चाहती हूँ। इस के बारे में बेता कहना यह है कि गने की क्षमता करने की हमारी जो ताकत है उस के मुताबिक 1975 में हमारे यहाँ 6.1 किलोड्राम प्रति व्यक्ति बष्ट की ताकत थी। वह ताकत 76-77 में बट गयी और हमारे देश में कंजम्पशन की ताकत बट गयी। आप किर भी शूगर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वह भी सबसीडाइज्ड रेट्स पर। हमारे यहाँ शूगर चार रुपये किलो मिलता है और वहाँ आप विदेशों में इसे कम कीमत पर बेच रहे हैं। यहाँ तो आप इसे सबसीडाइज्ड नहीं करते और बाहर भेजने में यह करते हैं। हिन्दुस्तान में जब भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो कीमतें कम हो जाती हैं। हमारे यहाँ शूगर का प्रोडक्शन अब जितना हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी शूगर की कीमत कम नहीं हो रही। इस सब के बावजूद किसान को कुछ नहीं मिलता, कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलता है। हमारे जो बड़े बड़े कारखानेदार हैं, मिल वाले हैं वे सारा मूनाफा ले जाते हैं न तो मजदूर को कुछ मिलता है और न कंज्यूमर को कुछ मिलता है। इस को आप को देखना चाहिये।

हमारी जहरत की 'जो चीजें हैं, जैसे प्याज है इस को गरीब से गरीब आदमी खाता है। प्याज भी आप एक्सपोर्ट करने समझते हैं। अब शायद आप ने इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। इस संबंध में आप से बड़े बड़े आदमियों का एक डेंटेशन भी मिला था जिसन मांग की थी कि इसका एक्सपोर्ट खोल दिया जाये। बड़े बड़े लोग प्याज किसान से 6 सौ रुपये टन में खरीदते हैं और 24 सौ रुपये टन में

उसे बेचते हैं। इसके बाबने मूँह है कि किसान और कंज्यूमर को कुछ दरों मिलता, सब बीच बाले लोग जा जाते हैं। आप के एक्सपोर्ट करने से प्याज की 6.4 परसेट प्राइसिंग बढ़ जाती है। प्याज में दलाल लोग इताली जा जाते हैं और किसान मरता है, कंज्यूमर भी मरता है। अब आप को इसका एक्सपोर्ट करना भी पड़े तो इसे स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के जरिये से करना चाहिये।

एक बात मूँह यह कहती है कि जो यह कहा जाता है कि मजदूरों को पैसा देने से प्राइसिंग बढ़ जाती है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि ये साल ही आप ने देखा कि आप ने मजदूरों का 15 सौ करोड़ रुपया बेज कीज करके रख लिया फिर भी प्राइसिंग कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही गई इसलिये मैं बहना चाहती हूँ कि मजदूरों की आमदनी और प्राइसिंग में कोई संबंध नहीं है। मजदूर तो गरीब ही होता जा रहा है। आज भी 75 परसेट से ज्यादा लोग दरिद्रता की रेखा से नीचे हैं। इसलिए हम को यह नहीं करना चाहिये। कम से कम उन्हें खाना तो मिलना चाहिये, वो टाइम रोटी तो मिलनी चाहिये।

चीनी आप शहरों में देते हैं लेकिन देहातों में नहीं देते हैं भेरी मांग है कि देहातों में चीनी देने की आप को व्यवस्था करनी चाहिये और वहाँ भी लोगों की सस्ती चीनी मिलनी चाहिये, कम कीमत पर चीनी मिलनी चाहिये।

आप ने कीमते कम करने की जो इच्छा व्यक्त की है वह बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आप को बतलाना चाहती हूँ कि देश के व्यापारियों पर नेरा चिल्कुल विवाद नहीं है। सभगढ़रों पर भी आप को रोक लगानी चाहिये।

श्रीसर्वी की तरफ से ही यही कहना चाहता हूँ कि हम शर्म को समय देने के लिये तैयार हैं। एक दो अद्वितीय में अगर कीमतें कम हो जाये तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन अगर कीमतें कम नहीं होती तो फिर हमें बैंक उठाना पड़ेगा, इतना ही इचारा दे कर ही समाप्त करती हूँ।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : Mr. Mohan Dharia is wedded to so many subjects on commerce. I know he is a competent Minister. But he can't be loaded with various subjects handled by various ministries in the previous Government.

The previous Government did certain exercises on export promotion and they brought about some successes also. We should not discredit anything on political considerations. My friend Mr. Pai has also made it clear. We should see to the growth of our national economy and export promotion. Mr. Mohan Dharia could do better and he could continue with the previous performance. The export-promotion performance of the previous government could be continued by the present Ministry, which has come to power 3 months ago. We must see that the export promotion efforts become successful.

The explanatory memorandum of the Central Budget for 1977-78 was released in the preceding session of Parliament. This was given before the final budget was introduced in this session. What we see is that export subsidies have been increased by substantial amounts. Before the budget is presented substantial amounts have been raised. Why? Export subsidy will ultimately create a burden on Indian economy. In 1977-78 expenditure on export promotion has risen by 73.6 percent. We spent Rs. 41.2 crores on export promotion in the financial year 1976-77. This figure has increased to Rs. 295.9 crores in 1977-78, the present budget. They are proposing to spend Rs. 303 crores on export promotion but the total allocation in the current financial year is Rs. 288 crores or 93% of the total. It is earmarked for export promotion. Rs. 161 crores or 57% is to be given as cash incentive to exporters. Who are those exporters? We know. Rs. 30 crores is set aside for giving subsidy on sugar export alone.

We are spending a huge sum of money on subsidy on fairs and exhibitions. It may be stated that they are relevant. But why a lavish spending on the fairs and

exhibitions is necessary? You know, that the subsidy given to the products being exported by the exporters is very high. I believe that cash assistance given has not been taken note of while giving direct subsidy to certain items. To me it appears that there is no justification whatsoever for giving such a huge subsidy to exporters for so long. But, that is what we have been doing so far.

At least, I hope the present ministry will shut out a certain subsidy that is given to exporters under the export promotion scheme. The budget does not reflect that at all. We therefore feel that the present Government should see to it that the Indian consumers are not allowed to bear that burden of such a huge subsidy that is given to exporters in their export promotion. For any price rise for this sort of an arrangement, the domestic buyers have to pay for some of their products. My hon. friend has already quoted certain facts about it.

Take for example sugar export. Why should a foreign buyer pay less for our sugar as compared to the Indian buyers? I do not see any justification at all in this. Why should we pay such an unreasonable subsidy to our foreign buyers at all? My point is that the consumer items must be removed completely from the payment of a high subsidy for export promotion. The other point is that the surplus capacity should be made use of to find foreign market for their products. I do not mind there a limited subsidy being allowed. We cannot get the goodwill from the other countries even if we allow subsidy on unproductive items which are economically as well as politically not viable.

As far as subsidy on export items is concerned, our Government should take certain steps to ban paying such a high subsidy on such items. They should make an exercise in this regard to see that the export promotion is done keeping in view the Indian economy in its proper perspective.

Coming now to export houses, there are certain big consumer cooperative houses that are operating in this country. That may be the reason why we find a lot of provision being made in this budget for the subsidy on exports. What should be the new strategy that we have to adopt? A lot of exercise has been done by the previous Government in this regard. Since Shri Mohan Dharia was also in the previous Government, he should not avoid the responsibility. Since he was controlling at a certain point of time, being in charge of this ministry, he should not escape from that re-

[Shri K. Lakshmi]

ponsibility. Besides that, he was also in the Planning Commission and he was in charge of planning of this country. He had not been able to explore the possibility of finding markets where we can send our goods and comfortably capture the market. I do not think we have made any effort in that regard. I only want to emphasise that a genuine effort must be made by him to find out markets in the Oil Exporting countries—OPEC—where we can explore the possibility for finding markets for our goods. We can even try; that in the Middle-East Muslim countries as also in European countries.

The previous Government had made several efforts for the past three years to export to these countries. That should not be discouraged. Though a new Government has come into being at the Centre, Shri Dharia was also there in the previous Government. Of course, I see the point that most of the Members of this House are quite new. You should take steps to see that there is an increasing sale of Indian goods in other countries also such as Iran, Saudi Arabia, Kuwait and so on and so forth.

In this connection, let me give you information to convince you of the impressive import requirements of these countries from here having been increased.

But the situation has been exploited by the western countries to sell their goods there. Britain, Italy, France and USA took advantage of this opportunity more especially. India should take advantage of the vast opportunities that are available in the OPEC countries. Greater efforts should be made to export in these countries so as to cut down the opportunities being utilised by the western countries.

I do not know the mind of the present government about nationalisation but both the public sector and the private sector are operating in our country. Now, what is our Trade Development Authority doing these days? It is busy visiting more countries but not probing new markets for our items. In the OPEC countries we should have commercial intelligence. Because of lack of commercial intelligence, in the OPEC countries we find failure on the front of joint ventures. Joint ventures in the OPEC countries on a scientific basis is very necessary and the new government must exercise its mind in this respect.

Sir, yesterday I received a telegram from Karnataka. In Karnataka there are small growers of onion. In Karnataka

we have successfully brought about land reforms and small cultivators there have taken to large-scale growing of onion. Now, what has happened? Sri Lanka was importing lot of onion from our country. Now, the export of onion is stopped. Prices have fallen. People are not getting the price. Onion is a perishable item. You have to help these poor farmers. The farmers are crying and I received a number of telegrams. The export of onion to the neighbouring countries like Sri Lanka etc. should be allowed. There should be organised co-operatives. It does not matter even if it is organised through other agencies. Now, the previous Government had created a branch in the S.T.C. to look into the various problems. It is because we had made certain exercise on that. In so far as Southern States are concerned, we have been exporting raw materials like hides and skins. But we are not getting good prices for them. Why cannot an organised public sector unit be created for this purpose so that it may collect the raw hides and skins from the various parts of Southern States and see that the finished goods are exported, because we have to pay a fantastic price for the finished goods even though we have got plenty of raw material in our country?

Sir, your Ministry is doing the distribution work through the co-operative system. The cooperative system has got deep-roots in our country. But it is not working properly; it is not functioning properly. In place of cooperative system, cooperative capitalism has started working in the name of cooperatives. Corruption in the co-operative field is rampant. The previous Government had appointed an Enquiry Commission to go into the functioning of the co-operative societies in Tamil Nadu. In the field of co-operatives, the work is not handled properly and a real co-operative spirit is to be instilled in the minds of the people. Wherever loopholes are there in the legislation, they have to be plugged and there is a need for the entire reorganisation and revamping of co-operative movement in our country. Recently there was a Conference of Asian Countries on the subject of Co-operative Credit and Financial Management, held in Madras. The Conference had made deliberations and some conclusions were drawn. Members from various parts of Asian countries participated including India, Sri Lanka, Thailand and Bangladesh. One of the recommendations made in the Conference was that credit facilities should be given through the co-operative machinery and provincial co-operatives. Co-operative capitalism should be avoided. The man-

gerial talent and training in rural sector are absent. There is a need for streamlining the co-operative machinery so that the poor farmers get benefit. In that respect, the Sivaraman Committee has also made some recommendations. I hope the hon. Minister is aware that there should be a co-operative spirit among the people and its growth cannot be judged by its size or the number of Members it has on its roll. It should be judged by the services it affords to the weaker sections, poorer sections and vulnerable sections of the people. Out of Rs. 170 crores provided for this purpose, they could not even handle a sum of Rs. 70 crores. It means that 2/3 of the co-operatives system is functioning in a sub-standard manner. Therefore reorganisation of the co-operative system from the bottom is very necessary. Recently, a conference for co-operative movement was held at the national level in which you would have participated. But, Sir, I may bring to your kind notice one fact, that is, that the Co-operative Unions, Marketing Federation, Sugarcane co-operative unions, etc. have all got vested interests. A spirit of co-operative capitalism has developed in our country. Unless such vested interests are broken and other measures are taken, co-operatives will get into the hands of vested interests and will not benefit common people. The rural people should be helped by Cooperatives and so the co-operative movement in the country has to be reorganised. The present government says that there is going to be no witch-hunt; with all that every day they are denigrating the previous government by name. It does not matter; we can take it and stand it for some time; but not for all times; we cannot tolerate it. What has the Janata party done to the poor? They are doing political gimmicks and appeals. The Prime Minister appeals to the traders, hoarders, blackmarketeers and smugglers to hold the price line. Have they heeded your advice? Will they? Never. They want to hold the country to ransom; they increase the price. Still you say you do not require any law. You criticise the excesses committed during the emergency but you do not say one good word about the discipline that was found in those days. My friend Brahmananda Reddy was making a statement. Do you think that by sprinkling ganga waters on hoarders and black marketeers you can make them take a philosophical attitude? The price of groundnut oil has risen from Rs. 9 to 10 and from Rs. 10 to 11. Similarly the price of sugar has increased; dalda price has risen. You cannot control any of these things. What about cement? You cannot say a word about nationalisation of sugar mills in U.P. which was demanded by 350 Members of Parliament in the previous regime. Is this government

going to nationalise those mills and remove this industry from the stranglehold of vested interest in U.P.?

What has been the decision of the government about establishment of a coconut board in Karnataka. Karnataka is one of the biggest producers of coconut. It is grown in a number of places in my constituency. We have been urging the government to set up a coconut board so that the grower could get a proper price. Mr. Dharia has got vast experience. He must forget that he is in the Janata party and see that socialist measures are taken. Economic price should be given to the growers. It is not enough to have political freedom; it is necessary to ensure economic freedom to the people. I earnestly appeal to him to see that a remunerative price is paid to the grower and that corruption in all walks of life is wiped out soon.

श्री परमानन्द शेखिलजीवाला : (खंडवा)
माननीय सभापति महोदय, सब से प्रारम्भ में मैं यह निवेदन कर दूँ कि उपमोक्षाओं की अनेक समस्याएँ हैं और इन समस्याओं के स्वरूप और आकार के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और मैं समझता हूँ कि उन समस्याओं के स्वरूप और आकार के बारे में कोई विशेष चर्चा करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। प्रत्यन् यह है कि इन समस्याओं का निराकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं और करना चाहते हैं।

श्रीमन् मेदा निवेदन यह है कि उपमोक्षाओं को उचित मूल्यों पर बस्तुयें प्राप्त हो सके, इस के लिये सन् 1966 में एक नीति लिखित की गई थी और वह यह थी कि उपमोक्षाओं को सहकारी उपमोक्षा समितियों के माध्यम से उचित मूल्यों पर जीवन की चीजें प्राप्त हों। श्रीमन् हम इस बात पर विचार करें कि सन् 1966 से विशेषकर पाकिस्तान के आक्रमण के पश्चात् उपमोक्षाओं की समस्याओं को क्या हम सहकारी समितियों के माध्यम से सुलझा पायें हैं। मैं निवेदन करता छालूंगा कि वित्तीक 3-2-77 के नेतृत्व में सरकारी सूची के द्वारा

[श्री परमानन्द शोबिंदजोब । सा]

से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और उस में यह बताया गया है कि वे जो उपभोक्ता सहकारी समितियों में से 40 परसेन्ट डोमेंट है और इन समितियों में से अधिकांश की हालत बहुत पतली है, बहुत बीक है। मेरा निवेदन यह है कि अब वह समय पा गया है जब हम सोगों को इस बात को मान लेना चाहिये कि इन कंज्यूमर्स कंप्लायरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से हम उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुलझा नहीं पाये हैं।

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि हम इस बात पर विचार करें कि आखिर ये सहकारी समितियों क्यों फेल हुईं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन समितियों की असफलता का बहुत बड़ा कारण यह हम को हड़ाता है, तो किसी भी गांव में ले जायें, वहां पर बजरंगबली के मन्दिर को देखें। उस को देखने से मैं समझता हूँ कि शाप को कारण समझ में आ जायगा। मन्दिर का निर्माण करने के लिये गांवों के सोग इकट्ठे हो जाते हैं और मन्दिर बना देते हैं लेकिन मन्दिर के बनने के बाद उस की व्यवस्था के लिये आपस में झगड़ पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि इन सहकारी समितियों की असफलता का बहुत बड़ा कारण यही है, हमारी इनहॉरेन्ट बीकेनेस हमारी इनहॉरेन्ट क्रेस्टरस्टिक हम भारतीय सोग, दस सोग मिल कर किसी औज का निर्माण तो कर लेकिन बाद में हम उसे औज से छला नहीं सकते, छला नहीं पाते और आपस में अचहना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि इन सहकारी समितियों के बारे में एक बार फिर से हमें प्रछंडी तरह से सोच लेना चाहिये कि वे भारत के टेलरेंमेंट की, भारत के भानस को सूट करती है या नहीं?

श्रीमन्: जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात माननीय मंत्री जी ने जनता दुकानें बोलने का प्रस्ताव किया है। हम सब लोग जानते हैं कि आपात काल के दौरान बसों के ऊपर, ट्रक्स के ऊपर ईंदिरा जी से सम्बंधित नारे लिखे जाते थे। निर्बाचनों के तुरन्त पश्चात जब जनता पार्टी की विजय हुई तो उन्हीं बसों और ट्रक्स के ऊपर ईंदिरा का नाम हटा कर जनता नाम के नारे लिखे जा रहे हैं। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या हम सहकारी समितियों, उपभोक्ता समितियों से उन का नाम हटा कर जनता बोर्ड लगाने जा रहे हैं? श्रीमन् कहा जाता है कि मुम्मी बोर्डिंग्स में दुकानें खुलेंगी, गांवों के अन्दर दुकानें खुलेंगी। श्रीमन्, मैं आपको घटना एक अनुभव बताता हूँ। हमारे 14 नेशनलाइज्ड बैंकों में एक नेशनलाइज्ड बैंक बैंक आफ ईंदिया है। इस के प्रधिकारियों के दिवाल में आपा कि भांव के अन्दर गांवी तकियों वाली आवाज़ आती जाते। उन्हें आवाजें खोल दी। मेरे निर्बाचन लेने में भी बादी तकिये आता बैंक खुला। जब वह खुला, उस समय मैं जेल में था। जब मैं जेल से बाहर आया तो देखने वाया। मैंने वहाँ के अधिकारी से पूछा कि रात के बात्ह बजे बाहर आप के पास कोई भांव रुपया उड़ाए गए थे या नहीं जानता। श्रीमन्, इसी तरह मैं जानना चाहता हूँ कि जो वे जनता दुकानें खुलेंगी क्या उन पर आठ दिन, पचाह दिन के फैटिट पर भाल निल सकेंगा या नहीं? जो लोग तुरन्त ऐसा नहीं दे पर्याप्त, क्या उन को भी भाल निल सकेंगा या नहीं? श्रीमन्, जेल बाहर है तो उसपर विशेष विकास किया जाना है।

अम्ब 12 रुपये, 13 रुपये किलो है। किलो तुकानदार चार बाजे का, बाठ आने का खेल देता है और उसके लिये वह 15 दिन और एक महीने छहरता है। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि बक्से का एक्सप्लाइटेशन नहीं होना चाहिए यगर बास्टर में जो बल्टुस्टिल है उसको भी हीमें देखना पड़ेगा। वह मजदूर के पास पैसा ही नहीं है कि वह नकद सामान ले सके। आपातकाल के दीरान बेरे खेल में अवस्था की गई कि तेल कंजयूबर को एक या पीन किलो दिया जाए। यह अवस्था करने से पहले वह भूल गये कि एक किलो तेल या पीन किलो तेल वह अकेला ले सकता है या नहीं। इसलिये श्रीमन् मैं चाहता हूँ कि इन बनता तुकानों को खोलने से पहले यंचीरता से सोचा जाना चाहिये कि जिन लोगों के लिये यह तुकानें खोली जा रही हैं उनकी क्या गति क्या है।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। माननीय पाई साहब के आवण का जो आविर्धि हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा कि कल तक हम कंसारियों के प्रत्येक कार्ब का बचाव करते थे, आज आप कर रहे हैं। मैं उससे लहसुत हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कहना कि वे भी बनता तुकानें खोलते समय इसकी दृष्टि में रखें कि वह नीकरताही का शिकार न हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज सरकार एक दैत्याकार स्वकंप बारज करती रही जा रही है। सरकार का हमारे जीवन के किन किन घंटों में प्रवृत्त हो चुका है इसका आवध जीवाजा नहीं भगाया जा सकता है और वह एक दूसरी है जो व्यापक है। सरकार का बनता

के दैनिक जीवन में बाल दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। इसको किस तरह से कम किया जाए उस की बच्ची यहां संभव नहीं है।

24 Hrs.

जबीं जो समस्या है वह यह है कि एक डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट में, एक विभाग और दूसरे विभाग में तालमेल नहीं है। एक ही बस्तु के बारे में किस प्रकार से नियंत्रण लिया जाता है, इस की एक मिसाल में देता चाहता हूँ। मैं तम्बाकू को लेता हूँ। तम्बाकू बोर्ड की स्थापना आपने कर रखी है। आपके मंत्रालय के प्रत्यंत यह आता है। कुछ दिन पहले हैदराबाद में तम्बाकू के नियंत्रण के बारे में सम्मेलन हुआ था। इस बोर्ड का सारा ध्यान इसी बात की ओर है कि यहां से बीड़ी और सिगरेट का ज्यादा ज्यादा नियंत्रित हो, तम्बाकू का ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण संसार के घन्दर भारतीय भूल के लालों लोग फैले हुए हैं। आप प्रसन्न करें या न करें। कितने ही लोग जहां, किमाम आदि जाते हैं। तम्बाकू भारतीय जीवन का आवश्यक अंग बन चुका है। तम्बाकू खनोंको प्रकार से बाया जाता है, जर्दे के क्षम में बाया जाता है, किमाम के क्षम में बाया जाता है। ज्यालों भारतीय जो बाहर रहते हैं उन में से भी काफी लोग तम्बाकू खाने के आदी हैं जैसे आप और हम हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह किनिष्ठ तम्बाकू जा सकता है या नहीं क्या इस बात की ओर ध्यान देना हमारा काम नहीं है?

जो तम्बाकू हमें बाहर भेजना चाहिये उसके आवार के बारे में जापर वह परिस्थिति निमित्त ही रही है कि यह उच्चों ही क्षमता ही जावे। ऐसे यात सब वह विवेशन

आप फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 है। इसके तहत नियम बने हुए हैं। इसके नियम 28 में कोलतार डाइज के रंग के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। कौन कौन से कोलतार डाइज के कलर यूज किये जा सकते हैं नियम 29 के अन्दर यह बताया गया है, किन किन खाद्यों के अन्दर इनका उपयोग किया जा सकता है यह बताया गया है। यह कलर आइस क्रीम में उपयोग किया जा सकता है, कुलफी, दूध में, कोका कोला में, अन्य प्रकार की साफ्ट ड्रिक्स में उपयोग किया जा सकता है, शरब में किया जा सकता है लेकिन तमाकू में नहीं किया जा सकता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अस्ट्रावार का एक बहुत बड़ा +वोल यह बनता चला जा रहा है। जर्डा, किमाम आदि वेचने वाले छोटे लोग होते हैं। अब फूड एडल्ट्रेशन रूल्ज के अन्दर नगर पालिका और नगर नियम के फूड अफसर इन छोटे छोटे दूकानदारों को जा कर पकड़ते हैं। मुझे यह कहते हैं संकोच नहीं है और न ही किसी प्रकार की शंका है और वड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं यह कह रहा हूँ कि यह अधिनियम भारी अस्ट्रावार का भूल बन रहा है। अस्ट्रावार करने वाले नगर कोई अधिकारी है तो ये फ़ृ आफीसर्स हैं। उनके इंसेप्टर को बहुत ज्यादा बड़ा दिया गया है। एक मामूली फूड अफसर जो नगरपालिका का होता है, वह पांच हजार, सात हजार और आठ हजार रुपये महीने से कम नहीं कमाता है। जहाँ वह सेम्पल लेने जाता है वहाँ हजार आठ सौ रुपया ले लेता है। आप यह भी देखें किकोल तार डाइज मिश्रत मिठाई को छोटे छोटे बच्चे खाते हैं तो उन को कोई हानि नहीं होती है लेकिन जब तमाकू बड़ा आदमी खाता है और उस के अन्दर कोलतार डाइज लगा दी जाए है तो हानि कैसे हो सकती है। यह जो एनामलस पोविशन है इस एनामलस पोविशन को दुक्स्त किया जाना चाहिये।

मैं यह मैं टैक्सटाइल इण्डस्ट्री की जनरल पौलिसी के बारे में नहीं कहूँगा, मैं केवल पावर-लूम के बारे में ही कुछ कहना चाहूँगा। इसके बारे में बजट स्पीच के अन्दर वित्त मंत्री जी ने बताया है कि हमने पावर लूम को कम्पाक्टेट लैंबी से मुक्त कर दिया। यह बात सही है। लेकिन इसके साथ साथ भेद कहता है कि देखना यह है कि यह इसका इच्छित परिणाम हुआ है कि नहीं। हम समझते ये कि पावरलूम एक ऐसा सैकटर है कि इसके ऊपर जो कपड़ा बनता है वह गरीबों के काम आवेगा और एम्बायर्मेंट पॉटेंशियलिटीज आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं कहता चाहता हूँ कि कपड़ा जो कम्पोजिट मिल बनायेगी और उसमें जो लगने वाला सूत है वो मिल को कोई उसकी इयटी स्पैन वाली नहीं है। नोटिफिकेशन नम्बर 137 के तहत कम्पोजिट मिल के अन्दर जो कपड़ा बनेगा उस कपड़े में लगने वाले सूत के ऊपर किसी प्रकार की इयटी याने पर नहीं लगेगी। लेकिन ताज़ब इस बात का है कि पावरलूम अगर कोई कपड़ा बनायेगा कम्पोजिट मिल से याने खारीद कर तो उसको इयटी देनी पड़ेगी। और परिणाम यह हुआ है कि नोटिफिकेशन नम्बर 132 और 137 के प्रकाश में जब कम्पोजिट मिल का एक छोटी जोड़ा 10 गज का अगर बाजार में बिकने के लिये आवेदा तो उसके ऊपर एकसाइज इयटी 30 पैसा लगेगी। लेकिन पावर लूम का वही छोटी जोड़ा जो 15 ह० का है और 10 गज का है जब बाजार में बिकेगा तो उस पर 78 पैसे इयटी लगेगी। और कम्पोजिट मिल पर नहीं लगेगी। जैसे जैसे जो यह खिलती निकलती है उस कपड़े के बारे में है जिसमें 34 और 36 काउटर्ट के कपड़े का उपयोग होता है। जैसे जैसे काउटर्ट बहुत जायगा याने के ऊपर इयटी बड़ी जाएगी और पावरलूम का कपड़ा बिल के कपड़े के मुकाबले में महँगा होता जायगा। इसलिये कम्पोजिट इयटी बहुत जो जो अस्ट्रावार किया जाता है ज्ञानीय वित्त मंत्री जी के द्वारा और उस

कारण से जो एक सुविद्धा पावरलूम सेक्टर को दी जा रही थी वह कोई सुविद्धा काम की नहीं है। स्थिति यह है कि मिल के मुकाबले में वह पावरलूम टिक नहीं सका। चूंकि यह व्यापार का विषय है इसलिये आप को इस मामले को टेक अप करना चाहिये। ऐरा निवेदन है कि मंत्रालयों के अन्दर जो स्थिति दीदा हो जाती है कोआडिनेशन न होने की वजह से उस पर बन्धीरता से विचार किया जाय। इनको विषय ऐसे हो सकते हैं जिन के बारे में मंत्रालयों में कोआडिनेशन से अच्छा काम हो सकता है। इसलिये ऐसा कोई तरीका ढूढ़ना चाहिये जिससे कोआडिनेशन हो। वरना कई बार ऐसा होता है कि किसी बस्तु को लेकर, जब वह चीज बाजार में आती है, तो कोआडिनेशन न होने की वजह से आगे समस्यायें खड़ी हो जाती हैं। हर मंत्रालय अपने अपने डंग से विचार करता है, कोई मंत्रालय अपने डंग से सोचता है तो दूसरा मंत्रालय उस पर कोई विचार नहीं करता है।

मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं, जहां पावरलूम उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। मन्त्री जी आप भी ऐसे राज्य से आते हैं जहां पावरलूम उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। ऐरा निवेदन है कि उस उद्योग को बायेवल बनाने के लिये, उसे ठीक से चलाने के लिये हम क्या करन उठाने जा रहे हैं, हमें यह देखना है।

ऐरा कहना यह है कि कुछ टैक्सों से कंपेन दे कर, एक मद में कम करके हूसरी में बढ़ा कर, अगर हम यह सोचते हैं कि इस तरह के हम लोटे लोटे उद्योगों को बढ़ावा देने तो ऐरा निवेदन है, वह ठीक नहीं है। 1966-67 में माननीय श्री प्रशोक मेहताजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी जो रिपोर्ट है वह आज भी बड़ा बेलड डाक्युमेंट है। अबस्थकरता आज इत्तेवात की है कि उसको देखा जाये। हमें घनिष्ठ रूप से निर्णय करना होगा कि प्रावरलूम कौनसा

करड़ा बनाये, हैडब्ल्यूम कौनसा करड़ा बनाये और मिल कौनसा बनाये। हमें इन बीकर सेक्टर्स को अगे बढ़ाने के लिये किस प्रकार से प्रोटॉकल देना चाहिये? लोटे भोटे कृष्णगंगा देके हमारा काम नहीं चलेगा।

अन्त में आपका धन्यवाद करते हुए माननीय मन्त्री जी ने जो डिमान्ड प्रस्तुत की है उनका समर्थन करते हुए मैं समझता हूं कि इह इन बातों पर व्यापन देंगे।

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): I am very glad to participate in the debate on the Demands of this Ministry. Shri Dharia has been closely associated with the co-operative sector in particular. Whatever position he has held, he has worked sincerely and devotedly, and I am sure that his services will prove beneficial to the country after his taking over this Ministry also.

The Finance Minister has expressed a desire to help the rural population and the development of agriculture. Next to agriculture, the second largest number of people in the country is engaged in weaving, but the concessions which have been given to the handloom sector, through they are reasonable, have been neutralised by the concession given to the power loom sector. This has been brought to my notice by the Andhra Minister of Handlooms. I therefore request Shri Dharia to take up this matter with the Finance Minister. Ninety per cent of the handloom are owned by individuals or co-operatives, but the powerlooms are organised by moneyed people. In Maharashtra it is more popular. In Andhra, though 10,000 units were sanctioned, only 2,500 have been sanctioned so far. There are two crore ordinary handlooms in this country on which depend the livelihood of nearly 40,000 families. The break-up is like this :

Andhra Pradesh . 6 lakhs

Tamil Nadu . 6 lakhs

U.P. 6 lakhs where 90 per cent of the weaver's are Muslims. Most of the people in this country think that handloom weavers mean a particular class of society. But they do not know that Muslims and Harijans are also there in this sector. In Assam, it is a livelihood for ever family. There, it is a must for ladies to learn weaving as they learn cooki-

[Shri K. Suryanarayana]

ing or sewing. So, the Government must do something concretely for their welfare. Unless Government does something, there is no difference between socialism and communism or Jantism and Congressism. The Congress Government has some very good schemes for the welfare of this class of people, but they could not implement them because of lack of funds. I do not want to enter into politics on this issue but I would request that some protection should be given to them. In this connection, I would suggest to the hon. Member that instead of giving rebate on finished products, rebate should be given at the stage of supply of yarn to the weavers. The price of the yarn should be reduced. If the rebate is continued to be given on the finished products, then the corruption will go on unabated. There are reports that several crores of rupees have been swindled. So, these things will go on if you continue to give rebate on the finished products and supply the yarn through mills and other agencies to the weavers. So, the yarn should be supplied to the weavers directly and there should not be anybody in between. In this way, the weavers will get some relief. The other day, Shri Charan Singh has also said that rural industries should be given due consideration so that the unemployed people in the rural areas get more job opportunities. I would again request the Government that if they want to help the weavers, concession or rebate should be given on the yarn and the yarn should be given directly to the weavers so that there is no need of any co-operative or any other agency. There are so many complaints in several States regarding corruption in giving rebates. A handloom can manufacture 5 metres only within 8 hours whereas a powerloom can manufacture 30 metres. So, I would once again request the hon. Minister to give serious consideration to this proposal.

Coming to the National Cooperative Development Corporation, it was started about 10—15 years ago. It is a novel system which was introduced in the country. But there is no supervision machinery. From the very beginning, I have been asking the Government in the House, during every session, that there should be a controlling authority over them. But nothing has been done. There is no machinery to supervise that the funds which are given by the Government of India to the State Governments or to the cooperative institutions anywhere in the country are utilised properly. There is no control over them. They are simply interested in taking back the interest on the principal. That is not the only purpose. We have given loans for

the purpose of the development of the cooperative movement as well as the production of these things in a systematic way. It is not only for the purpose of doing money-lending business. Whenever I raise this point, I am told that they are getting back interest from them. The State Government stands surely for the cooperatives in the matter of giving loans to the cooperatives. They are only interested enough to take back the interest on the loans given to the cooperatives. But we are interested more in production of goods, and the development of cooperatives. I would request the hon. Minister to have a supervisory machinery to see that the loans, which are given to the cooperatives, for the development of a particular cooperative, it may be a rice mill or a sugar mill or a cotton mill or any other industry in the rural areas, are properly utilised or not. This matter should be seriously examined. Otherwise there is no necessity to give huge funds like this. They are also getting a lot of funds from the market, from outside. It should be properly organised and put it in a right condition. There should be a controlling authority over all the cooperatives and other organisations to which they are advancing loans.

Coming to the cooperative sugar factories, that is the only rural industry besides the cooperative rice mills. According to the 1976-77 Report, out of 744 rice mills, 721 rice mills have been installed and out of 180 sugar factories, the licences have been given for 160 sugar factories. Except in Maharashtra and Gujarat, in all other States, the cooperative sugar factories are not being properly worked. What is the reason for that? They are not at all following any advice given to them. They are not at all giving any proper attention to the resolution passed by the All India Cooperatives' Conference. For instance, sometime back we passed a resolution in the All India Cooperatives' Conference that the cooperative law should be amended in Andhra Pradesh and other States. But nothing has been done. What has happened is that whosoever does not get the ministership or anything in the Government, the MLAs and the legislators are being appointed as Directors. Nobody is taking interest in the development of the cooperatives. It is so particularly in my district. Recently, the Secretary of a cooperative bank told me that for the last one year there is no quarrel because all the MLAs are Directors. They have been nominated. The same thing is happening in the primary cooperative land mortgage bank where an MLA has been appointed as the Director. He is a big merchant. He does not know even the ABC of cooperation. He only knows non-cooperation and creates troubles. The Central Government

and the State Government should learn from all these practical things. The co-operatives are not working in a systematic way. That is why we are being criticised by other friends that we are not concerned with cooperative movement.

Unless we do something concrete about these co-operatives, they cannot survive. There are so many rumours against them. Even the Director of a co-operative has no respect in the public. That is already going on in the minds of the people. In the Revenue Department, these LDCs and the UDCs are earning money. Everybody knows about it. This Government should try to put an end to this sort of corruption wherever it exists. Everywhere there is corruption in these things.

I am requesting Mr. Mohan Dharia to take the trouble of visiting all these places and particularly my own district where these cooperatives are there. In 1961, the co-operative movement was started in Andhra Pradesh. Still it is very very backward in this respect. They are having 10th position in the country. There is no proper attention being paid, as far as these co-operatives are concerned. I myself started a co-operative. I have come up. Maharashtra has also done something good for the development of co-operative sugar factory. There are some remarks against them. Those remarks should be rectified. Otherwise, you cannot blame the entire co-operative movement.

We have to avoid capitalism or communism or any other ism. Co-operative movement is the only thing which we can develop in this country and which suits this country. Eighty per cent of the rural people are agriculturists. Out of 80 per cent, nearly 60-70 per cent depend on agriculture; 5-10 per cent are the weavers; and the other 10 per cent are the carpenters and other people. The National Co-operative Development Corporation has organised nearly 15 co-operative organisations like co-operative marketing processing unit foodgrains marketing processing unit, sugarcane processing unit, cotton processing unit and so on and so forth.

Coming to the co-operative sugar factory, in my anxiety, in 1950, I had applied for a licence. I got the licence after 12 years. In the same way, in my own district, there are people who also got the licence. There are so many restrictions. I came back to Parliament in 1967. I got the licence with the help of the Co-operative Department. Within

six months, We collected nearly Rs. 71 lakh and the NCDC had given us Rs. 65 lakh. We had also borrowed "Rs. 50 lakh from the LIC and Rs. 170 lakh from the Industrial Finance Corporation of India. We constructed a factory including a building for the officers at a cost of Rs. 306 lakh. But we are not able to repay the interest. Now we are completing the third year and the losses are there. Only yesterday, I received a telegram from the Managing Director. He was Deputy-Collector and was appointed as Managing Director by the Government. He sent a telegram mentioning that according to such and such reason for the last three years the loss came to Rs. 115 lakh. Whose fault is this? This is how we are going. In the first year, we had crushed 80 lakh tonnes of sugarcane. In the second year, though we had crushed 1,04,000 tonnes of sugarcane, still the loss was Rs. 50 lakhs. This year we have been able to crush only 90,000 tonnes as against 150,000 tonnes which we had planned because there is no money to pay to the farmers in time. But the private factories in U.P., which are using all rotten and outdated machinery, are encouraged; they have been given all incentives. I had asked a question about the cost of the factories which were constructed in 1974-75 in the country. They said that 14 or 15 sugar factories had come up. They had machinery of the same capacity of 1,250 tonnes per day—crushing capacity. Some of the factories had paid Rs. 2 or 3 or 4 crores for the same machinery. The total cost was Rs. 4 to 5 crores. The cost of our factory was Rs. 3,06,00,000, and we have been penalised because we got the machinery at a low cost. The previous Government was not kind enough, on a report of Mr. Sampath, to give incentives to us because we had constructed at a lesser cost and paid only Rs. 1-1/2 crores for the machinery. They had said that, whosoever did not spend more than Rs. 2 crores on machinery would not get the incentive. For what reason? Is efficiency to be penalised? We got the low cost for the machinery after negotiations. On the Advisory Committee for the selection of the machinery, the same Central Government and State Government officers were there. We negotiated and got the price down. That was the lowest in those days. And, because of this, our Society, the West Godavary Sugar Co-operative Society, is not getting the incentive. I would like to quote this :

"These incentives are linked to actual cost of a 1250 tonnes standard plant as prescribed by the Government of India (excluding the optional items

[Shri K. Suryanarayana]

of machinery) on f.o.r. (machinery manufacturers' works) basis, i.e., excluding freight, insurance, octroi, sales tax and erection charges. These concessions are available when the f.o.r. cost of plant and machinery is Rs. 200 lakhs and above subject to a maximum of Rs. 400 lakhs. "The incentives envisaged in this scheme are not granted if the f.o.r. cost of the plant and machinery is below Rs. 200 lakhs."

What is the reason? Mr. Mohan Dharia, I can place before you the wide variation in the prices paid for the same machinery in the same year. One private factory had constructed at a cost of Rs. 5 crores; at another place the cost was Rs. 3-1/2 to 4 crores. The cost of our factory was Rs. 306 lakhs. This matter should be inquired into as to why there has been so much variation. It is a wrong thing which has been done so far as giving incentives is concerned. The low cost should not be the criterion for not giving the incentive. We have not been able to pay the instalment of interest for the last three years. This is not the fault of the management. It is because of the policy of the Government. We have been supplying sugar to Government, to the STC, -65 per cent—at levey price. We are sending only the balance to the other customers. We are sending 65 per cent to the parties recommended by the Government and to Vizag harbour for export. If the Minister is sincere, he should rectify this anomaly in giving incentives. My request to him is that this should be rectified immediately.

My next point is about rice industry. We, the Congress, passed long ago, in 1962—when Mr. Patnaik was with us—the Resolution for nationalisation of rice industry.

After the split in our party in 1969, we passed another resolution for nationalization of sugar factories in Bombay. I would request the hon. Minister to give due consideration to this aspect. When I requested Shri Jagivan Ram Ji to 'de-cooperative' our cooperative societies, he asked what the benefit will be to us. I told him that we would manage the factories in our own way, we might not ask for any concessions, we would have our own methods of manipulating the figures and recovering losses without any financial assistance, and the sugar produced may not be sold to them.

How, after introducing the new methods, i.e. by having diffusers etc. on an additional investment of Rs. 35

lakhs, in some factories, they are not showing more recovery of sugar. In the first year itself, our factory has shown 9-1/2% sugar recovery, second year also the same recovery was there, but this year due to the effect of cyclones, we got 8-93% sugar recovery. The cooperative movement in so far as sugar factories are concerned is losing its ground and is being heckled also.

I would also suggest that the rice mills should also be considered for nationalization. In my district, 14 cooperative rice mills were constructed by the financial assistance of the National Cooperative Development Corporation. NCDC may always say that they were not giving the loans direct, but they were doing so through the State Government and that they were getting back their loan plus the interest. But, I would like to submit that it is not intended for that purpose only: it is intended for the development of cooperatives. NCDC are not money-lenders only concerned with their principal and interest. After all, that is also public money. Only one rice factory is running properly; others are not. I have constructed a modern rice mill when Shri Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister. It costs me Rs. 33 lakhs; godowns 28 lakhs, machinery and building 5 lakhs. The machinery was imported from Japan. In Tanjore, in Tamil Nadu, another rice mill was put up for experimental purposes. It was with a four tonnes per hour milling capacity and the machinery was imported from Germany. They have repaid the cost of the machinery etc. because the DMK and the previous Governments helped the cooperative society in a systematic way. On the other hand, in Andhra Pradesh, the Government does not give any preference or the required assistance in time to run the cooperative rice mills. Tadepalligudem is the biggest rice marketing centre in Andhra Pradesh. I have not preferred my native place, Eluru, but I went forty miles away from my place for the setting up of a new factory, because that place is the centre for rice procurement. We invested Rs. 33 lakhs, but I left the society in 1967. Since then, it is not being run properly and now it has been closed, because of the accumulation of huge losses. One of the reasons is that nobody takes interest and they do not go in for competition. Now, I took two rice mills on contract and I have shown a profit of Rs. 2 lakh within three years by standing in the open competition. There must be sincerity and only then, we can succeed. On my personal guarantee, the State Bank has given loan. Now-a-days, nobody is prepared for standing surety. No bank, therefore advances any money to these rice mills.

Now, while on the one hand, all the cooperative rice mills are lying idle, the Food Corporation of India is constructing new rice mills. Why should they not take over these mills on lease or outright purchase instead of constructing new ones? FCI is a public institution and in these cooperative societies also, there is public money. We have no objection if they take over all the rice mills, but they should be properly run and the money should be repaid to the creditors. You should advise the Andhra Pradesh Government that instead of keeping these rice mills idle, they should lease them out or put them in the market for sale. There will be many people to take these mills.

I would request the hon. Minister to visit my place and see these sugar mills and rice mills for himself. He would realise how these mills are incurring the losses. You should take measures to wipe out these losses. The farmers have been crying and have requested me to take you, Mr. Mohan Dharia, with me to our district and show you all these mills. Let my society be converted into a joint stock company if the Government is not prepared to give the required incentives. This is because there is non-co-operation and always non-co-operation. That means that they are not giving any monies from the bank. In the State, 'Co-operation' means that they can put Directors without any knowledge of co-operation. That is what the State Government is doing. You write to the State Government also why they have not amended the bye-laws according to your suggestions and why they are appointing all the non-official Directors and that too only MLAs.

Finally, I want this free sale and levy sugar of 35% and 65% to be removed. Take the entire thing. Otherwise leave it to free sale and then only it will be solved. Leaving this 35% free sale you are encouraging black-market. They have to make money. Now they are crying after you releasing your stock in the open market. I want to request you to control it or otherwise leave it to the market. Sugar industry naturally wanted the excise duty to be reduced. If you are not giving any facilities, reduce the excise duty. Because you are taking 65% they will ask all the facilities. If you are not taking 65% and leave all the sugar to open market, they will not ask for any concession. That is how they are losing.

Finally, I am requesting you to examine the co-operative sugar factories. In your State also they are there. Mr. Raj Narain was saying, 'We are against co-operatives, we are against the Direc-

tors' saying so many things. That is not the fact. They have constructed them and managed them openly. They are very proud of their factories. They are running colleges, they are running medical institutions. They are giving facilities not only to workers but also to the general public. Every factory employs 1000—4000 workers. You please go and examine them. If there are any unfortunate things committed by the Directors or the management, try to rectify them. Don't blame the co-operative movement. Don't try to destroy the co-operative movement. Give them strength and avoid all these ill feelings and the co-operative movement should be strengthened. Then only our rural sector will develop and flourish. Mr. Charan Singh is always saying, 'We want the rural sector to grow.' We also support you in that and I hope Mr. Mohan Dharia will soon visit my place and give some relief to the people there.

श्री अमन्त बचे (कच्छ) : सभापति महोदय, मर्ली जी ने जो छिमान्व पेश की है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, केवल दो, तीन बारें बताना चाहता हूँ। एस्पोर्ट में ऐसा बताया गया है कि कांडला की ट्रैक जोन हमारे देश में ऐसा एक ही जोन है। . . .

सभापति महोदय : माप जरा माइक के पास आ जाएं, क्योंकि मापकी भावाओं सुनाई नहीं दे रही है।

श्री अमन्त बचे : लेकिन बहां के डैब्ल्यूपीटी और कंस्ट्रक्शन के लिये इस बजट में 1 लाख रुपये का प्रावीजन किया गया है। आज 12 साल से यह की ट्रैक जोन हमारे देश में काम कर रहा है। आज भी 28 यूनिट्स बहां काम कर रहे हैं। बहां से 100 प्रतिशत माल एक्सपोर्ट किया जाता है। यह दुःख की बात है कि आज 12 साल के बाद भी बहां कोई कानून नहीं बना है। नोटिफिकेशन के प्राप्तार पर ही यह की ट्रैक जोन काम कर रहा है।

वहां से 1975-76 में 347 लाख रुपये का फारेन-एक्सपोर्ट हमारो मिला और इस साल 1977-78 में 5.90 करोड़ रुपये

से भी व्यापा का फारेन-एक्सचेंज हमको मिलने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियों में जबकि सारे देश में यही एक की ट्रेड जोन है, उसके लिये तिक्क 1 लाख रुपये ईवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिये जो रक्खा है यह बहुत कम है।

यह भी गवर्नरमेंट भाक इंडिया का बनाया हुआ एक जोन है, उस पर काफी मात्रा में ऐसा लगाना चाहिये। इस जोन के ईवलप होने से हमको काफी फारेन एक्सचेंज मिलेगा। आज तक भी कांडला फी ट्रेड जोन में एप्राइजर एप्लायाइन्ट नहीं हुआ है, जबकि वहाँ नई पोस्ट क्रिएट नहीं करनी है। इसकी वजह से बाहर से जो व्यापारी बिजनेस करने के लिये आते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। जो वहाँ बेस्ट मैटीरियल होता है, उसके लिये कोई रुप केम नहीं किया है। भाज भी वहाँ पर बेस्ट मैटीरियल का गंज लगा पड़ा है। उसके लिये सोचना चाहिये कि क्या करना है। इस ओर मैंने मन्त्री महोदय का व्यापार पल लिख कर भी छींचा है, उन्होंने बा भी दिया है कि मैं इस पर सोच रहे हूँ। मेरी प्रार्थना है कि यह जो तकलीफ इस की ट्रेड जोन को हो रही है इस बारे में सोचा जाये और जो 1 लाख रुपये की बोही सी राशि इसके ईवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिये आपने रखी है, अगर बड़ी मात्रा में यहाँ ऐसा लगायें तो इस की ट्रेड जोन का ईवलपमेंट होगा और बहुत बड़ी मात्रा में हमको फारेन एक्सचेंज प्राप्त होगा। कमेटी आन पिटीशन्ज ने भी आपनी रिपोर्ट में इस जोन की दिक्कत के बारे में लिखा है, मैं मन्त्री जी का व्यापार उसकी ओर भी छींचना चाहता हूँ।

अन्त में मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय यहाँ की दिक्कतों को दूर करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने जो यहाँ डिमाण्ड कर्ती हैं, उनको सपोर्ट करता हूँ।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE (Ahmednagar) : I shall be dealing with the subject of co-operation. But before I go to that I would just like to make one or two observations regarding some other subjects of Ministry of Commerce.

In regard to exports my own feeling is that we should be prepared to export at the cost of national sacrifice. That should be our basic approach. Ultimately, even the price stability depends upon the stability of our rupee currency. Take for instance the experience of Japan or the experience of Germany. Or take Germany's experience. Look at Yen/or D.M. of Germany. They are strong currencies. They have very vast foreign exchange reserves with them. Substantial part of their production goes to meet the international markets. There should be an educative approach in the whole matter. This is what I would like to stress. Our valued colleague, Smt. Ahilya Rangnekar asked why rice was exported. I quite see the point. Even in the past rice in general was not exported but only one variety, Basmati rice was exported. This was consumed by less than 1% of our people, having very high income. If you look at the export pattern of China, they discouraged deliberately the local consumption of superior varieties of food. For this purpose they promoted export of rice. They imported large quantities of wheat. They exported superior varieties of rice and also processed fruits. This is the approach of countries which do such things in order to look to their basic national interests. To strengthen national economy people should be prepared to make sacrifices.

Now I come to the subject of export of oilcakes and on this point, I would request the hon. Minister to give up earning foreign exchange from oilcakes. On the one side the Prime Minister wants to encourage and develop the dairy industry. Dairy industry and animal husbandry can be encouraged only if cattle feed and concentrates are available in the country and the farmers get them at reasonable prices. At one time when foreign exchange reserves were very low, one could understand arguments in favour of export of oilcakes. But now the situation has changed. Our foreign exchange reserves are at a satisfactory level. Our export performance is much better now. Trade gap was quite wide in the past. Then there were some large imports of foodgrains and fertilisers. Today we are not importing them. As far as fertiliser production is concerned, we should see that the production increases by utilising Bombay High and Basin gas which would be the chief raw material for the manufacture of fertilizer.

Regarding the fodder resources in the country, many committees have gone into this subject and they have pointed out the need for developing our dairy and animal husbandry. They have stressed

the need of cattle-feed and poultry-feed being made available to the farmers at reasonable prices. Rs. 150 crores worth of oilcake was exported to foreign countries. We have seen this position during the last 3 years or 4 years and particularly so during the last 6 months. Cattle feed prices have gone up by 200 or 300 per cent. What I wish to submit is this. To talk of dairy development and also continue export of oilcake is a contradiction in itself. Dairy industry and poultry industry are such industries which are basically labour-intensive. They give employment to vast numbers of people. Large employment possibilities are there.

In view of these reasons I would request the hon. Minister to stop the export of oilcake as early as possible. If you do it, this step will improve our economy, it will give more employment to our people. This is one of the important suggestions which I wish to make so far as our export policy is concerned.

There is one more suggestion that I want to make. As is known to all of us, agricultural commodities play a very important role in earning foreign exchange for our country. Here there are certain complex situations that are developing.

I have read with interest some of the announcements made by the hon. Minister. For instance, he said that if prices of essential commodities go up, exports of these commodities would be stopped. I understand and appreciate his approach of the hon. Minister in this regard. But, ultimately, in the long run, we should not take an isolated approach. Take for example, tea, coffee, cardamom, pepper, tobacco etc., etc.

These are the items which earn a very sizeable amount of foreign exchange. Take for example Darjeeling in West Bengal. This is a place where the agro-climatic condition are such that we can produce the best type of tea. But our tea estates or plantations in that part of the country are not in a good shape. Unless of course we take steps side by side to improve the production of tea or coffee, we will not be in a position to have a proper correlation and coordination between exports and domestic consumption. As far as domestic consumption is concerned, a realistic assessment requires to be made. Let us see what is the present demand in our international market. Let us work out the foreign exchange that we are likely to earn. We should then work out our production programme on this

basis. I can say that with a certain sense of responsibility that, in this country, agriculture affords us a far more scope and big scope for earning foreign exchange.

We should not discourage that. That is possible only if we are also in a position to meet our own domestic requirements. Intensive agriculture will give a lot of employment to our people. *Ad hoc* decision should not be taken in regard to exports of onions, potato, vegetables etc., etc. They are labour-intensive and so, I say that *ad hoc* decision should not be taken in regard to their exports. If you do that, what will happen is that our production will get discouraged. Production in this country is getting an impetus only because of the increasing contributions made by our farmers. Exports are possible because our production is getting the necessary impetus. We should also have adequate storage to store these commodities so that, in the lean period, you may be in a position to meet the domestic requirements of this country. So, exports should not be stopped because ultimately, it is the farmers who will suffer most. You will not be in a position to control the price. With these few observations, I now come to the subject of cooperation.

One of our valued colleagues, Shri Brahm Perkash just now spoke. He was interested more in this subject. No doubt he is a seasoned person and he has spent major part of his life in cooperation. I may also tell him that same is the case with me as well. I had the fortune and privilege of working in the rural areas building up the cooperatives right from village cooperatives to marketing societies and processing societies. I spent a major part of my life in building up the village cooperatives. Because of that, naturally I have gained some experience of field problems.

14.53 hrs.

[SHRI D. N. TIWARY in the Chair].

I am not prepared to take a very discouraging view of these things. Shri Brahm Perkash said that he knew much more about the cooperative sectors. I am also aware of the very major drawbacks and weaknesses of our cooperative movement. I realise that poverty is still rampant in this country. Millions of our people are poor. Naturally, the cooperatives alone can serve them better. There is no other way. Shri Brahm Perkash perhaps has over-simplified this matter by saying that because of the political intervention, cooperatives have

[Shri Annasheb P. Shinde]

not developed well in this country. I can tell him—he should know that—that political intervention is not the main reason. If that is taken as an argument, then he would only be oversimplifying the matter. Take the case of Gujarat from which our Prime Minister comes. Cooperatives are doing well in Gujarat. Even in Maharashtra, they are coming up. Punjab also is doing well so far as cooperatives are concerned.

We have to go deep into the matter. Oversimplification of a thing will not help anyone at all. The major and foremost hurdle in the development of cooperative movement in this country has been our cast ridden society. Our society is sharply divided—one section of our society shows distrust to the other section. This is a historical fact whether we like that or not. Cooperative movement did not come up in some parts of our country because the zamindari system was prevailing so long in many areas. Otherwise, why is it that the cooperative movement has not come up in the whole of north-eastern region with all its fertile land, intelligent and good people. It is because of the zamindari system. Implementation of land reforms has a lot to do with the success of cooperative movement. Unless land reforms are implemented sincerely in the north eastern region and egalitarian land ownership is brought about, I do not think, even if government intervenes or does not intervene, it will help the cooperative movement.

15 hrs.

Fortunately, I had an occasion to discuss with eminent cooperators about the sociological reasons responsible for the failure of this movement. I was closely associated with Dr. Gadgil. He was an eminent cooperator. We came to the conclusion that if cooperative movement in this country has to be developed, then we will have to democratise our social structure and some democratisation has to be brought about in our economic structure also.

Mr. Chairman, Sir, now I will say a word about the uneven development of cooperative movement in this country. While all of us should realise that there are many weaknesses in the cooperative movement yet we should appreciate that cooperative movement has made some progress in this country.

Sir, in 1952, only Rs. 25 crores were being disbursed to the entire agricultural community through the cooperatives whereas today this credit has exceeded Rs. 1200 crores. Even the so-called nationalised banks and the private banks

are not in a position to cover much area as has been done by the cooperatives. We should not lose confidence in co-operative movement. If we look at IFCO, we find that Rs. 98 crores have been invested in this cooperative enterprise of Gujarat. It is succeeding well. Similarly, there is a Rs. 165 crores naptha based plant at Phulpur also. It will also succeed. Now, you may look to cooperative marketing in Punjab. It has played a very important role in the purchase and sale of agricultural commodities and supply of inputs to farmers through the cooperatives. In the country agricultural commodities worth Rs. 2,500 crores are sold through the cooperative marketing societies. This is no mean achievement. The movement has been progressing but if we try to improve upon and bring about certain changes in it, I think, it will succeed further.

Now, a word about the official intervention in the cooperative movement. Government's intervention is too much and I can say no political party is free from this sin in India. All political parties are tempted to interfere in the cooperative movement. I would request all political parties—including my party—to let the cooperative movement develop without political intervention. If we intervene in the cooperative movement, then not only the cooperative movement will suffer but also the economy of this country will suffer and as a result thereof the poor will suffer. I do not know whether my proposal will be acceptable or not but I would like to suggest that those who are active in cooperative movement at the tehsil, district or state level should resign from the cooperatives as soon as they become MLAs and MPs. Otherwise, I know from the experience how the politicians are tempted to use their positions in the co-operatives for political purposes and that damages the co-operative system. I know that many State Governments have not accepted the advice of the Central Ministry. They have been tempted to intervene in the affairs of the co-operatives because they want to bring their own party men in. For the co-operative membership, the principle of nomination should not be followed. It should entirely be a democratic election, democratic membership. But unfortunately the Government does not intervene where it should intervene and that is why the co-operative movement has suffered from a large number of cases of embezzlement and misappropriation. In such cases Government should intervene with a very heavy hand. My general experience is that Government is so reluctant that the entire system of auditing requires to be changed. Many times it is only a post-mortem. This year's accounts will be examined after one year

two years. That means, by the time it goes to the General Body, the concerned office leaves may or may not be there or the matters may because state. We will have to establish independent statutory organisation like Auditor General's Office for the co-operative department and a system should be developed for quick audit. Now, the world technology has so much developed, computers work out the balance sheet within a short time. The co-operative year ends on 30th June. Immediately after one month it should be incumbent on the co-operative organisation to bring out its balance sheet. In the world, even in 24 hours the organisation operating at international level having branches in many countries, has been able to prepare its balance sheet within 24 hours with the help of computers. Why should it be argued that we cannot prepare our balance sheet within the specified time? In any case, misappropriation is there. An independent authority should be asked to intervene in this and take strict action, whether he is a political person or a person occupying high position. Strict action should be taken against those who misappropriate the funds. After all it is public money which is involved in the co-operative movement.

There are two things. One thing is very clear that Government should not intervene in policy matters. That should be entirely the prerogative of the non-officials. So far as misappropriation of funds is concerned, the Government should come down with a very heavy hand.

Sir, I am sorry to note that this Ministry has not been bifurcated. I do not know why this position continues even now. At least now the Government should be in a position to rectify the position. Take the Co-operative credit. It does not come within the purview of Co-operative Department. It is a part of Agriculture Ministry. But the agricultural inputs are supplied by NAFED or other marketing organisations which are supposed to be looked after by Mr. Dharia. So far as the agricultural inputs are concerned, credit input supplies and marketing should be together. So far as the entire gamut of Co-operatives are concerned, it should be under the aegis of one Ministry. I wish the subjects of agricultural production and supply of agricultural inputs are brought together and put under one separate Ministry. So far as the co-operatives are concerned, there should be a separate Ministry for this purpose. I do not mean anything against Mr. Dharia. He can be the Minister of Co-operation. I

wish that at least the co-operatives in this country should be given a status of an independent Ministry and an independent man should be put in charge of the Department of Co-operation. My experience has been that this Department of Co-operation gets lost with bigger and many other Departments. Now, Mr. Dharia has to look after Commerce and Civil Supplies. It is a very big job. How can he attend to the subject of co-operation? This has been happening in the past also. I wish Mr. Morarji Desai who understands problems of co-operation—because when I started my work in the field of co-operation in early 50s, Mr. Morarji Desai was at the helm of Maharashtra affairs and we had a lot of encouragement—to the co-operative movements—I wish he looks himself personally into this matter and examines my suggestion very carefully so that this subject could come under a separate Ministry. This would help solve problems of millions of poor people in the rural areas as also the problems of people of the urban areas. In co-operative movement today the share capital is Rs. 1500 crores and the working capital is Rs. 5000 crores. There are now about three lakh co-operative organisations. There are so many lakhs of employees in the co-operative societies. It is not a small sector. It is a big sector. This movement should get due recognition.

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION SHRI MOHAN DHARIA—I share your concern.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : Then, Sir, there are two or three points. You are aware that the N.C.D.C. is a very powerful organisation for promotion of co-operative development in this country. In this corporation you should bring in more non-officials; if necessary, you can amend the law. You should give more massive support both by way of grants and loans. The NCDC should be authorised to raise loans from the market for supporting viable economic schemes such as processing, etc.

CHAUDHURY BRAHM PERKASH : For the information of the hon. Member, that is also the suggestion of the Administrative Reforms Commission.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : We welcome it. We should be clear what is the role of a cooperator, a non-official or politician and what is the role of paid officials. If somebody becomes the Chairman, he also thinks that he should carry out the work of the executive. There is need to develop professional management and the duties of

the executive should be defined, just as ministers' duties and secretaries' duties are clearly demarcated in the central government. Non-officials should lay down policy and the officials should implement it. My experience in Maharashtra and elsewhere is that non-officials are tempted to interfere in areas allocated to officials.

MR. CHAIRMAN : Do not ministers interfere with the work of secretaries?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: They are not supposed to and we know what has happened in the country. I hope Dharaji will accept my suggestion. You are a senior leader and you know that intervention comes when policies are not implemented; it should not come otherwise normally. There should be no interference in day to day affairs or functions entrusted to officials. You can remove the officers if you think they are not discharging their functions properly.

The support in the State budgets for co-operative movement is not adequate. At the end I should say that for multistate units there should be a law and I shall extend full support to that. At least they should make it a model law so that it may be an example in the country. Co-operation is a state subject and you can only lay down policies. But the Government of India can possibly influence and take the initiative in impressing the State governments so that more provisions are made in the State budgets for the development of the co-operative movement. In the Centre also adequate provisions should be made. My suggestion is that you should make a law governing multi-State units which will be ideal co-operative law and if you do so I think Brahmin Perkashji will have no complaint as far as that subject is concerned.

I know that some problems present a lot of difficulties and I do not want to go into such cases. Our experience has been that state governments do not carry out the mandate of the centre. Take the case of Gujarat. Even when President's rule was there the general experience was that the Governor or even the advisers were not implementing what the Centre said. Now I hope our friend will be in a position to help us. I would suggest that no State Government should be allowed to intervene. If necessary, amend the Constitution but see that no illegal obstructions or restrictions are put by State Governments as far as the

movement of commodities from one state to the other are concerned. Our general experience is that if there is a shortage of oil-seeds or oil the surplus states give instructions unofficially. When we ask them officially, they say there are no instructions. They issue instructions to the Collector and District Magistrate "Do not talk or move of the oil seeds from this district." This is the way how they operate. I think in this matter Mr. Dharji will be in a position to find a solution. Otherwise he will not be able to control the price situation. We wish him all success as far as the stability of prices are concerned. We may have political quarrels. But if stability of prices is not there, the country will suffer. The people will suffer. So we should arrive at a consensus on this.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar) : If it was an illegal obstruction, how could it not be removed by the then Government?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : Under the Essential Commodities Act, the State Governments have no power without the concurrence of the Centre. But the centre is very clear—Mr. Dharji is very clear on this point—that the Gujarat Government should not put restrictions on the movement of oil seeds. But despite that, the Gujarat Government continues to do that. That is my submission. I thank you very much for giving me this opportunity.

श्री युवराज (कटिहार) : बाणिज्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं बड़ा हृषा हूँ। जूट अठारह प्रतिशत इस देश की आबादी की एक भाग नकदी करता है। जूट भारत की नियर्यत की प्रमुख परम्परागत वस्तुओं में से एक है और विदेशी मूदा अधिक करने वाला सब से महसूलपूर्ण उद्योग है। लेकिन पिछले चार पाँच वर्ष में जूट उद्योग में किलोनी नियर्यत घाँट है इसको खोप देवें। 1974-75 में 31273 लाख रुपये का नियर्यत होता था जो बढ़ कर 1976-77 में 19625 लाख रुपये रह गया। इस प्रकार से जो बहुत विदेशी मूदा अधिक करने की एक मुख्य वस्तु की उपके नियर्यत में नियर्यत घास होता रहा। इससे लिहार

बंकाम भवन इन प्रदेशों के किसानों को वहां के बीचीहर मजदूरों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

इन्होंने जूट के विकास के लिए जूट कमिशनर की नियुक्ति की है। 16-17 इसमें मर्टेटिंग अफसर है और नान-मर्टेटिंग अफसर भी बहुत अधिक है। 13 लाख 27 हजार रुपये प्रतिवर्ष इस पर खर्च होता है न केवल जूट कमिशनर बल्कि आरनीय पटसन निगम जो 1971 में गठित हुआ था इसकी अधिकृत पूँजी पांच करोड़ भी और इस पूँजी से वह किसान का जूट बरीदा करता है। इस देश में सरगण नव्ये इनके कान्दे हैं। जिन घाठ जिलों में इंटेंसिव रूप से जूट की बरीद होती है, आपको जानकर ताजुन आया कि जहां सरकार हारा तीन करोड़ ग्रेयर पूँजी के रूप में और चार करोड़ रुपया क्षण के रूप में दिया गया है वहां यह निगम इतना निकम्मा साबित हुआ है कि रुपया लेने के बावजूद भी यह किसान का जूट बरीद नहीं कर पाता है और जो अविकलन रूप में लोग अवसाय करते हैं, जो सेठ हैं, जो उचांगपति हैं और जो जूट का आपार करते हैं वे जहां 55 रुपये, चालीस किलो के दाम इस निगम की ओर से निर्धारित किए गए हैं वहां वे लोग 40-41 रुपये भर के हिसाब से जूट बरीद करते हैं। यह निगम के केन्द्र के पास किसान जूट लेकर आते हैं तो उनका जूट नहीं लिया जाता है और वे सेठ लोग से लेते हैं। करोड़ों लिंग निपांसों से और बैंकों से क्षण में ये अवसायी लोग लेकर जूट का सौदा करते हैं, जूट बरीद करते हैं। वे लोग पहले से ही किसान को 30-32 रुपये के हिसाब से एदबास कर देते हैं और दो तीन महीने के बाद यह उनका जूट मार्किट में आता है तो उनको वे से लिया करते हैं। किसानों की कहरत यही है रुपये की फ़सल कराने के लिये, कपड़े के लिये, दाम बच्चों के परवरिश के लिये, और इन प्रदेशों में यहां 10 करोड़ भी आवादी ही ही वहां एकमात्र ऐसा जोप जूट ही है, उनके लिये यह लिंग विलुप्त निकम्मा साबित हुआ है,

किसानों का जूट नहीं बारीद पाता है, और जो निर्धारित मूल्य है जूट का अधर उसी दाम पर लेता तो भी किसानों को कुछ हृद तक लाभ ही हो सकता था।

आप देखेंगे कि इस जूट का सम्बन्ध किसानों से है और बंगाल से लेकर बिहार तक जूट मिलें हैं। मैंने निम्नतम अवदूरी विवेयक पर बोलते हुए बिहार की मुख्य मंत्री सार० बी० ए० ए० म० जूट मिल करिहार की तरफ सदन का द्व्यान आकर्षित किया था। उस दिन इच्छाम से भी आरिया बोजूद नहीं इस सिल-सिल में बैठे थे, तांत्र बातें कही थीं, और जूट उद्देश बन्ध होने से वहां के बजूरों का जो दम्पतीय विष्ट है उसका तरक ध्यान दिलाया था। बिहार सरकार ने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिशनर ने और तत्कालीन अम्ब भन्नी जी ने जो केन्द्रीय बाणिज्य भन्नी जी देखी प्रसाद बट्टोपाल्याय वे उनको पत्र लिखा था, और हाल ही में इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिशनर ने, जो जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके प्रशासनकाल में भी कई कई पत्र लिखे आपातकाल में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिशनर, बिहार ने पत्र लिखा है उसका अनिम पैरा पढ़ कर सुनाता हूँ :

"Now, there are two alternatives before the government. The management of the company can be taken over either under section 18A of under 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act but in the former case, an Investigation Committee will have to be constituted by the Government of India and only after getting their recommendation, the take over of the company will be possible. This will take a long time. But in the latter case, the Central Government can immediately take over, revive the company and cut short the time lag. Under the circumstances, it is recommended that the Central Government may kindly take over the management of the company under section 18AA of the Industries (D&R) Act immediately and run this factory. It may also be mentioned that due to financial constraints on the resources of the State Government it will not be possible for the State Government to bear the expenses of running the company. Moreover, the State Government do not have the necessary expertise and manpower to run this factory."

[बी युपराज]

ओर वाणिज्य मन्त्री ने जो बिहार सरकार को पत्र लिखा है उन्हें उसमें साफ़ कहा है कि किसी भी स्थिति में हम बन्द उद्योगों को नहीं ले सकें। अधिकार उन भजदूरों का क्या होगा, यह मैं जानना चाहता हूँ, जो एक, डेढ़ वर्ष से बेरोजगार बना दिये गये हैं मिल के बन्द होने से ? उनके बच्चे सड़कों पर भी भी मांगते हैं। वहां के स्वानीय किसानों पर भी बुरा असर पड़ा है, खास कर सहरसा, पूणिया और बंगाल के आसपास के जिलों में। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां के भजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। कटिहार की यह बड़ी मिल है। एक जूट मिल मृतपुर में है, और दो जूट मिलें कटिहार में हैं, लेकिन सबसे बड़ी जूट मिल मैसंस आर० बी० एच० एम० जूट मिल है जिसमें 3500 भजदूर काम करते हैं। इस मिल के बन्द हो जाने से सम्पूर्ण पूणिया, कटिहार, सहरसा के लोगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। मन्त्री जी ने बेरोजगारों को काम देने का लायदा किया है। लेकिन जो रोजगार में लगे थे और डेढ़ साल से बेरोजगार बना दिये गये मिल बन्द होने की बजह से उनका क्या होगा। इन लिंगों को चलाने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर उस मिल मालिक की इतनी हैसियत न हो कि पूरे मिल को चला सके तो भारत सरकार की जिम्मेदारी होती कि उस मिल को लेकर चलाके और उसमें काम करने वाले भजदूरों को रोखी दे। अगर वह मिल नहीं चलाते हैं, तो भजदूरों का क्या होगा ? 20 हजार लोगों का क्या होगा ? इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ?

इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि हमया अपने मन्त्रिमण्डल में इस मामले पर विचार कीजिये और बिहार का जो यह एकमात्र जूट उद्योग है, उसको दोबारा चालू करने का प्रयत्न कीजिये। अगर इसे टेक-ओवर करना यहै, तो टेक-ओवर करके उस मिल को छोलने की आवश्यकता है। इन लंबांगों के साथ मैं आपकी दिमाण्ड़ का समर्थन करता हूँ।

भी बंबर साल गृह्ण (दिल्ली सर) : सभापति जी, मंत्री महोबय ने जो आद्य सदन के सामने रखी है, मैं उनका समर्वत करने के लिए बढ़ा हूँगा हूँ।

यह डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें दीमार कारखाने हैं, और जितनी भी इकानीमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं, अगर कोई काम न करे, तो वह पहली सरकार की हों या इस सरकार की, तो आधिकार में जिम्मेदारी इसी मंत्रालय पर पड़ती है। महिलाएं भी इसी मंत्रालय से नाराज़ होती हैं। जब तक सारी गवर्नरेंट का को-आर्डिनेशन होकर जीव नहीं निकलती तब तक इस मंत्रालय पर फूलमलाएं नहीं चढ़ सकतीं, इसकी किस्मत में तो बिक बट्ट्स ही लिखे हुए हैं। इस विभाग के मत्री इतने अच्छे हैं कि व्यक्तिगत रूप में कुछ भी कहने को जो नहीं चाहता, लेकिन वो, तीन बीजों के बारे में कहना चाहूँगा ।

एक तो अच्छी बात यह है कि हमारा जो बेलेन्स आफ ट्रेड है उस में 1975-76 में 1224 करोड़ का डेफिसिट था। अब हमें यह आशा है कि यह बेलेन्स आफ ट्रेड हमारे पक्ष में होगा। यह देश में पहला या दूसरा साल होगा, जब कि देश का बेलेन्स आफ ट्रेड हमारे पक्ष में नहीं तो हम इस्पोर्ट यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम। इसके लिये मैं मन्त्री महोबय को बधाई देना चाहता हूँ लेकिन साथ साथ यह बात भी कहूँगा कि वहीं सरकार जो बीजें एक्सपोर्ट करती रही है, उनमें कुछ ऐसी भी बीजें आयिल भी जो जीवन के लिए बहुत चाही हैं, नसेसिटीज़ आफ लाइक हैं। लेकिन उनका उद्देश्य यह था कि एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिये चाहे यहां कुछ भी दाम हो जायें।

मैंने एक सवाल पूछा था कि किसी प्याज और आदान के से एक्सपोर्ट हो रही है ? अगर वह आकड़े देखे जायें तो काफ़ी भावा में हैं। जो भीजें यहां नहीं बिलाई हैं, जिनके दाम बहुत रहे हैं, जूँच बुज्जा के आदान कहाना पड़ता है कि हमारी पहली सरकार ने

गरीबों की कास्ट पर वह भीजें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की है जिसके उन्हें कारेन एक्सचेंज कमाता था। मंत्री महोदय ने माना है कि वह भीजें अब एक्सपोर्ट करनी बन्द कर दी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि सारी भीजें बन्द कर दी हैं या कुछ ही भीजें बन्द कर दी हैं। मैं मात्र कहना कि जो आवश्यक बस्तुएं हैं और जिनकी कीमतें इस देश में बढ़ रही हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास कारेन एक्सचेंज का रिपोर्ट काफ़ी है और 800 करोड़ रुपया हमने बजट में के लेकर भी इसका प्रावधान किया है। अगर उन भीजों की यहां कमी नहीं होगी तो इन्स्टेलेशन भी नहीं बढ़ेगा, समुद्रयोग भी होगा और दाम भी नहीं बढ़ेगे, जैसे कि हम फल, सब्जी एक्सपोर्ट करते हैं और आयल केस भी एक्सपोर्ट करते हैं। 1975-76 के मुकाबले में 1976-77 में चाय 26 परसेंट ज्यादा एक्सपोर्ट की गई, जिस की बजह से हमारे देश में चाय के दाम बढ़ गये हैं। इसी तरह काफी 100 परसेंट ज्यादा और आयल के बढ़ गुना ज्यादा एक्सपोर्ट किये गये। आयल के का सम्बन्ध पश्चिमी और दूध के साथ है। किंतु 48 परसेंट ज्यादा एक्सपोर्ट की गई। मैं किंतु नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे कार्ड दोस्तों के बताया है कि किंतु के दाम बहुत बढ़ गये हैं। इस लिए हमें दालों, जेजीटेबस्तू, किंतु और आयल के आवं उन आप्रवायक बस्तुओं का एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जिन के दाम हमारे देश में बढ़ रहे हैं। पिछली सरकार इन भीजों को एक्सपोर्ट करके एक शाल काम कर रही थी। हमने इस बारे में जो बातें किये हैं, हमें उन्हें पूरा करना चाहिए।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1977-78 में बूरा और सीमेंट को एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन देश में सीमेंट का बाटों है। यह तक इन भीजों का देश में बाटों है, तब तक उन्हें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास कारेन एक्सचेंज रिपोर्ट काफ़ी है।

सरकार ने कुछ भीजों पर इम्पोर्ट डम्पटी बिल्कुल हटा दी है, जिसके बजह से उनका इम्पोर्ट ज्यादा हो गया है। देश में उन भीजों को बनाने वाले जिल्सा रहे हैं कि यहां का माल नहीं बिकता है। मेरे पास इस बारे में कई ट्रिप्रोटेक्षन आए हैं। इसलिए सरकार को एक ऐसी बलेन्ड पालिसी अपनानी चाहिए, जिससे हमारा फ्राइन एक्सचेंज भी इस्टेम्पल हो जाये और हमारे यहां आवश्यक भीजों को कमी भी न हो और उनके दाम भी न बढ़ें। यहां के लोगों को भीजें मिलती नहीं है और हम उन्हें एक्सपोर्ट करें, यह उचित नहीं कहा जा सकता है।

मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ कि जहां 1976-77 के बजट में हैंडलूम के लिए प्लान और नान-प्लान दोनों को मिलाकर 15 करोड़ रुपये का प्रावधान था, वहां इस साल उसको बढ़ा कर 35 करोड़ रुपये कर दिया गया है—इबल से भी ज्यादा कर दिया गया है। यह एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबाल यह है कि हैंडलूम उत्तोग के सामने जो प्रावधान है, और इस बारे में हमारी पार्टी की जो नीति है, क्या उसको देखते हुए यह प्रावधान काफ़ी है या नहीं।

मंत्री महोदय को मालूम है कि महाराष्ट्र में हैंड-रीवर्स के सामने कितनी समस्याएं हैं। देश के बहुत से प्रदेशों में, जिन में जिल्सी भी जामिल है, उन्हें सूत नहीं मिलता है, और अगर भूत मिलता है, तो उन्हें प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का ढंग नहीं आता है, और उन्हें ट्रैकिंग-नो-हाऊ नहीं दिया जाता है। बजट में हैंडलूम के लिए डाई गुना ज्यादा प्रावधान किया गया है, लेकिन अगर हम एप्पलायमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारा कमिट्टीमें है,—हम केवल नारेबाजी नहीं करना चाहते हैं और हम लोगों को यह कहने का भीका नहीं देना चाहते हैं कि हमने घरने वाले भी नहीं किये हैं—, तो मंत्री महोदय किसास

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

मिनिस्टर साहब को चाहे इस बजट में, और चाहे सभी मेंटरी बजट में, हैंडलूम के लिए ज्यादा प्रबोधन रखने के लिए कहें।

सरकार ने सिक टैक्सटाइल मिलों को घरने हाथ में लिया है। वहाँ 1975-76 में 57 करोड़ रुपये का आठा है। 57 करोड़ का आठा है। अब एक साल में सिक मिलों का 57 करोड़ का आठा और यहाँ सारे देश में हैंडलूम को जिसके लिए हमारी पार्टी बचनबद्ध है उस को आप 35 करोड़ रुपया दें यह ठीक नहीं है। यह राजि पहले इनके हिसाब से तो ठीक थी। लेकिन जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से बहुत कम है। इसकी और 'भी मंडी भांडेवय ध्यान दें। इससे एम्प्लायमेंट भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, परवेंजिंग को मिट्टी भी बढ़ेगी। टैक्सटाइल मिलों में आज आप देखेंगे स्टाक पड़ा हुआ है कंट्रोल कलाय का। आपने उनसे कहा कंट्रोल कलाय बनाने के लिए, वे बना रही हैं लेकिन उसका सारा स्टाक वहाँ पड़ा हुआ है। कोई खरीदने वाला नहीं है क्योंकि गांव वालों की परवेंजिंग कैपेचिटीन ही है। जब तक परवेंजिंग कैपेचिटी नहीं बढ़ायी जायेगी तब तक चीज़ बेचा भी कर लेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ग्रन्था यह होगा कि लोगों की परवेंजिंग कैपेचिटी बढ़े और मैं यह जांचूंगा कि 35 करोड़ की जगह 100 करोड़ रुपया हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए मिलना चाहिए, तब इसकी युक्तियाँ होंगी। मुझे नहीं मानूम कि मंडी मंडावय की क्या प्रतिक्रिया इसमें है।

एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 63 ट्रेड मिशन्स हैं जो जिवेशों में काम करते हैं। उनके ऊपर सबा दो करोड़ रुपया जर्चे होता है उन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेज के रूप में। मैं दस बारह बार जिवेशों में गया हूँ और मैंने देखा कि हमारे ट्रेड मिशन्स वह काम नहीं करते जो उन्हें

करना चाहिए। अबी का कुछ भी नहीं मानूम है कि पिछले तीन महीने में क्या हुआ लेकिन कास्टीन्यूटी आफ आफिसर्स तो वही हैं, दो चार, पांच आप बदल सकते हैं, सारे तो नहीं बदल सकते हैं और बदलना चाहिए भी नहीं। देट्रेड मिशन्स बास्टर्ड में ट्रेड पर बहुत कम ध्यान रखते हैं। ट्रेडर या इंडस्ट्रियलिस्ट जो उन से गाइडेन्स चाहते हैं, उनकी चिढ़ी का जबाब भी वे नहीं देते। मैं जांचूंगा कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो। जोड़ा उनको और टाइट करने की आवश्यकता है। हर तीन महीने के बाद हर ट्रेड मिशन की रिपोर्ट आनी चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया, कितना ट्रेड पहले या, कितना बढ़ा, क्या याइडेंस उन्होंने दी। यह रिपोर्ट आप उन से मंगाते रहेंगे तो इसका लाभ हो सकता है।

कंट्रोल कलाय के बारे में मैंने कहा कि स्टाक पाइलिंग हो रहा है और दुष्प्राप्य से सरकार ने 1974 में तीस प्रतिशत दाम कंट्रोल कलाय का बढ़ा दिया। उसके बाएँ अभी जनवरी 1977 में 35 प्रतिशत दाम बढ़ा दिया। करीब एक डेव साल में 65 प्रतिशत दाम एक्सेम बढ़ा दिया। उस में बबलेंमेंट को सम्बिली देने में करीब 24 करोड़ रुपये की हानि होती है। अबी आपने इस बजट में भी एक प्राविजन किया है कि कपड़े के ऊपर कुछ इयटी में बदल की है, उसका भी द्वारा कुछ गलत हुआ है। मूले पता नहीं आपका ध्यान इसकी तारक बया है या नहीं। वह कलाय अनजाने में हो गया। काइन कलाय पर आपकी इयटी कम हो गई और कंट्रोल कलाय पर इयटी ज्यादा हो गई। कल मैं एक जांची में गया था। कपड़े जालों के बहाँ जांची थी तो वे बजाक करते रहने कि यह जनता पार्टी की सरकार ऐसा काम करती है, लूकांकि उन को तो फ़ज़ाहा हो जाय। उन्होंने ही मुझे बताया, किरण जैन आकर उसको ऐक किया तो मुझे लाज़ कि यह बात ठीक है। तो आप इसको भीक कराइए। कंट्रोल कलाय पर ज्यादा इयटी नहीं बढ़नी चाहिए। यातेर वहाँ जैन के हाज़ार

वी वही रहे या उसके कम दूरी पड़नी चाहिए और पर्यावरण कोरिस्टी बढ़ाने की भी आप कीचित्करें।

आपने मिल टैक्सटाइल मिलों के लिये एक नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन बना रखी है, उसमें 103 या 104 मिल हैं, लेकिन इस बक्त काम ज्याद 101 मिल कर रही है। देश के टोटल काटन-टक्सटाइल का 20 प्रतिशत उत्पादन इन मिलों में होता है और इन लाख लकड़ियों इन मिलों में काम करते हैं। यह एक तरह से काफ़ी बीमार मिलों का अस्पताल है, जिसकी जिम्मेदारी मंजूरी गदोदय पर आकर पड़ी है। जब कोई बीमार थम तोड़ने लगता है तब उसको इन अस्पताल में ले जाया जाता है। इसनिये मैं आपकी भजबूरी को समझ लगता हूँ। इसी का लह परिणाम है कि 1975-76 में 57 करोड़ रुपये का बाटा थआ, 1976-77 में 31 करोड़ रुपये का बाटा थआ और इस बजट में भी आपने 19 करोड़ का बाटा इसमें बताया है। आप इन मिलों के मोर्डाइजेशन, एक्सप्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है और इसके लिए काफ़ी ऐसा इस साल भी— ज्याद 58 करोड़ रुपया—इसमें रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इन में भी भी जो मिलें बीमार हो रही हैं, जिसकी इकानमी ठीक महीं हो रही है, वह ज्याद इसलिये है कि उनको जान-बूझ कर बीमार किया जा रहा है। मुझे यह है—संजय साहब के मानक में 10-10 रुपये के सिर्फ़ 100 रुपये के भेयर हैं, यद्यपि यह कहा जा रहा है कि उसको गवर्नरेंट टेक्सोबर करें। करोड़ों रुपया उस में सरकार का, जनता का दूब गया, लेकिन संजय बाबू का सिर्फ़ 100 रुपये का नुकसान हुआ। इसी तरह से मैं सिक्के मिलें हैं—ये जिसने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, ये जेत खेलते हैं, पहले उसका सारा सज्जा आ जाते हैं,

उसका पूरी तरह से खून चूस लेते हैं, जब उसमें नुकसान होने लगता है तो नुकसान सरकार के हाथों कर देते हैं। यह अच्छी बात है कि आपने कह दिया है कि हम सिक्कमिल्स को नहीं लेंगे, उस के लिये दूसरा रास्ता आपने बताया दिया है। लेकिन मैं यह सुनाव देना चाहता हूँ कि आप अपनी कामसं मिलिस्ट्री में एक इन्टेलिजन्स विभाग बनाइये, जो इस बात की जांच करे कि कौनसा एक्शन किस इण्डस्ट्री का जेन्डर है और कौन-सा गिरिजाधारी यहाँ सामने आ सके और जब बहुत मजबूरी हो, तब ही उसको लेने की कार्यवाही होनी चाहिये।

मेरे अपने इलाके में भी एक कपड़े की मिल है, वह काफ़ी भिस-भेनेज़ है। पांच-साल साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि कोई आई० ए० एस० आफिसर वहाँ आकर बठ जाता है, जिसको इतना भी मालूम नहीं है कि मिल क्या होती है और कैसे चलाई जाती है। अगर आप के पास समझदार आदमी या अनुभवी आदमी नहीं हैं तो आप लोगों को देन कीजिये। जब 100 से ज्यादा मिले आप के पास हैं तो इन को चलाने के लिये एक ट्रैक्टर-कंडर आप के पास होना चाहिये। जिस को इण्डस्ट्री का जान नहीं है, ऐसे लोगों को इन मिलों को चलाने के लिए भले भीजिये, उनको देन कीजिये, एक्सोकेशन दीजिये, ताकि वे उनके सफलतापूर्वक चला सकें। एक तो पहले ही इन मिलों में काफ़ी कर्पॉरेशन है, किर किसी आई० ए० एस० या आई० पी० एस० अफसर के भेजने से बह करपान या गडबड कम नहीं होती है और ज्यादा बढ़ जाती है—इसको रोका जाना चाहिये।

यह मैं मुख्य सवाल की तरफ आता हूँ, वह है—आम रोकने की बात। यह देश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसके-

[श्री कंवर लाल शुप्त]

अमर ही हमारी फरफौरेंस का जजमेंट होगा। जनता हमें इसी चीज़ को लेकर जाचेगी, वर हमने दामों को बढ़ाव से रोक लिया, तब तो ठीक, बरना इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। मैं यह देख रहा हूँ—इस देश की सबसे बड़ी प्रभारिटी—हमारे प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी भाई ने दो बार अपील की। उसके बाद इण्डस्ट्री वालों का एक स्टेटमेंट भी निकला। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ—इण्डस्ट्री के लोग—मैं सबके लिये नहीं कह रहा हूँ—लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं, जिन के रामेंटीरियल के दाम गिरने के बाद भी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट के दाम नहीं गिराये हैं। आपने जो रिपोर्ट पेश की है—मुझे दुख के के साथ कहना पड़ रहा है—दामों को बढ़ाने से रोकने के लिये उसमें केवल दो पैराग्राफ हैं। मैं उन्हीं को पढ़ने के लिये उत्सुक था, लेकिन उनमें आपने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि आप दामों को कैसे ठीक रखेंगे, अब तब इस दिशा में आपने क्या किया है और आगे क्या करने जा रहे हैं? आपने कन्यूमर कोसिल की बात कही है—लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप आपने मन्त्रालय में इसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कीजियें। एक चीज़ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इण्डस्ट्रीज का और खास तौर से जो नेसेसिटीज आक लाइक की इंडस्ट्रीज हैं, सबे करवाइए, कि जिस दाम पर ये चीज़ें बेची जाती हैं और जो उनकी कास्ट आती है, उसमें कितना अन्तर है। मेरी मांग है कि एक सीलिंग आफ्र प्रोफिट होनी चाहिए जिप्रोड्यूसर को, इण्डस्ट्री वालों को इतना प्रोफिट होना चाहिए, इतना प्रोफिट मिडिलमैन का होना चाहिए और इतना प्रोफिट एक रिटेलर का होना चाहिए। जब तक सीलिंग आफ्र प्रोफिट नहीं होगी, चाहे वह फार्मली हो या इनफार्मली और खास तौर से नेसेसिटीज, आक लाइक की तो जहर होनी चाहिए, तब तक हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कन्यूमर को कुछ राहत मिल सकेगी। टेरेलीन के कपड़े को

ही आप लें। उसमें 50,50 परसेन्ट प्रोफिट लिया जाता है और मुझे मालूम है कि फारेन गवर्नमेंट्स को तो 100, 100 और 200, 200 परसेन्ट प्रोफिट लेकर बेचते हैं। इन सब चीजों को रोकने का काम आपके मन्त्रालय का होना चाहिए।

सुपर बाजार के बारे में मुझे यह कहता है कि दिल्ली में जो सुपर बाजार तरह हूँगा, तो वह फैनाट प्लेस में बुला और उसकी ओ बार, पांच बाजेज है, वे भी शानदार इलाकों में ही हैं। उस सरकार ने इस काम को किया था। उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए उन को रोजाना बुरा कहना ठीक नहीं है लेकिन मैं अपने मन्त्री जी से कहूँगा कि वे सुपर बाजार या डिपॉटेंटल स्टोर जो खोले वे कारीब बस्तियों में खोले और भारी मात्रा में खोले। जो भी गन्दी बस्तियाँ हैं वहाँ पर इन को खोले और वहाँ पर लोगों को सब बस्तुएँ मिलनी चाहिए, रोजाना इस्तेमाल की जीवं मिलनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, उनको कोई लाभ नहीं होगा।

एडिबिल आयन का जो इमोर्ट का किस्ता है, उसके बारे में अमीन साहब ने कह दी दिया है और मैं उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहता। वह एक बहुत बड़ा स्ट्रेंग्ल है और उसका कुछ इलाज आप ने किया भी है। इसमें जो विस्त्रित एक्सिमेंट है, उसको सभा मिलनी चाहिए और सी० बी० भाई द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सारी बातें इस सदन के सामने आ सकें कि किन लोगों ने क्या क्या गहबदियाँ की हैं और जिन लोगों ने सरकार की ओका दिया है उनके साथ हमें नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे देश में कारीब 2 लाख 40 हजार फैयर प्राइस वाप्स और केरोलिन आयल की शाप्ट हैं और अब 1,000 शाप्ट और खोलेंगे। मैं समझता हूँ कि वह टोकन संक्षण है लेकिन मैं चाहूँगा कि जो नेसेसिटीज

धारा लाइक है इनकी व्यवस्था धारा उन दुकानों पर भीर विशेष कर गांवों में उन दुकानों पर कर सकें, तो अच्छा होगा। गांवी बस्तियों में भीर गांवों में जो ऐसी दुकानें हैं उन पर धारा इन गांवों को दीजिए जैसे कपड़ा है, साड़न है या दूसरी भीर छोटी छोटी व्यवस्थक गांवों हैं। इस तरह की व्यवस्था सरकार कर सकती है।

इन गांवों के साथ जो भवनदान की मार्गे भवनी जी ने देश की हैं, उनका मैं समर्पण करता हूँ भीर मैं यह आशा करता हूँ कि हमारे भवनी जी इन समस्याओं को सुलझाएंगे जिस से कि हमारी समस्या भी आगे सुलझ जाए। हम भीर वे एक किसी में बैठे हैं। यह किसी चलती रहनी चाहिए, यही मेरा कहना है।

भी बस्तन जाटे (प्रकोला) : मध्यापति महोदय, पहले तो मैं श्री मोहन धारिया जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन जैसे प्रगतिशील, उत्साही युवा भवनी को यह बड़ा महत्वपूर्ण भवनकामा मिला है, जो यदि कामयादी से बस सका, तो इस देश की जनता का भास्य बदल सकता है।

साधापति महोदय, मुझे मालूम है कि पहले जब मैं भवनी थे तो किस दुबिया में उनको बहुत बार काम करना पड़ता था और एक चूटन सी बहसूस होती थी और अपने इरादों को, भवनी आकांक्षाओं को भीर अपनी कल्पनाओं को भे धमनी जामा नहीं पहला पाते थे। अब मैं आशा करता हूँ कि नई सरकार में उन्हें पूरा पूरा भीका मिलेगा तो बहुत कुछ काम जैसा मैंने कहा भीर मेरे मिल भी कंवर लाल गुल जी ने नहा है, वे कर पाएंगे।

रिपोर्ट तो धारकी भवनी तक मिली नहीं, वैर जो सिविल सर्प्लाई मिनिस्ट्री का बजट मिला है, उससे हमें कुछ जानकारी धारके परफोर्मेंस के बारे में विज्ञती है। उससे लो-890L.S.—3

तीन बातें सामने आती हैं। एक तो यह है कि जहां तक कीमतों का सवाल है, उन कीमतों को रोकने में हम असमर्थ रहे हैं। हालांकि कुछ समय के लिए, जैसा कि आपने रिपोर्ट में कहा है, 1974 में होलसेल हैंडेक्स 183.4 था। यह सितम्बर में था। मार्च, 1976 में यह हैंडेक्स 162.2 पर आ गया। पर्याप्त, यह 11.6 घिर गया।, लेकिन अब फिर से यह बढ़ कर 182 से ऊपर चला गया है। यह भी चित होलसेल की है। हम लोग तो जीजें ट्रिटल में खरीदते हैं। प्रतिदिन हम लोगों को यह करना पड़ता है। महाराष्ट्र में मुझे मालूम है, यहां भी यही हाल होता, तेल जो पहले 6 रुपये किलो तक नीचे आ गया था, अब फिर 11 रुपये साढ़े ग्यारह रुपये पहुँच गया है। आम आदमी रोज के जीवन में तेल, नमक मिर्च का उपयोग करता है सूखी रोटी खाकर ही उसका जीवन चलता है। अब अगर ये ही जीजें महंगी हो जाएं तो उसके जीवन पर कितना असर पड़ता है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस सब की क्या बजह है? क्या देश में तेल का उत्पादन कम हो गया है? ऐसी बात भी नहीं है। आपने इकोनोमिक सर्वे में जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता चलता है कि 75-76 में तेल का रिकार्ड उत्पादन था, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ। अब इतना उत्पादन होने के बाद भी कीमतें कम नहीं होतीं। यह क्यों होता है? यह सब इसलिए होता है कि हमारी वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। इस पर जरा गहराई से संचिए। हमारी वितरण व्यवस्था पर हमारा कोई काबू नहीं है। सारी वितरण व्यवस्था डिमार्पण और सम्पाद्य पर आधारित है। साधापति जी, मान लीजिए बाजार में किसी जीज की मांग है तो उसके लिए बाजार तो होता ही। जब बाजार होता तो उस जीज का बेचने वाला भी होगा। लेकिन जब उस जीज की पूर्ति नहीं होती तो स्वाभाविक है कि कीमतें बढ़ेगी। अब जारीबार धारके

I have said it before and I say it now.

"This mixed economy is the biggest unmixed, unmitigated evil"

Whichever Government is there, there will be no solution to your problems. You can't take years.

[**श्री बसंत साठे]**
 यहां है, बेचने वाला भी है लेकिन क्या उसका उत्पादन जल्दी के मुताबिक नहीं हो रहा है हमारे यहां नीड बेस्ट, डिमान्ड बेस्ट प्रोडक्शन नहीं होता। सभापति जी आप कितनी भी ऊँची बात करें, बुनियादी बात यह है कि खरीदार देश में है और बेचने वाला भी है लेकिन मं रेलिटी नहीं है। मार्किट मारेलिटी की बात होती है। मारल बैल्यूज की बात की जाती है। लेकिन वह चीज़ यहां नागृ नहीं होती है। जब यह होगा तो आत्मा भी बेची जाएगी। इसलिए उनको अपील बार-बार करना, मैं नहीं समझता हूँ का यादमन्द साकित हो मैकता है। इसका कारण यह है कि वे अवधार कर रहे हैं। उनको मुनाफा चाहिए अपनी चीज़ का और जहां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलेगा वहां वे उस चीज़ को बेचेंगे। इस बास्ते उनको कासने में काई लाभ नहीं है। एक प्रेस गिल्ड के सामने शायद पूना में आयण करते हुए श्री मांहन धारिया ने यह कहा था।

He said "He had been criticised for his views on trust in man and trust in trade. But this was the philosophy to which the Janata Party was pledged and it was strongly believed that by and large the society was honest."

उन्होंने कहा कि स्थान बीइंज़ बाई एंड सार्ज़ आनेस्ट होते हैं। लेकिन जब वे अवधार में और मार्किट में खड़े हों जाते हैं बेचने के लिए अपने आप को तो उनकी सारी की सारी मारेलिटी वही हो जाती है। उसमें आपका ट्रस्ट क्या काम करने वाला है? इस बास्ते आप अपने आप को गुभराह न करें। मैं कहता हूँ कि इस देश में यह जो मिश्रित अर्थ व्यवस्था, मिक्स्ड इकोनोमी की फिलोसोफी हमने शुरू की थी और हमने यह आगा की थी कि इसके बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे लेकिन उससे पैदा होगा मोनस्टर। (*Interruptions*)

इसलिए यह कह रहा हूँ कि निजी क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर में क्या पैदा होगा? जो उंकीज वक़्त होगा वह पब्लिक सेक्टर में होगा। बुनियादी चीज़ें वहां पैदा होंगी जैसे लोहा, कोयला, पावर, जनरेशन और सारी कंज्यूनर गुडज जहां घरसली प्राकिट होता है वे जिस के हाथ में रहेंगी? निजी क्षेत्र के हाथ में रहेंगी। सारा काला धन कहां पैदा होता है? निजी क्षेत्र में ही तो पैदा होता है। किसना हुआ है? दीस हजार करोड़ पैदा हुआ है। एक प्रैरेलल इकोनोमी बल रही है। आपकी राष्ट्रीय आप तो उन्हींस हजार करोड़ और काला धन है दीस हजार करोड़। क्या कन्ट्रोल करने वाले हैं आप? किसने ही बड़े मिलिस्टर हों कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप बास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो एक अर्थ व्यवस्था आप काम करें। मैं ट्रेडज़ के खिलाफ नहीं हूँ। आपको ट्रस्ट करना है करें, उनके अपर आप निर्भर रहें लेकिन एक सेक्टर आप बनाएं। आपकी करपोरेशन के बे मुखिया हो सकते हैं, उनको आप इचार्ज बना सकते हैं। तब आप उनसे कह सकते हैं कि वे ठीक कीमत पर माल को दें। होलसेल और एटेलर का क्या मार्जिन होता है? होलसेलर का डेढ़ दो परसेंट होता है और एटेलर का तीन परसेंट। आप 105 रुपये में गेहूँ बरीबते हैं। अब वह 110 रुपये में मिलना चाहिये। क्यों कहीं कंज्यूनर को कहीं इस भाव पर मिलता है? बदलई में जिस दाम में बिकता है इसको आप दें। बिना किसी का नुकसान किए आप उनको राष्ट्रीय डिस्ट्रिब्यूशन में बढ़ों नहीं लाते। क्यों आपने उनको क्षृद्ध दे रखी है। किस आप कहते हैं कि उनको हम सबस्टीट्यूट करें एवं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से। माफ करें हमीं बहल में आप क्या कहते हैं:

"He thinks that the Government did not have enough power under the Essential Commodities Act to bring down the prices. He also thinks this as the inability of the Government do so in the absence of adequate buffer stock."

तो परिवहन बिल्डिंग्सन मिस्ट्रीमें आफ बकर स्टाक बनायेंगे, और हैडस का खर्च करेंगे, दाई लाल कंपने प्राइस गोप्प बनायेंगे। और इतना सारा खर्च कर के फिर भी प्राइवेट सेक्टर आल रहेगा जो प्राइवेटसेक्टर अपने आपको जिन्हा रखने के लिये आप की इकोनामी को चलने नहीं देगा। इसलिये प्राइवेट सेक्टर और परिवहन सेक्टर यह डायर्को खत्म कीजिये। एक सेक्टर बनायें। प्राइवेट सेक्टर बाले भी राष्ट्र के नागरिक हैं, उन्हें नुकसान न पहुंचाते हुए एक डिसिप्लिन में लाहये। संक्ष उसको आप आहे जो दें, एक डिसिप्लिन जो अन्दर यदि ला दिया तो आप की समस्या हल हो सकती है। फिर कीमत बढ़ने का सबाल नहीं है, क्योंकि जो भी उस नियम के बाहर आवश्य उसको आप सजा दे सकते हैं, उसका शाइर्सेस कैसिंस कर सकते हैं।

Let every trader be member of that national sector, whatever you may call it, and not outside that.

यह एकमात्र रास्ता है इस देश को आगे ले जाने का। मैंने इस पर बहुत चिकार किया, लेकिन युजे तो कोई रास्ता नहीं दीखता। इसी तरह से यदि चलते जायेंगे तो आप भी उसी नहीं में चिरने वाले हैं जिसमें हम निरत हैं। अमरपलायमेंट बढ़ेगा।

26 अक्टूबर,

स्माल सेक्टर की आपने तारीफ की और कहा कि उसमें उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और एमप्लायमेंट पोटेंशियल भी ही है। आपने यह बताया कि आर्गेनाइजर सेक्टर में, परिवहन सेक्टर में ज्यादा एमप्लायमेंट मिलते। अब स्माल सेक्टर में ज्यादा हैडलूम ले जीजिये। अच्छा हो गया जीवंती चरण तिह जी आ जये, और आपके लिये भी आ जये (भी राज नारायण) समाप्ति भी, हैडलूम सेक्टर में 20 लाल

हृष्टुम्बों को आजीविका मिलती है। करीब व 40 टाका टोटल कपड़े का उत्पादन उस सेक्टर में होता है और 20 लाल हृष्टुम्बों के समस्य भी काम करते हैं उस में। मतलब यह कि तकरीबन एक करोड़ लोग काम करते हैं। और मिल सेक्टर में 7 लाल लोग काम करते हैं, लेकिन किर भी सारे देश की दौलत मिल सेक्टर में है। एक टक्सटाइल पौलिनी काटन टू स्लाय आप टैक्सटाइल में चालू नहीं कर सकते? क्या हो रहा है कि सिक घिने गई हो उसको ले लो। इससे काम नहीं चलेगा। मिल मालिक उसका पहले बून बूस ले और बीमार कर दे और फिर हम उसको ले लें। अब दूसरा नुआह क्या करने वाले हैं कि जो अच्छी मिलें बलाने वाले हैं वह उन सिक मिल्स को ले लें। तो इससे काम नहीं चलेगा काटन प्रोड्यूस करने वाले किसानों को काझी नुकसान हो रहा है। पर एकड़ प्रोडक्शन इस देश में कम हो रहा है। जब ज्यादा उत्पादन किया जान्धा में और महाराष्ट्र में, 70 लाल बेच तक उत्पादन हुआ 1974-75 में तो आपने किसान को तबाचा मारा और काटन के दाम चिरा दिये। नतीजा यह हुआ कि दूसरे साल उत्पादन घट गया। इस्पोर्ट पर आप 100 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, लेकिन अपने किसानों को बोहा ज्यादा दाम देने को तेवार नहीं है। कोई कोइंस्ट रेलवाय आपने कभी निकाला है? एक कमेटी बैठायी भी उसकी रिपोर्ट भाँगायें, यिदिलवैन किलाना जाये जला जाता है। एक महाराष्ट्र में भोजपुरी लुक है, बरा काढ़ोल आया तो आपने उनको कहा हम तुमको पसा नहीं देंगे। सारे देश की काटन कार्पोरेशन को आप कितना रुपया देते हैं? 200 करोड़ रुपया आहिये। सेकिन देश में टर्न और बाक काटन के लिये 20 करोड़ रुपया देते हैं और आप सबसे हैं कि काटन की प्राइसेस को काढ़ोल कर लेंगे? यह क्या भजाक आप करते हैं?

आप काटन और स्लाय की पालिसी जीजिये, मैं आपसे कहता हूँ कि किसानों के

[वी बसन्त सांड]

सावधान्य होगा तो वह अच्छा कपड़ा पैदा कर सकते। पीछे आजोक मेहता कर्मीशन बना, श्रम बने, किसी नहीं रिपोर्ट आई लेकिन कुछ नहीं हुआ। हैंडलूम सेक्टर के लिये आप धोती साड़ी रंगीन रिजर्व करिये, फिर देखिये कैसे अच्छा कपड़ा पैदा नहीं होगा। जितने चिल हैं, उनको टिप्पणिग मिल में कन्वर्ट कीजिये, यार्म सप्लाई कीजिये। हैंडलूम अच्छा बने तो तो क्यों नहीं लोग उसे लेंगे? सस्ता भी बनेगा और एस्ट्रायमेंट भी लोगों को मिलेगा। पावरलूम मिल की सबसीडियरी है, और कुछ नहीं है। भिरणडी में क्या हुआ, एकसाथ बचाना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि एक ही कलाय सैक्टर को अगर आप श्री चरण सिंह जी के आकार्तिक में एक डेंड्र भाल में रिकार्डोनाइज कर लें तो सारे देश में कान्ति हो जायेगी।

अगर मार्केटिंग होगी, तभी गांव में चीज़ पैदा होगी। आज समस्या यह है कि गांव में पैदा होने वाले भाल को बेचेगा कौन, खरीदेगा कौन? आप उत्पादन भ्राता भार्कोटिंग अपने हाथ में ले लें, एक सैक्टर बना दें, सारे प्राइवेट सैक्टर को उसमें भाल दें तो मेरा कहना है कि देश में 60 करोड़ लोग हैं, उनमें से 30 करोड़ हाथ चीज़ उत्पादन करने लगे जायें। अपने केवल देश के अग्नात ही वहीं परदेश में भी भाल भाल बेच सकते हैं। आप दूसरे क्षेत्रों को फाइन और सुपर फाइन बना कर, गार्मेंट्स बना कर एक्सपोर्ट करें। पर हिन्दुस्तान के जोख ये काटन पैदा कर, उससे हिन्दुस्तान के लोगों को तो कपड़ा मिल सके। गांव गांव में दूसरी चीज़ें पैदा हो सकती हैं, पर उसकी जड़ दो भार्कोटिंग है। कोई भी चीज़ देहात में दूसरे पैदाने पर पैदा नहीं हो सकती अबर यास उत्पाद प्राइवेट सैक्टर में कम्पीटीशन में शाम देंगे, चाहे वह को-ऑपरेटिव में बने या कुछ बने, वह बिक नहीं सकती है क्योंकि लीबर फ्रेडर के साथ क्या कम्पीटीशन करेगा।

यहां किसी पार्टी का सवाल नहीं है, देश की इकानामी में हम सब सोब आगे साथ हैं। जैसा मैंने जूह में कहा कि भेहरवाली करके मिक्सड इकानामी का मान्स्टर बत्त्य करिये। प्राइवेट सैक्टर को भी आप एक राष्ट्रीय सूच में ले आयें, उनका नुकसान नहीं करना है। आप उनको काम में लगाय, ट्रेडर्स को काम में लगायें, होलसेलर्स को काम में लगायें, मूर्जे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन भेहरवाली करके अंग्रेजेसी को काम में भत लगाइये। क्या इनका काम है इण्डस्ट्री को बलाना? जो भी नहीं कार्पोरेशन बनती है, उसमें फोरन अंग्रेजेसी आ जाती है।

इसलिये इन खतरों से सावधान रहने हुए मैं आगा करता हूँ कि हमारे वित्र श्री आरिया जी कुछ कर पायेंगे, हमारी दड़ी जूह-कामनाएं उनके साथ हैं। हमको बुझी है चलो देश का भना उन्हीं के हाथों से हो जायें।

*SHRI A. MURUGESAN (Chidambaram): Mr. Chairman, Sir, on behalf of my party, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to say a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Commerce.

It is really a matter of great satisfaction that the exports of our country during 1976-77 reached the figure of Rs. 4,981 crores, the highest in the last thirty years. At the same time, it has to be borne in mind that the rise in international price of commodities is the main cause of this significant growth, and definitely not due to the increase in the quantum of exports. The price of our traditional items like tea, sugar, coffee, leather, leather products, pepper etc. in international markets showed an upward trend and in consequence our exports in value went up considerably. So this should not lead us to any complacent attitude in the matter of our exports.

It cannot be denied that sugar export is subsidised substantially. We sell sugar at 75 paise per kilo in the international market. Within the country the price per kilo of sugar is Rs. 4.50. For example, if our export earning through sugar is Rs. 100 crores, the sugar-mill owners in the country get a subsidy of Rs. 600 crores. This huge

*The original speech was delivered in Tamil.

sum does not come from the Government's coffers. The sugar-mill owners are permitted to sell at Rs. 4.50 per kilo within the country to offset their loss in selling sugar at 75 paise per kilo for the sake of export earnings. With this bounty the sugar magnates dabble in politics. The common people are unfortunately the pawns in the game of chess between the Government and the sugar-mill owners.

It is also a matter of concern that our share in international tea market is declining. The tea export of Sri Lanka is considerably larger than our tea export. I would like to know the reason for this fall. We are exporting unmanufactured tobacco. I wonder why we have not so far tried to acquire the technical knowhow for producing tobacco to suit the taste of international connoisseurs. The Imperial Tobacco Company has perfected this technique and it is exploiting our ignorance in this matter. Huge sums are remitted to the Head Office account in foreign land. Last year our exports to East European countries have fallen. While we can rejoice that our exports have picked up in the case of ECM countries, the fall in our exports to East European countries must be investigated by the Government. We are earning in foreign exchange to the tune of Rs. 236 crores in the export of leather and leather manufactures. The State of Tamil Nadu contributes nearly 60% of this earning. On account of certain restrictions imposed on the export of semi-leather, the leather trade in Tamil Nadu has come to grief. I request that the Central Government should enquire into this and do the needful.

In our exports, the traditional items play a major role. Similarly, we seem to be following a set pattern in importing traditional items like wheat and such other food items. The barometre of a nation's economic progress is more and more export of engineering goods and less and less import of traditional food articles. Besides any other economic indication, our country's export and import trade shows clearly our under-development both in industry and agriculture. During April-December, 1976 we imported foodgrains, worth Rs. 1,425 crores and the value of import of fertilisers during this period was Rs. 1,120 crores. Out of the total import bill of Rs. 3,592 crores, these two come to Rs. 2,545 crores. I do not think we require any other confirmation for our economic backwardness.

What is the institutional set-up for achieving this much talked about export miracle? We have the Trade Development Authority, State Trading Corpora-

tion, Metals and Minerals Trading Corporation, Handicrafts and Handlooms Corporation, Tea Trading Corporation, State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation. Let us see the performance of the last mentioned institution. It has imported huge quantities polythene granules from Japan. As a result, a few thousands of small industries engaged in the manufacture of polythene bags, sheeting and tubing are on the verge of extinction. You will appreciate that within the country the I.C.I. is manufacturing polythene granules and this concern could have been encouraged to push up its production schedule to meet the growing needs of polythene granules. No, this State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation, in order to justify its existence, must import polythene granules from Japan, which in turn would curtail the indigenous production. We cannot afford to waste the valuable foreign exchange in such unwanted things.

The National Textile Corporation is functioning under the aegis of this Ministry. Recently, the hon. Finance Minister stated that this concern has incurred a cumulative loss of Rs. 114 crores. With a view to revitalise the sick textile mills, which would enable greater production of standard cloth and also cloth for export, the Government took over these textile mills. Neither the production of standard cloth has gone up nor the cloth for export market. This House is aware of our dismal export performance in readymade garments. The hon. Minister is duty-bound to explain to this House the reasons for such a sad performance.

Before I conclude, I would urge upon the Janata Party Government at the Centre that it should prune the sprawling empire under the Commerce Ministry. Our Embassies abroad can be activated for meeting our requirements in export trade. I will illustrate this point by referring to the Trade Development Authority in Parliament Street, which has been entrusted with the duty of looking after our exports. Highly paid officials are adorning the air-conditioned rooms. If you go inside to enquire about potential export channels, you are confronted with a list of companies located in different countries and you are advised to contact them. Should we have this white elephant of TDA to prepare such a list? Similarly, you go to STC and try to find out about import possibilities. You will be given a detailed lecture. All the literature brought out by STC must be published in all the regional languages. I emphasise this point because the STC officials are highly discourteous towards traders who do not know English or Hindi.

[Shri A. Murugesan]

I request that the hon. Minister may try to give clarifications in his reply to the debate on the points I have raised.

With these words I conclude my speech.

श्री मुरुगेसन प्रसाद वर्मा (चतरा) : सभापति महोदय, मैं इस मान्य का समर्पण करते हूँ दो तीन बातों की ओर ध्यान ध्यानपूर्णता करता चाहता हूँ। मूल्य के सम्बन्ध में और सहकारिता के संबंध में विशेष रूप से मैं निवेदन करता हूँ। मूल्यों में बृद्धि हो रही है इस से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह बृद्धि क्यों हो रही है इस के बारे में विभिन्न भवित हैं। सब से उत्तम बात यह आती है कि मूल्य की बृद्धि इसलिये है कि उत्पादन कम हुआ है। यह कारण बहुत मान लेते हैं। लेकिन मेरी इस में असहमति है। मैं उत्पादन हूँ कि अगर उत्पादन की कमी के कारण मूल्य बृद्धि होती, उत्पादन अगर कम होता तो देश में जितने सोग है उन्‌जितनी आवश्यक बस्तुयों आहिये उस की पूर्ति नहीं होती जाहे मूल्य कितना भी होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता यह है कि चीजें तो मिल जाती हैं, केवल कीमत अधिक देनी पड़ती है। तो सिर्फ यह मान लेना कि उत्पादन की कमी के कारण मूल्यों में बृद्धि है इस से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि आज चीजों का उत्पादन तो होता है लेकिन उस के वितरण की प्रणाली मुद्दे न होने के कारण, वितरण सही ढंग से न करने के कारण, विधिवत मूल्य पर, जो मूल्य बास्तव में होता आहिये उस पर वितरण न होने के कारण यह मूल्य बृद्धि

होती है। सब से बड़ा कारण मूल्य बृद्धि का यह है और जैसा कि हमारे मिल साठे साहब कह रहे थे कि देश के अंदर काला धन समानान्तर रूप से चल रहा है, वह काला धन भी मूल्य बृद्धि का एक कारण है। आप देख लेंजिए, किसान विभिन्न प्रकार की चीजें पैदा करता है जो खाने के काम आती हैं लेकिन अगर आप मूल्यों का सबंध कराएं तो आप को यह पता लेना कि जिस हिसाब से मूल्य बृद्धि हुई है उस हिसाब से किसान को वह नहीं पहुँच पाता। इसका अर्थ यही है कि जो उत्पादन करता है और जो उसका उपयोग करता है उसों के बीच का कोई आदमी ऐसा नहीं है इस व्यवस्था के अंदर जो उस की चीजों को कम मूल्य में ले कर अधिक मूल्य कमाने की चेष्टा करता है। वह काम वह उसी धन से करता है जिसे हम काला धन कहते हैं जिसके कारण मूल्यों में बराबर बृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर डालडा को ले लीजिए। अभी जब जादी आहु के दिन ये तो इसका मूल्य बहुत कम जाता गया, अब फिर नीचे चला गया। अब वह मूल्य नहीं है। जब ज्यादा ज़करत भी तो मूल्य बढ़ गया, ज़करत कम हो गई तो मूल्य घट गया। उत्पादन से कहाँ इसका संबंध है। इसका संबंध ऐसे लोगों से है जिन को आमीण खेड़ों में आठतिथा कहते हैं। अठतिथा एक जगह इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने में उस धन का उपयोग करता है। आप तो उस धन को केवल कपड़ते हैं जो आप की नजर में है जिस पर वह आवधि कर देता है या और दूसरे टैक्स देता है। लेकिन दूसरा धन जिससे वह स्टाक करता है वह धन हवारी आवधि की नीलेज में नहीं है। मूल्य बृद्धि का कारण तिके उत्पादन की कमी नहीं है, लेकिन हवारा नियंत्रण और वितरण प्रणाली मुद्दे न होने के कारण मूल्य बृद्धि होती है।

इसका एक और भी कारण है—
इस देश के अन्दर शोधोगिक व्युतु के
मूल्य और हावि मूल्य में बड़ा अन्तर है। इन
दोनों के मूल्यों को नियन्त्रित करने वाला
एक ही शादी ही है, एक तरफ़ के ही सोने इन
का नियन्त्रण करते हैं। जो दृष्टि से
उत्पादन होता है, उसके मूल्य में और
शोधोगिक मूल्य में जो फिस्टड प्राइस होती
है, जो तय की जाती है, उसमें समानता
न रहने के कारण मूल्यों में उत्ताप-चढ़ाव
होता रहता है। आज जूरत इस बात की
है कि हमारे मंत्री महोदय ने देखना चाहिए
कि इस को कैसे सुदृढ़ करें, कैसे इसके प्रदर
समानता पायें।

वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के
लिये सहकारिता भी एकमात्र साधन
हो सकती है। परन्तु आज सहकारिता
की स्थिति क्या है? मैं यह मानता हूँ
कि आमीण धर्म—व्यवस्था
को सुदृढ़ बनाने के लिये, आमीण जीवन
को सुखमय बनाने के लिये यह आवश्यक
है कि पंचायतें और सहकारिता सुदृढ़ हों,
मजबूत हों, लेकिन यह कैसे हो सकता है?
मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ—
आज महाराष्ट्र की कोशापरेटिव सोसायटियां,
मुजरात की कोशापरेटिव सोसायटियां बड़ी
मजबूत हैं। मूले इन की बहुत नजदीक
से देखने का मौका तो नहीं मिला है,
लेकिन जैसा भीने मुझे भी पढ़ा है—वहाँ
की सहकारी संस्थायें बहुत अच्छी तरह से
काम कर रही हैं। लेकिन इसी तरह
हमारे विहार में क्या हालत है? आज
बहुत से सदस्यों ने यहाँ बहुत अच्छे भावण
दिये। जीवनी जहाँ प्रकाश जी ने जो बातें
कही हैं, मैं उन सब के सहमत हूँ।
किन्तु मैं अपने सहकारिता मंत्री को यह
मुकाबला देना चाहता हूँ कि आज सहकारिता
राज्य का विवर बना हुआ है और यही
कारण है कि जो राज्य काला काम करते

होते हैं उन के यहाँ सहकारी संस्थाओं
की स्थिति सुदृढ़ है, लेकिन जिन राज्यों
में सहकारिता परिवार की संस्था बन गई
है, अवित की पौकिट की संस्था बन गई
है, वहाँ हालत छाराब है। उन
स्थानों पर न हम वितरण प्रणाली को
सुदृढ़ कर सकते हैं और न केडिट को
सुदृढ़ कर सकते हैं और न ही आमीण
जीवन को मुखी बना सकते हैं। विहार
एक ऐसा ही राज्य है जहाँ आप के केडिट
बैंकों का, लैंड डेवलपमेंट बैंक का, मार्केटिंग
प्रार्टनिंजेशन्ज का, किसानों को कोई लाभ
नहीं पहुँच रहा है। करोड़ों लपये की
गड़बड़ वहाँ चल रही है। किसी कोशापरेटिव
संस्था ने गव. के किसानों के लिए
जब लिया, उस को उस संस्था के सभा-
पति और सेकेटरी ने अपनी जेव में रखा,
लेकिन जिन के नाम पर वह रपवा
सिया गया उन को उसका कोई, लाभ नहीं
पहुँचा।

एक बात यह भी है कि कोशापरेटिव
में आफिसियल छा गए हैं—मैं इस
का विरोधी हूँ। आज सहकारी संस्थाओं
में सरकारी अधिकारियों की छाप नहीं
होती चाहिए, जो बुने हुए प्रतिनिधि
हैं उन का ही नियन्त्रण उस पर होता
चाहिए। जिन लोगों के जीवन को
सुखमय बनाने के लिए इन सहकारी
संस्थाओं का निर्वाण किया जाता है,
यदि उन का ही सम्बोध उन में नहीं
होता तो वे सहकारी संस्थायें सुदृढ़
नहीं हो सकतीं। आज विहार में क्या
होता है? 11 आदमी मिल कर एक
कोशापरेटिव बना कर सारे गांव पर
नियन्त्रण करते हैं, एक तरह से वह
पारिवारिं संघ बन गई है।
इसीलिए मैं सुकाब देना चाहता हूँ
कि यह राज्य का विवर है, इस को
लैंडल एक्ट में बदलना चाहिए। हम
प्रथम देश के आमीण जीवन को सुखमय

[श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा]

बनाना चाहते हैं, बितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, इस के लिए जरूरी है कि केन्द्र का एक हो, जिस के अन्दर सारे देश में रहने वाले लोगों का समावेश हो। आप का यह ऐस है, आवजेक्ट है, जब आप काम करना चाहते हैं और सरकारी संस्थाओं के साध्यम से, तो सारे देश की कोआपरेटिव पर आप का डाइरेक्ट नियंत्रण होना चाहिए। यह मैं मानता हूँ कि कोआपरेटिव एक राज्य का विषय है, ग्राम-पंचायत एक राज्य का विषय है, लेकिन जब देश की उन्नति का सबाल है, देश की गरीबी का सबाल है, और देश के विकास का सबाल है, तो इन संस्थाओं पर केन्द्र का डाइरेक्ट नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि एक कोआपरेटिव केन्द्र सरकार स्वतः बनाए, जोकि सारे देश पर लागू हो। इन संस्थाओं को तो राज्य सरकारें ही बलाएंगी लेकिन उन पर पूरा नियंत्रण, डाइरेक्ट नियंत्रण आप का हो।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि विहार के अन्दर जो कोआपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, जोकि भाँड़ों से संबंधित हैं, जब तक वे बायाएंबिल यूनिट नहीं होंगी, उन का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो सकता, वे स्वतः अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। उन के आय के साधन इन्हें चाहिए कि वे अपने को बचाने में समर्थ हो सकें, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए और जब तक केन्द्र द्वारा एक सेन्ट्रल कोआपरेटिव एक नहीं बनाया जाता और सारे देश में वह समान रूप से लागू नहीं होता, यह संभव नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि देश के अन्दर इन सारी संस्थाओं की स्थिति बहुत बरबाद है। अगर इस की विस्तीर्ण स्थिति बच्ची होगी, तो

बितरण प्रणाली में, छोटी के विकास में, देश के आधिक विकास में, और सार्वीय जीवन को सुखी बनाने में यह अपना योगदान दे सकती है। इसलिए सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने की बहुत आवश्यकता है।

हैंडबूम की बात आप सीखिए। यह प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। इन संस्थाओं के द्वारा हम उस की रखा कर सकते हैं। इसलिए मैंने यह कहा है कि यह जो स्टेट का सबजेक्ट घटी तक बना दुआ है, इस को सेक्टर का सबजेक्ट बनावे क्योंकि कोआपरेटिव और आप पचायतों में बड़ा बनिष्ठ सम्बन्ध है।

माय ही साथ में एक विवेदन यह कहना कि कोआपरेटिव से भेरा गहरा ताल्लुक है और 45 साल से राज्य की संस्थाओं से, प्राइमरी तोसाइटी से ले कर बड़ी संस्थाओं तक, भेरा सम्बन्ध रहा है। मैं आप को विहार की बात बताता हूँ। विहार के अन्दर या तमाज़ा होता है। जब भी जनजीवन विषय जो की सरकार भी तो छोटी छोटी सोसाइटियों की जगह पर एक बायाएंबिल सोसाइटी बनाने के नाम पर उन्हीं उन को सुपरसीड कर दिया और यह कहा कि जब यह बायाएंबिल यूनिट हो जाएगी, तो वैक के चुनाव करावें लेकिन जब चुनाव का बहत हुआ, तो सब को उन्होंने रिलीज कर दिया और कहा कि जैसे लूटते थे लूटी। यह जोई एक अच्छी सरकार की नीति नहीं कही जा सकती। यह एक अस्तित्व की नीति नहीं होती चाहिए। बानीय मंडी जी वहे कंठ अस्तित्व है और कोआपरेटिव से उन का बड़ा बहुत सम्बन्ध है। इसलिए भेरा जहाँ वह है कि विहार में जो सारे सोसाइटिव वैक हैं, वह

चाहे स्टेट कोशापरेटिव बैंक हो, सेन्ट्रल कोशापरेटिव बैंक हो, शार्केटिंग यूनियन हो और चाहे खंड भार्गव बैंक हो, उस में जो बड़े बड़े यगरमण्ड प्रबंध कर गए हैं और उन्होंने जो उनमें गड़बड़ियों की हैं, उन की जांच भागी चाहिए। इस की आप जांच करें या सी० बी० आई० से जांच करवाएं। जांच करवाने पर आप को बहां पर बहुत सी गड़बड़ियों का पता चलेगा।

विश्वास जमेगा और उसका हमें समर्थन प्राप्त होगा कि बास्तव में जनता पार्टी की सरकार ने बहुत उत्तम कदम उठाया है। इससे अट्टाकार ही नहीं मिटेगा बल्कि कोशापरेटिव संस्थाओं का भी सुधार होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोशापरेटिव के बारे में एक सेन्ट्रल एक्ट बनाने पर आप विचार करें। यगर वह मुमिल हो सके तो इसे बनायें। इससे सहकारी संस्थाओं का सुधार होगा और उन पर आपका डायरेक्ट नियंत्रण होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करें।

मैं आप से यह भी बता दूँ कि यथा के रजिस्ट्रेट मिस्ट्रेट और सुवहमव्याम ने अख्य सेन्ट्रल कोशापरेटिव बैंक के केस को पकड़ा था। बहां के सेनेटरी के बिलों कराए के बहन का भासला और वर्षे के दुष्यदृश्य का भासला पकड़ा और लेत हैटीटैटूट करने के लिए लिखा लेकिन उह सारी काँच को दबा दिया। आपने सहकारों में यहां होगा कि विहार में कबं देने के लिए रेलवे टेलन और गाड़ी बैदान को भी भार्गव कर दिया गया। इस तरह की अपेक्षा बहां की है और इस की यगर आप जांच करवाएंगे तो आपको बहुत सी और बास्तों का पता चलेगा। मैं जासता हूँ कि हमारे प्रवेश में एक ग्राम्य रजिस्ट्रार कोशाप्रेटिव आये। जब उन्होंने भासले पकड़े तुल किये तो उन्हें चार जहानों के यगर ही रक्षा कर दिया गया। योकि ऐसियों जो जहांचती भी वे अब होने लगती हैं। अब हमारी जासता पार्टी की सरकार है। हमारे घोषणा पत्र में वी वह दिया चुप्ता है कि हम इस तरह की बूराइयों को हट करें। इसलिए मेरा कामसे निवेदन है कि जिसी भी प्रियसी सरकार के यगर इस ब्राकर की बड़बड़ियों हुई हैं, चाहे वह किसी के हारा हुई हैं, किसी एक अविक के हारा हुई हैं, उन सब को छोड़ किया जाये और जिन्होंने बड़बड़ियों की हैं, उनके विकास कार्यकारी की जाएं। इससे जासता में

भी मूल्यव्य प्रशास बर्नी (सीबान) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का भौका दिया। हमारे सुविदेह बाबू ने यही जो कहा वह ठीक है, मैं उनके समर्थन में ही दो-एक बातें कहूँगा। आप जब तक कोशापरेटिव के कानून में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कुछ काम नहीं हो सकेगा। मैं इस सम्बन्ध में दो-एक परिवर्तन सुझाता हूँ।

पहली बात तो यह है कि आडिट को आपको रजिस्ट्रार के आफिस से विस्तृत प्रलिङ्ग करना होगा। सहकारी समितियों के लिए रजिस्ट्रार बहार, विष्णु, महेश तीनों हैं। बहां के रूप में रजिस्ट्रार का काम है कि कोशाप्रेटिव सोसाइटीज को बता कर रजिस्ट्रेशन करता। जब सोसाइटीज बन जाती हैं तो रजिस्ट्रार का वफतर विष्णु के रूप में उनको युपरवाइज करता है, उनको जासता है। और उनकी जमानियि, लिकिडेशन भी यह के रूप में करता है। ऐसी स्थिति में उनके नीचे जो आडिट विपार्टमेंट रहता है उसमें हित्तत नहीं ही सकती कि वह सभी समय सही बात कह सके। यगर रजिस्ट्रार के सामने प्रष्ट बातें जाती हैं कि कहीं मदबड़ी हुई है तो इससे रजिस्ट्रार के सुवरचिक्षन में कभी जाती है। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि

[**श्री मृत्युंजय प्रसाद बर्मी]**

मुख्यमन्त्री द्वारा ये बोलें आपके सामने रखँ दी हैं। अब उनके दोहराना बेकार है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप रजिस्ट्रार के दफ़्तर से आडिट को अलग कर दीजिए। यों तो जो भी आडिटर की रिपोर्ट आती है उस पर भी रजिस्ट्रार के दफ़्तर में कोई बास एक्षण नहीं लिया जाता। इसलिए आडिटर कोई बास काम वहाँ नहीं कर पाते।

इसी बात यह है कि अगर किसी से विकायत प्राप्त है कि अमुक सोसाइटी में गडवड है तो उसकी आंच करायी जाए और अगर आंच करने में गडवडी निकलती है तो कार्रवाई की जाए। हमरे वर्तमान कानून के मुताबिक रजिस्ट्रार को किसी भी दरबास्त को रद्दी की टोकरी में फेंकने का पूरा अधिकार है। इसलिए रजिस्ट्रार से सम्बन्धित कानून में यह सुधार किया जाए। अब क्या होता है कि सोसाइटीज को और से, अर्थात जनरल बाड़ी की ओर से, मैनेजिंग कमेटी से या बोर्ड आफ डायरेक्टर्स दरबास्त जाए तो रजिस्ट्रार कार्रवाई करता है। अब मैनेजिंग कमेटी या बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अपने खिलाफ कांस शिकायत करने लगे। ऐरा कहना यह है कि किसी भी सोसाइटी की जनरल बोर्डी की बोर्डी हो और उसमें इसी ताकत हो कि वह मैनेजिंग कमेटी को बदल सके, हटा सके, तो फिर इसके लिए रजिस्ट्रार के पास जाने की प्रावधानकता नहीं होगी। कुछ मुठ्ठी भर लोग अपनी गोटी जाना लेते हैं और फिर हटते नहीं हैं। ऐसी हालत में व्यक्तिगत रूप से यदि कोई लिखता है तो कानून में यह होना चाहिए कि रजिस्ट्रार उसकी शिकायत को सुने। अब के कानून में तो उसकी मर्दी है कि वह सुनी या न सुने, रद्दी की टोकरी में फेंक दे। मैं इस बात का शुक्लबोधी हूँ। मैंने कई बार लिखा और 1974 से लिखता रहा जो हूँ अब अब तक कुछ नहीं हुआ। जब मैं जेल में था उस समय से लिखता रहा किया, आज-

तक उसकी इकायायरी हुई या नहीं, पता नहीं कहा तक कार्रवाई हुई। यह अबूरी "ए गई है। इनकायायरी इस मायने में हुई कि एक अफसर आए थे। नीनेवर ने उनको कागज नहीं दिखाए और वह भी यही खत्य हो गई। मृमे कुछ बाब नहीं दिया गया। इस इकायायरी के बाने क्या है? प्राइमा फसाई केस जहाँ बनता हो उस केस को तो आपको रजिस्ट्रार को आंच करती ही होगी। हाँ जहाँ निवालत केस हो वहाँ ऐसी बात नहीं चलनी चाहिए।

16.35 hours.

[**SRI SONU SINGH PATEL in the chair.**

काल्केसिस हुई है रजिस्ट्रार की ओर उनके पहले कमेटीज भीं। उन कमेटीज की रिपोर्टेशन आई और उन पर दिखार हुआ। लेकिन ये सब बातें तिर्की कायदों में रह गई हैं, आपे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। बल्कि टालने के लिए यह कह दिया जाता है सहकारी साम्बोलन में से ही आडिट आर्गेनाइजेशन इसी तरह से डिवेलप करेंगी तो अच्छा होगा, अपने तौर पर आपे बड़े तो अच्छा होगा। लेकिन जब तक नहीं होती है तब तक रजिस्ट्रार के हाथ में रहे तो ठीक है। यह भी कह जाता है कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार का पद वे दिया गया है जीक आडिटर को। लेकिन इससे भी कोई कायदा नहीं होता है सोलिड आडिटर यह रहता तो रजिस्ट्रार के प्रभाव ही है। उसका अलग रहने का कोई पर्याप्त नहीं रह जाता है। मैं विहार के परिमेय में यह बात कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अन्य प्रेसों से कुछ घटता है। जैसे प्राजा में यह है जैसे वहाँ एक आडिटर सोसाइटी बदल दे कही हुई है। तब जगह ऐसा नहीं है। वह भी ऐसी है जो सब जगह एक सी होनी चाहिए। आडिट आर्गेनाइजेशन अलग होनी चाहिए।

विहार में ऐसे देखा है कि वही बड़ी सहकारी बंस्काधों को कुछ लोगों से

अपने हाथ में कर लिया है और बाहर बाहर और चौदह चौदह बरस से वे इनके बैयरमीन खले गए रहे हैं। इस बीच में उन्होंने भी कुछ किंवा उसका जिक यहाँ न कहं तभी अच्छा होगा। संस्कार भी कौन कौन सी? बिहार राज्य की केन्द्रस्थ सब से बड़ी बड़ी संस्कार यैं जैसे स्टेट कोओपरेटिव बैंक, कोओपरेटिव फैब्रिकेशन, लैड मार्टेज बैंक, बिस्कोमान, आदि।

बी अमानमंडी प्रसाद शास्त्र (गोदाः) :
अर्द्ध वैक।

बी मृत्युजय प्रसाद शर्मा : वह बड़ी संस्कार नहीं है (इंटरव्यू) वहाँ भी बड़ी गड़बड़ ही है। उनकी बजह से उसके अफसरों को तो जेल भेज दिया गया, सब कुछ हुआ लेकिन जो बैयरमीन ये और जो केवल बैयरमीन ही नहीं ये इनवैस्टमेंट कमेटी के भी बैयरमीन ये उनके खिलाफ भी चार्जिंग ये लेकिन उनको किसी ने पूछा तक नहीं। चीफ मिनिस्टरने उन को बिल्कुल घलग रखा और उन के नीचे बालों को दै जेल भेज दिया। चीफमिनिस्टर के जाने के कुछ दिए। पहले तक तो कुछ नहीं हुआ था। हाल तक उनको निकाला नहीं गया था। बाद में क्या हुआ पता नहीं। अगर किसी की बैष्णवी किसी की सम्पत्ति उसको आप बनने दें तो किर वह अपनी सम्पत्ति को छोड़ेगा ही क्यों? वह नहीं पर जमा रहने की हर सम्भव कोशिश करेगा। अपनी सम्पत्ति को बनाये रखने के लिये हुनिया भर के दुरे खले काम करेगा। लोक क्या कर रहे हैं उस फिल्म में भी नहीं जाता है।

बिहार में एक विषम बात कि कोई छः साल से अधिक व्यापक विषय बिहार नहीं रह सकता है

इसके बारे में एक आर्डिनेंस हुआ था। यह आर्डिनेंस लैप्स हो गया तुबारा आर्डिनेंस स बना। यब किस विधि में यह चीज है कहना कठिन है। आप तो जानते ही हैं कि बिहार में आर्डिनेंसों का राज रहा है। उनको कानूनी रूप बहुत कम दिया गया है। उनको कानूनी रूप देने का ब्याल हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं आया। एक बिनोब भी बात है योदी तकलीफ भी होती है कहने में। बिहार में कोओपरेटिव सोसाइटीज के बारे में 1912 में कानून बना था। फिर 1935 में वह पक्का हुआ। उसका नाम जो बला था रहा है वह बिहार एंड उडीसा कोओपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बला था रहा है। आज तक भी उस एक्ट से उडीसा नाम अभी तक हटाया नहीं जा सका है। योदी उडीसा ने बिहार से हटने के बाद अपना भलग ही एक्ट बना लिया है जिसमें बिहार का नाम नहीं है। और एक हम बिहार बाले हैं जो 1977 में भी उडीसा को अपने साथ कामबद्ध हो जाए हैं। तो इससे भनुमान होता है कि कितना अधिक हम इस चीज पर ध्यान देते हैं।

व्यापार में मुझे एक ही बात कहती है और वह यह कि आप नियर्ति के लाभ में पह कर ये उन वस्तुओं का नियर्ति न कीजिये रुपया कमाने के लिये जिनकी जरूरत महां बहुत ज्यादा है। ऐसी चीजों का नियर्ति कम से कम कीजिये जिनकी पूति तुबारा न होने वाली है। विसाल के लिये प्रकृति में हमें बानिय पदार्थ दिये हैं जो वह हमें तुबारा नहीं देती, अब आज उनको बायर कर देते हैं। इस समय खले ही हमें ऐसा बिल आया, लेकिन आने वाली बीड़िया जैवरेशन उनको कहाँ से पैदा करेंगी? कहा जाता है कि बैलाडीला से आवश्यक और बाहर भेजते हैं और उससे काफ़ी विदेशी मुद्रा कमाते हैं। किन्तु मार्गिनिय में आप को लौस होता है उनकी कमी पूरी करते

[मी मृत्युजय ब्रसाद बर्मी]

हैं व्यापार में दिखा कर कि रेलवे में हमें इतना मुनाफ़ा हुआ है। तो क्या जापान के लिये हम अपनी सारी की सारी प्राकृतिक सम्पदा खट्टम कर देंगे? 100 वर्ष में न सही 1000 वर्ष में खट्ट हो जायगी। जितना सामान हम बुद्ध बना सकते हैं उतना ही ब्यनिज पदार्थ निकालें। यहाँ से और बाहर भेज कर वहाँ से तैयार माल भेगा करके बीच में बहुत सा पैसा गंबार्ये, 10 हजार का और भेजें और 100 का माल भंगायें, यह 61 का नहीं है। जितना और हम स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे माल तैयार कर सकते हैं उतना ही निकालें, और उससे माल तैयार करके बाहर भेज सकें तो भी, लेकिन बाहर से तैयार माल भंगाना छोड़ दें। इसलिए वह नीति गलत है कि हम मिनरल्स के नियांत पर अपना सारा आर्थिक ढांचा रखें। यह बहुत बड़ी भूल हो रही है। वही हाल कोयले का हो रहा है, जिस का नियांत तो नहीं होता है, मगर ऊर्जा के लिये हमें तेल की टाई कमी हो रही है, क्वालिटी कोयले की कमी हो रही है। तो आखिर यह भी तो खट्ट हो जायगा। इसी तरह से और बहुत से मिनरल्स हैं जिनकी आगे चल कर के कमी हो जायगी।

जो भीजें हम बुद्ध पैदा करते हैं और प्रकृति हमें दुश्मारा देनी जैसे जंगलात की भीजें हैं, हम अभौं पैदा करें, जानवर पालें उनके दूध से बना हुआ सामान बाहर भेजें, यह सब भीजें चल सकती हैं क्योंकि वह भीजें हम बार बार पैदा करते रहेंगे। किन्तु जो हम पैदा नहीं कर सकते उनको खट्ट कर दें तो मतलब यह हुआ कि आने वाली पीढ़ियाँ, जैनरेशन के मुँह का आझ बरबाद कर रहे हैं अपने आराम के लिए, उनकी खुराक छीन रहे हैं अपने गेश के लिये। यह नहीं होना चाहिए।

आपका व्यापार जो आप के हाथ में है वेष्ट के भीतर वह ठण्ड पड़ा है बहुत जगह।

इसलिए नहीं कि लोगों को सामान नहीं मिलता है, किन्तु इसलिए कि जो कर्मचारी हैं उनका लोगों के साथ ऐसा तोर तरीका है कि सामान कम बिकता है। क्योंकि वह जानते हैं कि सामान बिके या न बिके, जैसे सुपर बाजार हैं, कंज्यूमर्स कोम्पारेटिव स्टोर्स हैं, कर्मचारी को बेतन मिलता ही। अधिक बिकी होगी तो उसका लाभ कर्मचारियों को होगा नहीं, और बिक्री कम होगी तो भी कर्मचारी को तनावाह तो मिलेगी ही। तो ऐसी हालत में वह क्यों अम करें? आज यही स्थिति आदी भण्डारों की है, वहाँ पर भी कोई काम नहीं करता है। अगर आप बजाज की दुकान पर जायें तो वह एक नहीं, दस कपड़े दिखाते हैं, वह कोणिश करता है कि ग्राहक वाली हाथ न लीटे।

लेकिन सुपर बाजार और दूसरी जगहों पर हालत यह है कि आपको जंचे तो लो, नहीं तो न लो। मेरे एक मिल ने मुझे बताया, एक लोहे की भारी चोड़ उन्होंने बतायी। उन्होंने कहा कि जबरा एक कर रस्ती से बांध कर दे दीजिये, इसे खुला कैसे ले जाऊँ। उनसे कहा गया कि रस्ती या मुतली तो नहीं है, मत दीजिये, छोड़ दीजिये। आप कैसे भीतों दे दीजिये, पैसा लौटा देते हैं। क्या कहीं कोई आपारी इस तरह की बात करता है? अगर ऐसिया के लिये छोटी छोटी भीजें उतके पास नहीं हैं तो भी कहता है कि मैं आगे देता हूँ, और उसका इतजाम करती है। और भी पक्षांतर तरह से उसे राजी रख लेता है। लेकिन इन कर्मचारियों का जबाब तो यह कि हम किस किस भीज के लिये कहाँ कहाँ रिक्वी-जीवित करते हैं, किससे माने? हबारे वाले सामान नहीं हैं तो क्या करें?

सभी जगहों पर, आहे को-ऑपरेटिव हों या और बहुहों, राजनीति के स्तर पर लोगों को नियुक्त कर दें दिया जाता है। कहीं भी यह नहीं देखा जाता कि उसको जिस काम के लिए बिठाया जाता है, उसका उसे जान है या नहीं। ऐसे कि को-ऑपरेटिव में बहुत बहाव स्पष्ट होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट करना होता है, लोन देना होता है, वहां काइनेशनल एडवाइजर कहिये या और कुछ कहिये, जो भी रहे उसको बैंकिंग की समझ होनी चाहिये। यह कोई नहीं देखता कि उसे इसका जान है या नहीं। जो बेपरवान या सेकेटरी होता है वह तीक है सब कुछ जानता है। उसको इसका प्रन्दाज होता है या नहीं, यह भवितव्य ही जाने। और फिर नुकसान हो तो इस में आश्वयं क्या है। जो इसके बारे में जानकारी रखता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। मेरा कहना है कि जहां बड़ी-बड़ी रकमों की बात हो वहां ऐसा जहर करें कि टैक्निकल एक्सपर्ट के हाथ में हो कहने का अधिकार ना हो ही निकित उसको हम तरह की बीटों पावर भी हो जाये, जहां उसे ना कहना हो तो कम-से-कम उसकी ना बाली बात अवश्य मानी जाय, मानी पढ़े। अगर ऐसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में होता तो यह बात न होती।

इन बद्दों के साथ मैं प्राणा करता हूँ कि महाराष्ट्र में जो भंडी महोदय की अनुभव हुआ है, उसका लाभ सारे राष्ट्र को यह दे सकें।

SHRI VAYALAR RAVI (Chiravinkil): Mr. Chairman, Sir, first of all, I must congratulate my friend Mr. Mohan Dharia for his ability to rule over this big empire. But I would like to draw his attention first to the alarming situation of the soaring prices as on date. I am not looking at it from the political angle, but from the realistic angle. Even Emergency could not do anything with the prices. It has been clear and evident from the fact that

during early six months of 1976 the prices rose by 11%. But in the later part of 1976 there was a decrease and it was less than 1% according to your own report. It is very clear that in the last quarter of 1976-77 i.e., during the last three months of the financial year, the prices have gone up by 2.7%. But in the last three months the prices have gone up high. May I draw the attention of the hon. Minister to the fact that the increase in the price level of primary articles like foodgrains, cereals, pulses and vegetables, milk and milk products, egg, fish and meat was 16.8% I used to go to the market to purchase eggs and meat. Their prices have gone up very much. It is true that they have risen by 16.8 per cent. The general price level has gone up by 10%. If you take food articles like fruits, their prices have gone up by 29.4% in the last three months. The prices of foodgrains have gone up by 11.7% while the prices of vegetables have gone up by 27.6%. This is not a matter of political accusation. It is a matter of grave concern to every one of us. It must be tackled in a way that we are able to feed the poor people. We have to find a strategy to control the prices. I want to know what strategy the minister proposes to adopt. The previous government resorted to the method of cutting money supply and reducing the demand. It can be a shock treatment which can be given for a short time but it cannot be the permanent feature of the economy. Unfortunately, the present government also is adopting the same method of controlling money supply and demand. This will not generate growth and this is not good economics. I appeal to the minister not to resort to this method. It was all right to adopt it during the emergency having compulsory deposits and all that. But now there should be a new method of greater production and better distribution. I agree that it is a good beginning to have a thousand janata shops, but only a proper public distribution system can control the prices of essential articles. After all, there are hardly 5 or 6 essential things which the rural poor require—rice or wheat, a little sugar, a little kerosene a little oil and a piece of cloth. In the case of the urban people the requirements are a little more. Not only the government but all of us will be failing in our duty if the rural poor are not able to get these essential articles at reasonable prices.

At present the production and prices of all essential consumer goods, from toothbrush to edible oil, are controlled by a few monopolists over whom the government have no control. We have-

[Shri Vayalar Ravi]

to look at the problem from two angles—the needs of the rural population and the needs of the urban population—and control the price level because the people are suffering very much.

The Commerce Ministry—Whether it is the previous government or the present government—deserves congratulations for their better performance. But I want to point out certain things. According to your own report, the world trade has gone up in volume by 11% and in value by 10%. But what is our share in it? You say it is appreciable, but it should be a little more appreciable.

I want to draw attention to UNCTAD IV. Even before that, in the meeting of the Group of 77 in Manila, the Government of India took the position that the developing nations should mobilise all their forces and take a joint stand in basic questions. So far as the Nairobi UNCTAD meeting is concerned, India could play an important role in putting up a strong case for the developing nations. We could very well see the arrogant position taken by the United States like a big brother and throwing a political challenge to the developing nations. We have to take certain basic decisions in this regard in the international conferences. Even today big nations like the United States may not change their attitude, because they are concerned with political attitude and matters. India and the other developing nations of the Group of 77 have been exploited all along. We have to prevent this exploitation and stand on our own legs. We should question the big brother attitude of the United States. In UNCTAD IV, we did it to some extent, but nothing came out of it excepting a resolution on commodity world trade or something like that. Nothing more was achieved in UNCTAD IV. According to your own report, our export trade with the United States is only 0.5% as against 12.4% of the Latin American countries. This is because of political considerations of the United States. You must have that basic understanding when you are taking up the whole question of the improvement of the trade of developing countries.

Then I come to the export surplus. This export surplus is Rs. 72 crores. Of course there is an improvement in the export trade, but it is mainly due to the reduction in imports. I cannot understand, Sir that in 1976-77 there was a huge increase of 39 per cent in imports. Even though we had a good surplus in fertilizer and improvement in production, yet we had gone in a huge way for the import of these things which comes to over Rs. 1000 crores. If you analyse the situation,

Sir, I believe we could reduce the import completely and make more than Rs. 72 crores surplus and we could establish a good trend in the export trade. But at the same time when we are continuing this trend of export, I think the Minister has to look into this carefully to find out which are the areas where we could cut down the imports as much as possible because I find during the last year there was a lavishness in the issue of import licences because they say we got a surplus of foreign exchange in our hands. So we issued the import licences lavishly. It went up to 39 per cent. That is why we could not have save more money and it was only Rs. 72 crores.

Then, Sir, regarding our effort for export to the hard currency areas, I can see that a good effort is made for export to the hard currency areas. In this connection, I would like to stress the need for more trade with the EEC nations. I agree and appreciate that there is an increase of 65 per cent to EEC. It has gone up to Rs. 1,047 crores. But, I think, Sir, there is an agreement on coir, an agreement on jute and coal and on different areas of steel, sugar etc. I wish that more efforts have to be made to see that more areas are found out for export and more share of export to the EEC nations. In Latin America there is an improvement. Among the Gulf countries, I find there is a reduction in exports to Iraq. I would like the Minister to examine as to what happened to our exports to Iran. There is not much improvement in our trade relations with Gulf countries. Many Indians are living in the Gulf countries and we can improve the trade relations.

Lastly, Sir, I come to the commodity items with which we are very much concerned. You please allow me a few minutes more. This is about coffee, coir, rubber, cardamom, marine products and so on and so forth. These are the traditional items which need encouragement. Here I found an anomaly. You will agree with me, Mr. Chairman, that this is very interesting. Kerala earns a minimum of about Rs. 300 crores of foreign exchange every year. Now it has gone up to Rs. 500 crores.

MR. CHAIRMAN : What about coconuts?

SHRI VAYALAR RAVI : Coconuts on which you are also interested will come last. Here I can say that MDA has spent about Rs. 160 crores. Your cash subsidy has gone up to Rs. 159 crores. As regards engineering goods, I congratulate them for the export of goods worth Rs. 550 crores. I agree, it is a good

performance. But you have given a cash subsidy of Rs. 80 crores. These are finished goods and products. We have given a cash subsidy of Rs. 139 crores and MDA spending was about Rs. 160 crores. I would like to appeal to the hon. Minister to find out what encouragement is given to coffee, rubber, cardamom and other marine products. I can tell you, hon. Minister, it is 'NIL'. But you are harming us, punishing the grower. Take for example, coffee. This is a very serious matter. According to your own report, 57000 tons of coffee were exported and we earned Rs. 140 crores. The unit value per quintal is 2,456. You want to kill the goose that lays the golden egg. Then what did you do? The duty of Rs. 500 was increased to Rs. 1300. Then we all came, represented and begged the Minister to reduce it. What did you do? You increased it to Rs. 2200 per quintal. Then again representations were made and you reduced it to Rs. 1600. This is big trick you played on us. Now, the duty we have to pay is Rs. 1600. This duty of Rs. 1600 had been introduced when the price was Rs. 2500/- per quintal. Today according to a telex message, it has been sold only at Rs. 1500/- They are unable to sell coffee; they have withdrawn from the market. The duty is Rs. 1600/- It is a very heavy. Once you were paying cash subsidy to the industrial products, to the extent of Rs. 140 crore. Today you are burdening the poor coffee growers numbering 1 lakh in Karnataka, Tamil Nadu and Kerala have to pay duty.

17 hrs.

I know that your Janata Government is preaching for the farmers to come up. But you are punishing the farmers of coffee, rubber and cardamom. In cardamom, you have increased the duty. Again, the rubber gives employment to 1,80,000 People. Please check up the statistics. The small grower, 1,50,000 in Kerala alone. We produce 1,72,000 tonnes of rubber. The consumption is only 133,000 tonnes. It is surplus today by a minimum of 40,000 tonnes. Do they not deserve encouragement? But what did the government do? they have stopped the subsidy i.e. the replacement subsidy. It was given from the rubber cess fund. It is put in the Consolidated Fund of India. The price has also come down. The cost has gone up to Rs. 900 but the price is only Rs. 600/- Please fix the statutory price at Rs. 1000/- per quintal.

Lastly about fish. What are you doing about marine products? Are you doing anything? I am not blaming you; you have come just now. I am repeating my old arguments. I had requested the earlier government to do something. They did

nothing. There are 10,000 boats in the east and west coasts. Government did nothing to help them. They have only introduced a licensing system for these fishing boats. It is a hurdle. Without any encouragement, we are earning Rs. 186 crores, without any investment and the target is Rs. 210 crores. Do they not deserve encouragement? On the other hand you prosecute them. But Tatas and Birlas entered the field to export. Even they are at loss. Because they enjoy benefit of Export House.

Lastly about coconut in which we are all interested. Coconut oil is used as edible oil in Kerala. In other parts of the country it is not used so. It is used as an industrial oil there. All over the western coast, coconut is being produced. The economy of Kerala is dependent on coconut. About Rs. 700 crores is the income from coconut. The previous government harmed Kerala by deciding to import coconut oil. We requested them not to do so. I made repeated requests that the import should be stopped. It was not stopped. So, I appeal to the hon. Minister to look into the question from the point of view of the people of Kerala, irrespective of their political affiliations, the State government and the Members of parliament coming from that area. Please stop the import of coconut oil as also withdraw the reduction in the import duty. Let me conclude with the hope that our problems will be viewed sympathetically, there will be more production our country will prosper and we will earn more foreign exchange.

श्री अर्मसह भाई पटेल (पोखंदर) :
सभापति महोदय, माननीय वाणिज्य तथा
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री जी
जो मांगे ले कर इस हाउस में आए हैं,
उन मांगों का मैं समर्थन करता हूँ।

मैं दो तीन बातों पर चास तीर से
मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के
लिए बड़ा हुआ हूँ। पहली बात
यह है कि सरकार ने जो बायदा बाजार
आयोग बनाया है, वह मूँगफली, मूँग
फली के दाने, मूँगफली के तेल, रुई
चिनोले और भरणी आदि के बायदा के
बारे में क्या करते हैं वे लोग हमारे
यहाँ पोखंदर, राजकोट, जामनगर, माणा-
बंदर और धाराजी में अधिकारियों की
ओर से भैर धोरण बायदा बाजार चलता

[श्री धर्म सिंह भाई पटेल]

है। यह गैर-व्योरण वायदा बाजार उन प्रधिकारियों की तरफ से चलाया जाता है जिसमें उन को 500, 500 और हजार हजार रुपए मासिक पगार मिलता है। कुछ विकावे के लिए वे कहीं कहीं पर रेड कर देते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि भारत सरकार की ओर से क्यों न इस वायदा बाजार को अच्छी तरह से धोरण मर चलाया जाए। इस पर जो रोक लगा रखा है उस को हटाना चाहिए, और वायदा बाजार को मजबूरी देनी चाहिए। राजकोट-धाराप्री-माणिकन्दर-जामनगर—पांवंदर में जो यह बाजार-वायदा बन्द किया गया है, उसको फिर शुरू करने की जरूरत है। उसपर अपर चार्ज लगाया जाए, तो भारत सरकार को 10 करोड़ रुपए की आमदानी हो सकती है। हमारे सौराष्ट्र में आज से 12 साल पहले वायदा बाजार चल रहा था और उसमें देश को 50 लाख रुपए की आमदानी थी। तो मेरा सुझाव यह है कि वायदा बाजार आयोग को इस की जांच करनी चाहिए और मृगफली के दाने, तेल और दूसरी सब चीजों जैसे रुई, बिरंगे का वायदा बाजार फिर बे क्षुर करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि किसानों को हृषि के लिए कर्जा लेना पड़ता है। हमारा जो रिजर्व बैंक है, वह किसानों के लिए 7 प्रतिशत के हिसाब से राज्य सहकारी बैंकों को कर्जा देता है। राज्य सहकारी बैंकों को कर्जा देता है। जिस सहकारी बैंक ताल्लुका में सहकारी बैंक की गाँवों को कर्जा देता है और वे गाँव में जो सहकारी सोसाइटियां हैं उन्हें कर्जा देता है। इस तरह से किसानों को 12 से 15 पर सैन्ट पर सोसाइटी के कर्जा

मिलता है। हमारे रिजर्व बैंक और भारत सरकार की नीति तो बहुत अच्छी है कि वह 7 प्रतिशत पर किसानों को कर्जा देती है लेकिन इतनी ज्यादा ऐजेंसिय होने के कारण किसानों के हाथों में वह 15 प्रतिशत पर पहुंचता है। जब ऐसी बात है तो इस से किसान को क्या विशेष सुविधा दी गई है स्पेक्टिक 15 प्रतिशत पर तो व्यापारियों से भी उस को कर्जा मिल जाता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इतनी सारी ऐजेंसियों जो हैं, उन को निकाल देना चाहिए। किसान को राज्य सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक और अन्य राष्ट्रीय कृषि बैंकों से भी कर्जा लेना पड़ता है। ऐसा क्यों न किया जाय कि एक ही संस्था हो जो किसानों के लिए भारे कर्जे का प्रबंध कर दे और ज्यादा से ज्यादा 9 प्रतिशत पर किसानों को कर्जा मिले और सारे देश में एक ही तरीका होता चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में है।

तीसरी बात में यह कहना चाहूंगा कि मृगफली, सरसों और घरघरी जैसी हमारे देश में पांच प्रकार की तेलीयियां होती हैं और उन का उत्पादन लगभग 80 लाख टन होता है। इस देश में भारतीय चाय नियम है, भारतीय कायू नियम है, भारतीय रुई नियम है, भारतीय रबड़ नियम है और भारतीय काढ़ी नियम है। जब मृगफली और चाच तेलीयियों का 80 लाख टन का उत्पादन हमारे देश में होता है, तो व्यों न इसके लिए भी एक नियम की आवश्यकता की जाए जो इन बातों को देखे कि कैसे इन की अच्छी फसल कर सकते हैं और कैसे तेलीयियों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं तथा दूसरी जो इस की ज़रूरत है, उस को सुलझा सकते हैं।

बोधे दिन पहले मंत्री जी ने एक सुझाव देते के साथने रखा था कि बत बर्बं में साड़े बारह साल टन मूँग लसी खोल का नियंत किया और चालू साल में साड़े सात साल टन मूँगफली खोल का नियंत का लक्ष्य रखा है। इसमें से पांच साल टन मूँगफली खोल का नियंत हो गया है। पर्याप्त 6 महीने बाकि हैं, इस 6 महीने में मूँगफली की खली का क्या नियंत करें? माननीय मंत्री जी ने दो लाख टन मूँगफली की खली मूँग और कुकरे के लिए रिजर्व रखी है। इस मूँगफली की खली का बाजार में भाव 1700 रुपये टन है लेकिन मूँग और कुकरे के लिए 1200 रुपये टन का भाव रखा गया है। यह बात गलत है। कम दाम रखने से वे लोग अरीद कर बाजार में खुले रूप से कालाबाजार करते हैं। यह जो इन उद्घोरों के लिए भाव पर पावंदी लगायी है यह अच्छी बात नहीं है। माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में ठीक से सोच-विचार करें और मूँगफली की खली का नियंत पूरे छह महीने तक चालू रखें।

सभापति जी, कांग्रेस सरकार ने एक प्रणाली की है। वह है सभी जगह लाइसेंस, परमिट, कंट्रोल, कोटा नियम् बना दिया। हमारे राष्ट्रपिता नांदी जी ने कहा था कि "कम कायदे, कम कर, इसका नाम स्वराज्य" है। मैं एक दुकान में गया तो उस दुकान में लाइसेंस पत्र की बीस छवियाँ मैंने देखी। उस दुकान में भवान और कुटुम्ब की छवियाँ तो उतार कर रख दी गयी, लेकिन लाइसेंस पत्र की छवियाँ लगा दी गयीं। क्या हम भी ऐसा राज चलाना चाहते हैं? अनता पार्टी ने इसने शोषण पत्र में यह शोषण की है कि हम नांदी जी के रास्ते पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो हमें यह लाइसेंस परमिट कोटा राज बदल करता पड़ेगा। एक दुकान और उद्योग बाजे के पास एक महीने में 12-13 इंसेप्टर लोग प्राप्त हैं और लाइसेंस के जाते हैं। कभी कभी एक-एक दिन में दो-दो इंसेप्टर आते हैं। यह दुकानदार और उद्योगवाला

क्या व्यापार करे, क्या सरकार को भेजे? हम पांच साल में इतना कर सकते हैं कि जो एक दुकानदार या उद्योगवाला अपनी दुकान में कंट्रोल, लाइसेंस की 20 छवियाँ लगाता है, उनमें से 10-15 छवियाँ तो कम कर सकते हैं। भगवर हम ऐसा करेंगे तो गांधी जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। हमें गांधी के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।

हमारे सौराष्ट्र में राणाराव, पोरबंदर और मिक्का की सीमेंट फेनिक्सिंग है। गुजरात के लिए प्रमिल से जून तक का कोटा 307500 मीट्रिक टन सीमेंट प्रलोट करने का था लेकिन पर्याप्त तक—जून मास पूरा होने वाला है—गुजरात का 146807 मीट्रिक टन सीमेंट मिल पाया है। गुजरात को सीमेंट का पूरा कोटा मिलना चाहिए। हमारे सौराष्ट्र में मजदूरों और किसानों का कालेबाजार में सीमेंट लेकर काम चलाना पड़ता है।

मैंने जो ये दो-चार बातें कही हैं आपका है मंत्री जी इन पर विचार करें। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि (i) किसानों को सात प्रतिशत भ्याज की दर से कर्जा मिलना चाहिए। (ii) मूँगफली, मूँगफली के दाने, मूँगफली के तेल, वर्ष, बिनोले बीरह का खोरणसर बायदा बुरु करने की मूँगरी दी जाये। (iii) मूँगफली, सरतों, एरंडी जैसे तेलीवियाँ का भारतीय नियम बनाया जाए। (iv) किसानों के लिए एक ही सरकारी संस्था या बैंक में से 9 प्रतिशत भ्याज से कर्जा मिले। (v) मूँगफली के खोल के नियंत के लिए जो पावंदी या नियमन किया है वह हटा दिया जायें। मैं मंत्री जी से प्रावृत्ता करूँगा कि वे मेरे सुझावों पर विचार कर अपना करें।

की तेज प्रताप तिल (हमीरपुर). ३ सभापति महोदय, सहकारिता मंत्रालय के जो अनुदान की मार्गे पेश की गई है उनका समर्वेत

[श्री रेज प्रताप सिंह]

करने हुए मैं सदन का बहुत बड़ा समय लूँगा। मंत्री महोदय का ध्यान मैं सहकारिता आन्दोलन की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस आन्दोलन के साथ कांग्रेस सरकार द्वारा जो खिलवाड़ की गई है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। यह सौभाग्य की बात है कि इस मंत्रालय का भार ऐसे एक व्यक्ति के हाथ में है जिससे हमें बड़ी आशाएं हैं। मैंने नियी रूप से जो बातचीत उन से की है उससे मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि वह इस आन्दोलन को एक नया रूप देंगे। सहकारिता आन्दोलन का संसार भर में सर्वभान्य जो सिद्धांत है उसका वे आदर बरते हैं यह आभास मुझे उन में बातचीत करने के बाद मिला है।

कांग्रेस सरकार ने गत वर्षों में जो दस्तावेजी सहकारिता आन्दोलन के साथ की है वह नितांत निन्दनीय है। बड़े ध्यानपूर्वक मैंने जिदे साहब का भावण सुना है। वह सहकारिता मंत्रालय में स्टेट निन्दनर रहे हैं। उनके समझ भी ये सब बातें आती रही हैं। सहकारिता आन्दोलन में काम करने वाले नेता एवं कार्यकर्ता उनके ध्यान में ये बातें लाते रहे हैं लेकिन उन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं की है। सहकारिता आन्दोलन तभी सफलता के मायथ छल सकता है जब उसके सर्वभान्य सिद्धांतों पर आधारण किया जाए। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और वहीं की बात मैं सकता हूँ। सहकारिता आन्दोलन का यह सर्वभान्य सिद्धांत है कि उसके प्रबन्धक जो हैं, जो उसके संचालक हैं ये सभी चुने हुए होने चाहियें। लेकिन गत वर्षों में जितने भी उल्टफेर उस राष्ट्र के सहकारी कानूनों में किए गए वे निन्दनीय हैं। उनमें सहकारिकता के सिद्धांतों की अवहेलना की गई। आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि हमारे यहाँ पर चुने हुए संचालकों को अकारण भी हठाया जा सकता है किसी भी बड़ी से बड़ी संस्था में और सिफ़े इस कारण से हठाया जा सकता है कि किसी दूसरे में सरकारी

पूँजी उस संस्था में लगी हुई है। चूँकि कुछ धर्मों में सरकारी पूँजी उसमें लगी हुई है इस बास्ते दो तिहाई संचालक भी वहाँ सरकार नियुक्त कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। यह कारण बताना कि सहकारिता आन्दोलन में चूँकि सरकार ने पूँजी लगाई हुई है इसलिए उसको दखल देने का अधिकार प्राप्त है तो वहीं है। बहुत से देशों में मुख्य सहकारिता आन्दोलन का प्रध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कहीं भी ऐसा नहीं है कि वहाँ चुने हुए संचालकों को, अध्यक्षों को राष्ट्रीय या प्रान्तीय स्तर पर इस तरह से हठाया जा सकता हो। उनको बड़ा सम्मान वहाँ दिया जाता है। जब सरकार बजट बनाती है, सहकारिता आन्दोलन की प्रगति के लिए प्राविधिक करती है तो उन से वहाँ बराबर परामर्श दिया जाता है और एक सभ्मानजनक स्थान उनको दिया जाता है। यहाँ दुख की बात है कि बड़े से बड़े राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं तक से कभी काई परामर्श नहीं किया जाना है। जो भी कानून बने हैं

। जब भी काई मार्गे रखी जाती हैं हमारे देश में उनके बारे में किसी भी सं वा से कभी कोई परामर्श नहीं किया जाता है। मैं मंत्री जी में निवेदन करना कि जो आकांक्षाएं इस जनता सरकार से जनता की हैं उसमें एक आकांक्षा यह भी है कि जनता सरकार हारा कभी भी किसी भी सहकारी संस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। किसी प्रकार से, किसी बहाने से, चाहे कुछ भी अंग पूँजी हो हम उस के भैनेजैंट में संचालक बैडल में दो तिहाई या आधे से ज्यादा संचालक नियुक्त नहीं करेंगे और उन को आवादाना तरीके से काम करने दिया जाना चाहिये।

माननीय शिन्दे साहब कह रहे थे कि सहकारी संस्थाओं में बड़ा बराबर काम हुआ है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ देशिये वहीं बंदी नजर आती है, कोई भी विभाग है, कार्य को बहुत ही बड़ा देखा गया, हमारी कार्य प्रगतिं चाहे जैसी हो, कि हमारी बड़ी ही

निवारी स्थिति है हर क्षेत्र में। लेकिन उस को बढ़ा-चढ़ा कर कि सहकारी आन्दोलन में सारा प्रष्टाचार आया हुआ है, यह स्वयं एक निवारी बात है, और यह एक बहाना है। मैं आप को उदाहरण दे तामास संस्थाओं में, जहाँ प्रादेशिक स्तर की होंगी या छांटे स्तर की, हर जगह कांपेत सरकार ने ऐसे नोटों को नामजद किया है जिनका महकारी आन्दोलन में कोई बास्ता नहीं है। मेरे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जायेंगे कि जिनको कोई अकर जान नहीं है गहकारी आन्दोलन का, वे उसके निर्दोष संचालक बनाये गये हैं, बल्कि उपायक बना दिये गये हैं। उन में क्या आशा की जा सकती है? वह कभी सहकारी आन्दोलन को न तो समझते हैं और न कुछ हर समझते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बहुत सी संस्थाएँ हैं जैसे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन आफ इंडिया है जिस का मैं सालों उपचयन रहा है, लेकिन जायेत के जमाने में कभी कोई मान्यता या सीधी संस्थाओं को नहीं दी गई। मृजे, आशा है कि जो महकारिता का सिद्धान्त है कि किसी भी दल का अविन अगर चुन कर के आता है और उपायक या अधिक बनता है सहकारी संस्थाओं का तो उन पर कोई दबाव नहीं दिया जायेगा और उनको पूरा सम्मान दिया जायगा। यह है हमारी जनता पार्टी का दृष्टिकोण जो हमारे माननीय संघी जी घपनायें, और जो नियम बने हुए हैं प्रदेशों में, उनको इसी किंदान्त पर ढालेंगे।

एक बड़ी भारी इन्टरवेंशनल कोऑप-रेटिव देलायेंस नाम की संस्था है, उन की जानकारी में जब यह बात आयी कि हिन्दुस्तान के सहकारी आन्दोलन में कोप्रेस सरकार ने कितने ही सिद्धान्तों का हनत किया हुआ है तो उन्होंने एक पत्र लिखा था सरकार को और उस पर यहाँ से लिखा गया कि हमने छानबीन की है और कुछ मुश्किल दिये हैं। मृजे मालूम है अस्तित्व रूप से कि उस पर कोई अमल नहीं किया गया। मृजे जानकारी

नहीं है कि जो लिखा गया, और न इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि कम से कम जो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल को ऑपरेटिव यनियन आफ इंडिया नाम की संस्था है, और भी कांई संस्था जिसको भवी जी उचित नहीं, उन को बुला कर के जाहे ऐडवाइजरी कमेटी के रूप में या जाहे जिस स्पष्ट में हो, किसी प्रकार का एक माडल रिपोर्ट मार्ग देश में बनता चाहिये जिस में सहकारी मिदालों की रक्षा हो ताकि हम सही रूप से उस में कार्य कर सकें और प्रगति ला सकें। ऐसा कुछ करना चाहिये। उन को हमें मान्यता देनी चाहिये।

मैं सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि हर दो, चार वर्ष में हमारी सहकारी समितियों का स्वरूप बदल जाता है। कभी-कभी तो यह तय हुआ पिछले 10, 15 वर्ष पहले कि हर वर्ष में एक सहकारी समिति होती। 15, 20 हजार समितियां हमारे प्रदेश में बन गईं, और उन से ज्यादा भी बन गईं। उसके बाद फिर यह तय हुआ कि इस का आप्रिस ठीक से मेटेन नहीं होता है, इसका रेकार्ड ठीक से नहीं रखा जाता है इसलिये वायरिल यूनिट होनी चाहिये और जो कर के लार्ज साइज सोसायटी बना दी गई। कुछ दिनों उसका भी अनुभव किया गया, वह एक्सपरीमेट भी चलता रहा। अब विंगत 2, 3 वर्षों से ऐसा किया जा रहा है कि 3, 4, 5 गांवों को मिलाकर सोसायटी बना देते हैं, न वह लार्ज सोसायटी होती है, न स्माल, एक विचित्र बीच की स्थिति हो जाती है। हर 3, 4 साल में उकाका स्वरूप बदल देते हैं। कभी स्थिर नहीं रह पाती है। पता नहीं लगता कि कौनसा आदमी किस सोसायटी का सदस्य है। यह एककृत होनी चाहिये। बहुत गांवों को मिलाकर यदि समीत बनाई जाती है तो वह ठीक से को-ऑपरेटिव नहीं रह पाती। हर 4, 4 और 6, 6 गांव से डायरेक्टर उसके चुने जाते हैं, वे बैठते नहीं

(भी तेज प्रताप सिंह)

जो सचिव और सुपरवाइजर होते हैं, वह मनमानी करते हैं, कभी डाय-रेक्टर / इकट्ठे नहीं हो पाते हैं और सभापति बैरेट कोई नहीं देख पाता है। मैं नमस्ता हूँ तो गमी सहकारी नेताओं को बैठकर इन सब पहलुओं पर विचार करना चाहिये कि इसका क्या स्पष्ट हो। उसकी व्यवस्था को समझना चाहिये ताकि जो स्वल्प स्थिर किया या और कल्पना की भी मिश्रित इक नामी हो, जैसा माठे जो ने कहा है, वह मिश्रित इक नामी में हम समझते हैं कि जाहे पब्लिक बैक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, को-आपरेटिव बैक्टर बनवान बनता है। उसमें हम सभी समस्याओं से हन कर सकते हैं।

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में जहां नक लिखने का सम्बन्ध है, तो ऐस गणधर ने इसको बड़त महत्वपूर्ण स्थान दिया है, नेकिन किया उल्टा ही है। कार्यक्रम में उसको परिणत नहीं किया है। यह हमारी आर्थिक प्रगति का एक माध्यन होगा और सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यन बनेगा, ऐसा भी मानते हैं। नेकिन उसको बर्नाल, पुर्ण बनाया जाये, तभी यह हो सकता है। मैं नमस्ता हूँ कि जनना पार्टी की सरकार इसमें सफल होगी और महकारी आनंदालन को अपने कार्यकाम में बलवान् मूल्यमेंट बनाने में सफल होगी। जिसमें आर्थिक जगत और सामाजिक समस्याएं हल हो सकेंगी।

मैंने अखबारों में पढ़ा, मानवीय मंत्री जी ने इसकी योजना रखी है बीवर मैट्टर्स के लिये। जैसा बहा जाता है, यह सही है कि सुपर बाजार जो खूब ढूँढ़ा है, ये बड़े बड़े गहरों में हैं और बड़े बड़े लोगों के लिये हैं। वह तो खूब स्टर्ड-फर्मेंट कर लेते हैं, नेकिन माध्यारंग जनता, कामन मैंने उसमें सम्बन्ध नहीं जोड़ा गाता है। ऐसा ध्यान रखें कि जो 1000 रुपू करने वाले हैं, वह ऐसी जगहों पर खोलने चाहिये जहां छोटे लोग हों, जिसमें

सही कीमत पर उनको सामान बिल सुके। मैं इस दृष्टिकोण की प्रशंसा और सराहना करता हूँ।

मैं गोव-गोव में जब भी अपने लोक में पूछता हूँ तो मजदूर लोग दिलचारते हैं कि यह गल्ला हमको घोड़ा मिला है, एक किलो से भी कम मिला है। कृषि की दयनीय स्थिति है। मैंने मजदूरों से पूछा कि इसका क्या इलाज किया जाये। उन्होंने कहा कि पानी की अवस्था कर दीजिये, किसान पुट्ट लोगा, उसकी पैदावार अधिक होगी तो हमारी मजदूरी बढ़ेगी। जब किसान का प्रति एकड़ लकार इनाके में ढाई, तीन यन पैदा होता है, तो वह उसमें क्या मजदूरी है सकता है, उस बढ़ लाने के लिये मुश्किल है। तो ऐसा इंटर लीड है। अगर हम पूर्ण विभाग के लिये कहें कि साहब अपने डिस्ट्रिक्यूशन सिस्टम के लिये कुछ करें तो क्या वह जाहू करेंगे? कुछ नहीं कर सकते।

हम यह कहते हैं कि आपने 30 साल में कृषि को इस तरह से बढ़ावा दिया है कि उसकी कांटे नोटेबल तरकी नहीं हुई है। जैसे कह रहे थे कि एडीबल आयल की बड़ी कमी है उसकी कीमत 12, 13 रुपये हो गई। उसकी पैदावार नहीं बढ़ी। ऐसा कहता है कि जब मिश्रित का साधन 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा तो सरकार कहा से आयेगी और कैसे एडीबल आयल की बढ़ि होगी। तो यह कोई जाहू कर सकेंगे, ऐसा संभव नहीं है।

मैंने इस बात पर बहुत विचार किया है कि सरकार की दो तरह की कीमत रखती है। नेताओं, बड़े लोगों, अपरेटर्स और गहरों में रहने वाले सफेदपोशों की कीमती 2 रुपये किलो पर विलती है। जहां एक प्राचीन लोगों का सम्बन्ध है, कावेस सरकार की ओर से मह कोलिंग की गई थी जहां लालूरी भी न बिल पाये। गोव में एक लालूरी

साल तक यह की जाय पड़ी। जो छः, वह दोरे भीती महीने में मिलती है, उसमें से आधी तहसील हैब्बदाटर में ही विक जाती है, और आदीय लोगों को खुले बाजार में 4, 5 लप्पे किलो पर खरीदनी पड़ती है। इस अवस्था को अविनष्ट बत्तम किया जाये। जाहे जो भी कीमत किसके की जाये, लेकिन ईश्वर के नाम पर, जनता सरकार के नाम पर, इस को बत्तम कर दिया जाये। हमारे देश में इस प्रकार दो तरह की कीमत नहीं होती जाहिए। यह बदनामी का कारण है।

विस तरह से जब तक इकानोमी को बीर्डलाइज नहीं किया जायेगा, तब तक अटाचार बत्तम नहीं हो सकता है, उसी तरह जब तक हम जासन प्रबन्ध में शक्ति को विकेन्द्रित नहीं करेंगे, तब तक अटाचार बत्तम नहीं होगा।

यह बड़ा जल्दी में बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि जायद इसी कारण इसमें सहकारिता के लिए बहुत कम रुपया रखा गया है। अब इसको की फैक्टरी जल्दी इनस्टाल हो सके, तो उससे हमारे क्षेत्र में बहुत तरफ़ी होगी। एन० सी० ढी० सी० जैसी जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, उन में कोई कोपापुरेटर जायद नामिनेट्ड हो। अबल हो नामीनेशन नहीं होना जाहिए, लेकिन अबर नामीनेशन करना ही है, तो ऐसे लोगों को बेवर्टेन नियुक्त किया जाये जो सहकारी आवोलन में काम कर सके हैं, जो प्रापेट हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तभी सहकारी आवोलन आगे बढ़ सकेगा। सहकारी आवोलन सहकारिता के सभ्ये सिद्धांतों पर ही चलना जाहिए; उसके बाद इसारी तरफ़ी नहीं हो सकती है। मूले जाऊ है कि मंत्री महोदय के नेतृत्व में सहकारी आवोलन तिरंतर प्रशंसित होगा। यह अवसर है कि यह इस के लिए सहकारी आवोलन के कार्यकरीयों

से परामर्श करते रहें, जाहे वे किसी भी पोलारिटेक यार्डी के हों।

इन जबदों के साथ मैं हम यांगों का समर्थन करता हूँ और आजा करता हूँ कि हमारी सरकार के अन्तर्गत हमारे ज्ञेय में बड़ी तरफ़ी होती है।

SHRI CHITTA BASU (Barasat):
Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants now under discussion, subject, of course, to certain comments which I would like to make in this connection. I venture to make these comments because I have got great expectations from the hon. Minister as, I believe, he is a person of commitment towards socialist directions of our economy. Naturally I expect from him that he would not only be as committed as he was earlier but also pursue the path without any wavering. I would also urge on him to see whether it is possible to reverse certain processes which would be required for taking the country towards the socialist directions of our economy. I particularly mention two vital aspects of our economy which are under his direct control and supervision, namely, jute and textiles. These are the two important and vital arteries of our national economy.

Firstly I would like to mention certain aspects of the jute industry. I think, the hon. Minister will agree with me that the jute industry is today in the throes of a deep crisis. I do not like to join issue with him, but, I think, he will agree with me that the basic reason for this deepening crisis in the jute industry is primarily mismanagement, fraud and diversion of superprofits by the captains of the jute industry. If he does not agree, I have nothing to quarrel with him, but his predecessor, belonging to the Congress Party, Prof. D.P. Chattopadhyay had officially agreed that the basic reason for the crisis in jute industry was due to the fault of the captains of the industry. My question at this time is : what are the specific proposals of the Government of India to save the industry from the crisis?

Here, the question of the availability and prices of the raw jute occupies a very important position in the whole jute economy. Since the time at my disposal is very short, I would only say that the availability and the prices of the raw jute constitute the basis of the problem. That being the case, the jute growers of West Bengal, Assam, Orissa and Bihar, have been denied their legitimate due. If I

[Shri Chittu Basu]

am permitted to quote certain non-official agencies, I may point out that during the last thirty years of Congress rule, the poor agriculturists of West Bengal, Bihar, Orissa and Assam have been deprived of more than Rs. twenty-five thousands or this much amount has been forcibly snatched away from them. Had this amount been there in the States concerned, they would not have been as they are today; they would not have been under developed or the regional imbalance would not have been there, as we say now-a-days.

As you know, the price of raw jute was fixed at Rs. 135 per quintal by the APC last year. Fortunately or unfortunately, I do not know, why the prices of the raw jute for the current season has not yet been fixed. Rs. 135 is absolutely unremunerative, and I would say that it should not be less than Rs. 200 per quintal. May I ask the hon. Minister whether he has taken the trouble of going into the cost structure of the production of jute? Would he now take the trouble of going into the production cost of Jute in West Bengal, Assam, Bihar and Orissa and find out how and why the price has been fixed at Rs. 135 per quintal?

I would like to say from my experience of West Bengal that though the price of raw jute was fixed at Rs. 135 per quintal, the jute growers were not getting it. Today, as we learn from the newspaper reports, the jute mill-owners of West Bengal are thinking in terms of declaring closures or layoffs in their mills, because according to them there is less availability or no availability of raw jute. They are purchasing raw jute from the market at Rs. 200 or 235 per quintal, while the jute growers were not getting even Rs. 135 per quintal. May I request the hon. Minister that he should review the entire position and break the monopoly of purchase of raw jute by the jute mill-owners. The Jute Corporation of India has proved ineffective in the matter of ensuring fair price to the jute growers or in respect of supplying adequate raw material to the jute mills. Out of a total production of 80 lakhs bales, as far as my information goes and the government statistics go the Jute Corporation of India could purchase only 6-7 lakhs bales. Almost an overwhelming quantity of raw jute was available in the free market and the middlemen and the mill owners purchased this raw jute at a relatively less price. In this respect, I only want to mention that the raw jute price has not increased in comparison with the price of the finished goods of jute. As far as my statistics go, it is amply proved that while the prices of finished raw jute

goods in the international market increased by 190 : 290 per cent, the increase in the raw jute price has been not commensurate. In this connection I would like to compare the price of raw jute with raw cotton. As far as my information goes—I have no quarrel for cotton getting a remunerative price thanks to the Maharashtra Government which has made a great attempt to ensure fair price by taking up a programme of monopoly purchase of raw cotton, the cotton growers got remunerative price and the price of raw cotton has increased by 100%. But earlier it was not so and it increased by dribbles. But in the case of jute, the price remains to be stagnant and there is no mechanism to see that along with the increase in the prices of finished goods of jute, the raw jute price also goes up. There is no such mechanism. I feel in all fairness the government should reconsider the entire issue and fix a remunerative price for raw jute. In this connection, may I draw the attention of the hon. Minister to the report of a committee headed by Mr. Nirmal Chandra Sen set up by the United Front Ministry of West Bengal. That committee went into the entire matter in all its aspects right from the point of jute grower to the point of price of finished goods. The committee made certain recommendations. May I request the hon. Minister to kindly go through that report which will help him to understand the whole problem of the jute industry in West Bengal better and do justice for the jute growers of these 4 or 5 States. I do not want to dilate much on this subject, but I would very much like to mention about the jute industry also.

Export has been on the increase so far as my figures go. The export has increased and the income out of exports has also increased. The income from export of finished jute goods has gone up from Rs. 2050 per tonne in 1965-66 to Rs. 4300 in 1975-76. Whereas the price of finished jute goods has almost doubled, the price of raw jute has not registered any remarkable increase. I think the Minister should look into the matter and take steps to see that the jute growers of the Eastern States get a remunerative price and also expand the network of purchasing centres of the Jute Corporation of India so that the jute growers can take their produce to the Jute Corporation and sell it to them.

About textile industry, I have only one thing to say. About the textile industry, there should be a rational textile policy. In a state of resorting to adhocracy, in a state of taking certain measures in a peaceful manner, there should be a national and also rational approach. In the scheme of things, the question of the price of the raw cotton, question of the wages

for the workers, the question for the modernisation of the textile industry, the question of the problems of the hand-loom weavers and the elimination of conflict between the various segments of cotton textile industry are to be the main ingredients of development in national as well as rational textile policy of our country. In this connection I would say if the Governments' intervention is relaxed I think that kind of policy cannot be evolved. I would again say there are basis for nationalisation of these industries. Unless you nationalise jute industry, you will be waiting for the appetite of the captains of the industry. Therefore, I say instead of offering concessions after concessions, I have got a long list of concessions, instead of waiting for the appetite of the tycoons of the industry, Government should consider the case for the nationalisation of these two industries. I think Government should not fight shy of it. I hope the hon. Minister should take a note of it and in the interest of the two basic industries of the country rid them from oft-repeated crisis. Unless that is done, I think the national economy cannot be put on a sound footing.

श्री मोतीभाई आर० चौधरी (बनास-काठा) : माननीय सभापति जी, माननीय भंडी जी जो ये मांगे लेकर इम हाउस में आए हैं, उन मांगों का मैं समर्थन करता हूँ।

मैं दो तीन बातों पर चास तोर पर व्यापार आकर्षित करने के लिए बढ़ा हुआ हूँ। पहली बात तो मैं निर्यात नीति के बारे में कहना चाहता हूँ और वह यह है कि इस देश में जिस चीज़ की कमी है, उस के निर्यात को कम किया जाए। खास कर इस देश में बेरोजगारी का सवाल बहुत बड़ा सवाल है और गांवों में काम देने के लिए पशुपालन का ध्यान बेरोजगारी को कम करने की दिशा में बहुत उत्कृष्ट माना गया है। पशुओं के लिए जो जली होती है, उस का निर्यात करने से एक साल में दो से तीन गुना इसके दाम बढ़ गये हैं। इस बारे में इस सवाल में बार बार माननीय भंडी जी का व्यापार दिलाया गया है कि ऐसी चीजों का निर्यात बद्द होना अस्थन्त आवश्यक है। दूसरी उच्चाग के लिए यह अस्थन्त आवश्यक है कि इस का निर्यात बद्द किया जाए क्योंकि इस देश में सबसे

ज्यादा पशु हम रखते हैं लेकिन दूध कम पैदा होता है। अधिक दूध के लिए पशुओं को अच्छा खाना मिलना चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि पशु आहार की जो चीज़ें हैं, उन को बाहर न भेजा जाए। मैं आशा करता हूँ कि माननीय भंडी जी इस पर पूरा ध्यान देंगे और पूरा-पूरा विचार करके ऐसी चीजों के निर्यात को बन्द कर देंगे।

ऐसे ही ग्रीष्मों के लिए प्याज अस्थन्त आवश्यक चीज़ है। अब इस का निर्यात कम किया गया है लेकिन ऐसी चीजों का निर्यात न हो, इस का व्यापार रखा जाए। आनू के दाम भी बहुत बढ़ गये हैं जिस की वजह से एक सामान्य आदमी इस को नहीं खा सकता। इस का निर्यात भी बद्द होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : केला भी।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : केला भी है। मैं सभी चीजों के बारे में कह रहा हूँ। खाने की चीज़ें बाहर नहीं भेजी जानी चाहिए क्योंकि इस से यहां पर दाम बढ़ जाते हैं।

इसी बात यह है कि रुई को बाहर से माना बद्द करना चाहिए। हमारे देश में लम्ब तारी रुई इतनी पैदा हो सकती है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सक। लेकिन हमारी नीति ऐसी रुई है कि हम किसानों को मदद देने के बावजूद बाहर से रुई भेजते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे किसानों को सरकार ज्यादा से ज्यादा मदद दे जिससे ज्यादा से ज्यादा कपास बे पैदा करें। कपास बोने के मौसम के पहले सरकार रुई बाहर से नहीं मानवेशी। ऐसी नीति जारी करदे जिससे किसान ज्यादा एकड़ में कपास की खेती करें। सरकार रुई का आवात बिल्कुल बद्द कर दे। आशा है सरकार इसके लिए कुछ आवश्यक कदम उठावेगी।

[मी भोतीश्वारी आर० चंघरी]

मानवीय मंत्री जी ने बजट में सहकारी चीनी मिलों के बारे में घोषणात की रकम बढ़ाई है। इसे बीस करोड़ से बढ़ा कर सताईस करोड़ कर दिया गया है। लेकिन शूगर मिलों की मांग तो ब्रावर बड़ी रही और हमारे गुजरात में तो इसके लिए सरकार की ओर से पूरा मैसा न होने की वजह से यह काम आगे नहीं चल पा रहा है। चार सहकारी शूगर कारखानों के लिए तो सरकार से मधुरी भी नहीं मिली है। मैं आशा करता हूं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा सहकारी चीनी कारखाने बोलेगी। मैं चाहता हूं कि सहकारी चीनी कारखाने काफी खुलें। राष्ट्रीयकरण के बजाय सहकारी चीनी कारखाने बनाये जाएं। अब अधिक सहकारी चीनी कारखाने बनाये तो इससे राष्ट्रीयकरण का सबल भी हल हो जाएगा और गन्ने की खेती भी बढ़ेगी। इससे देश में ज्यादा काम मिलेगा। देहातों में लोगों का काम मिलेगा। सरकारी (राष्ट्रीयकरण किय) चीनी मिलों के बजाय सहकारी चीनी कारखानों का ज्यादा से ज्यादा इंतजाम किया जाए। यह अच्छा रहेगा।

बहुत सी प्राइवेट कंपनी मिलें पुर्व बाजार होने की वजह से खराब पड़ी हैं। ये मिलें बड़ी जाती हैं और सरकार के लिए इन सिक मिलों का एक ऐचोदा सबल पैदा हो गया है। इससे देश में बेरोजगारी का सबल भी उठ बढ़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में भेरा कहना यह है कि अब तो बिजली गांव-गांव तक पहुंच गई है। स्थिति मिलें यंत्र के बजाय गांव-गांव में बंबर चबूं चलें। बंबर चबूं में बिजली लगा दी जायें और कलाई का काम किया जाए। इससे देश में बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी और यह मिलों से सरकार के सामने जो समस्या बढ़ी होती है वह भी नहीं होगी। (सलिए मैं अनुरोध करूंगा कि कलाई मिलों के बजाय शम्बर चबूं में बिजली लगा कर उस से कलाई

का काम लिया जाए। इसके लिए कोई योजना बननी चाहिये और सरकार को उसे बताना चाहिए। जो ऐसा सरकार इन कलाई मिलों को देती है उसका उपयोग इस योजना में किया जाए।

काण्डला में फटिलाइजर का कारबाना है। फास्फोरिक एसिड की जांतपी रही है उसको दूर करने के लिए फास्फोरिक एसिड का प्लांट काण्डला में रखने के बारे में सोचा गया है। इसके लिए साठ करोड़ रुपये की जरूरत है। (स बजट में कलाई रुपये का बाबतान किया गया है। यह मास्मा सरकार के अभी भी विचाराधीन है। मैं अनुरोध करता हूं कि बाहर में करोड़ों रुपये की बिदेसी मुद्रा बच्चे करके जो खाद हम मंगाते हैं, उसे न मंगा कर देश में ही वह रकम बच्चे की जाए और खाद कारबाना बोला जाये। फास्फोरिक एसिड का प्लांट जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिये और इसके लिए काफी ऐसा रखा जाना चाहिये। जितनी जल्दी इस को स्थापित कर दिया जाता है उतना ही ज्यादा देश को साम होगा, हमारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा और विदेसी मुद्रा भी बहत होगी। और भी ज्यादा रकम का प्रावधान उसके लिए इस बजट में किया जाना चाहिये।

हैंडलूम के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। मेरा कहना यह है कि बेरोजगारी और बेरोजगारी को दूर करने का यही एक माझ रस्ता है।

हैंडलूम को प्राप्तिकरण दी जानी चाहिये, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिये। तीस साल आजाद हुए हमारे देश को हो गए हैं लेकिन काम मांगने वालों को हृष्ट काम नहीं दे सके हैं, इस से ज्यादा सज्जा की बात कीई दूसरी नहीं हो सकती है। इस काम में लेजी लाई जानी चाहिये ताकि लोगों को श्रीकार जिल सके। इसके बादाका बाहर पांच लाठे और चारा नहीं है। हाथ से चलने वाले उद्योग बंधों पर हमें ज्यादा के ज्यादा और

देना होगा और इनको बढ़ाना होगा। घोटी साझी बनाने का काम इनके लिए रिजर्व कर दिया जाना चाहिये। एक मात्र यही रास्ता है बेकारी को दूर करने का। हृषकरणों पर ज्यादा जोर दिया जाए, उनके लिए ज्यादा रकम का प्रावधान किया जाए। मैं आशा करता हूँ कि इस ओर आप ध्वन्य ध्वनि देंगे।

नैशनल लेबल की जो सहकारी भवस्थायें देन में काम कर रही है, उनकी डेवल मैट में बढ़ावा मिलना चाहिये। एक नैशनल लेबल की सोसाइटी का किसी मैं जानता हूँ एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो नए रखे गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। जो काफिल और गैर रीति कर्मचारी थे उनको उन्होंने निकाल दिया है। उद्योग मंत्रालय द्वारा यदि उनको गतल डॉग से यह निकाले गये कर्मचारी संसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बातों से आपको सावधान रहना चाहिये। आपको देखना चाहिये कि जो बेहुलीयाद जिकायतें हैं वे न होने पाएं। और अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों की कदर की बजाय सजा न हो। यह गैर रीति जो हुई है। यह नैशनल सोसाइटी में तीन साल से ग्राहित न हो गया है। इससे गैर रीतियां करने वालों को उत्तेजना मिलती है। ऐसा न हो पाये इसलिये समय पर ग्राहित हो जाने का इन्तजाम होना चाहिये।

नैशनल सोसाइटीज का ग्राहित भी समय पर नहीं होता है। इस बजह सभी गैर कानूनी बातों को, गतिविधियों को, खर्चों को बढ़ावा मिलता है। हर साल उनका समय समय पर ग्राहित होना चाहिये। इसके बारे में भी आप देखें, इन खर्चों के साथ मैं इन ग्रन्तदाताओं की मार्पों का समर्थन करता हूँ।

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore) : Mr. Chairman, Sir

SHRI VAYALAR RAVI: She is going to have the second chance.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: I won't have any chance if the hon. Members interrupt me in this fashion.

MR. CHAIRMAN: Sir, the first thing that I would like to refer here is this. This particular ministry is a sort of a package ministry. I would like to point out to the Minister that he liberalises the import policy which he is introducing or which has been introduced, which is going to hit hard our indigenous industries, particularly, in the small-scale sector about which he is speaking day in and day out in various places from Poona to Delhi.

Encouraging the import policy is exactly going to hit this very vital sector of our country's economy because, if we are to achieve some measure of improving the standard of living and also of improving the general economy in the rural areas, then it is extremely important that some help and more attention should be given to the small scale industry.

We have 111 items of import being liberalised and 28 more items of machine tools have been put in the free licence. In addition to that, this emphasis on import liberalisation which is given in the present Janta Budget makes one worried because one feels that in the name of import all kinds of things will be brought into it. The foreign exchange reserves of Rs. 3,200 crores which we have will be squandered away.

Sir, the present Commerce Minister is a trusting minister. He wants to extend his trust to every section of humanity in our country, that is importers, traders, hoarders, black-marketeers, smugglers and the consumers. He trusts all of them. He trusts the consumers also and in turn wants the consumers to extend their trust to him.

12 Hrs.

Sir, my fear is that to those whom he is giving import licences will actually betray his trust in the same way those who got the import licences for edible oil, betrayed the trust which the Government placed on them. We know Sir, when the price of edible oil changed in the foreign countries, then many of the import licences that were given to the importers for edible oil were not used for importing edible oil but on the other hand certain mal-practices crept in. You will find a number of un-named accounts abroad as a result of the trust placed in those who said that they would import edible oil.

MR. CHAIRMAN: Mrs. Parvathi Krishnan, as you will take some more time you may continue your speech on Monday.

12.02 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, June 27, 1977/Ashad 6, 1899 (Saka).